R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-25

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष:22 । अंक:11
01 से 15 मार्च 2024
पृष्ठ:48
मूल्य:25 रु.

क्या कांग्रेस लौट पाएगी सत्ता में ?

सत्ता की आदी रही कांग्रेस नहीं निभा पा रही विपक्ष की भूमिका

आपातकाल लगाने वाली पार्टी अब सरकारी सख्ती से घबरा रही

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | 2 माह में आईएएस के रिकॉर्ड तबादले

मप्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की, जबकि 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल बना और 30 दिसंबर को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। मुख्यमंत्री बने मोहन यादव को दो महीने...

राजपथ

10-11 | अबकी बार कांग्रेस...

डॉ. मोहन यादव जब से मप्र के मुख्यमंत्री बने हैं वे लगातार सक्रिय हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बिना रूके बैठकें, दौरें और सभाएं कर रहे हैं। मोदी-शाह की ही तरह सत्ता और संगठन की यह जोड़ी...

योजना

15 | अमूल की तरह सांची बनेगा...

गुजरात के अमूल की तर्ज पर मप्र के सांची का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सांची डेयरी प्लांटों को भी अपग्रेड किया जाएगा और प्रदेश में होने वाले दुग्ध उत्पादन और दूध से तैयार होने वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

विवाद

18 | पीएम आवास बना फांस

चार साल से होम लोन की किस्त और मकान का किराया दोनों भर रहा हूं। वेतन का 70 फीसदी हिस्सा केवल इसी में जा रहा है। बच्चों की छोटी-छोटी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाता तो शर्मिंदा महसूस करता हूं। मप्र टूरिज्म विभाग में काम करने वाले राहुल तल्खी ने इस तरह अपना दर्द...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की धुरी रही कांग्रेस, आजादी के बाद अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी। एक वक्त था जब इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को केंद्र की सत्ता में पूरे 25 सालों तक कोई सीधी टक्कर देने वाला भी नहीं था। आज आलम ये है कि केवल 3 राज्यों की सत्ता में कांग्रेस की मौजूदगी है। वहीं भाजपा का परचम हर तरफ लहरा रहा है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि रोजाना किसी न किसी राज्य में पार्टी के नेता हाथ का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

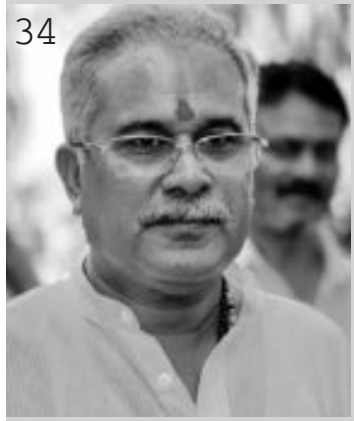

राजनीति

30-31 | राहुल कांग्रेस बनाम...

सत्ता की इस अंधी चाह में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों वाली भाजपा कहीं खो गई है। कांग्रेस मुक्त भारत की जगह पर भाजपा मुक्त भारत हो गया है। जनसंघ के परिवारों से निकले भाजपा के कार्यकर्ता डॉ. मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय...

महाराष्ट्र

35 | विचारधारा नहीं सत्ता ही लक्ष्य

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस से 50 साल से भी पुराना रिश्ता था। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, मिलिंद देवड़ा खुद भी कांग्रेस के सांसद रहे थे। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री...

बिहार

38 | बिहार में महिला वोटर किसके...

जैसे-जैसे लोकसभा का चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक समीकरणों और एजंडों पर मंथन भी तेजी पकड़ रहा है। बिहार में नीतीश के एनडीए में आने के बाद भाजपा के लिए नफे और नुकसान की भी चर्चा हो रही है। कई लोगों का मानना है...

6 -7 अंदर की बात
39 पड़ोस
40 विदेश
42 अध्यात्म
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

सिस्टम की नाकामी या लापरवाही...?

शा*यर फहमी बदायूनी का एक शेर है*

पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा
कितना आसान था इलाज मेरा

लेकिन, 12 हजार करोड़ से अधिक के बजट वाले मप्र के स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में कोई भाग्यवान ही होता है, जिसे पूरी तरह तिमारदारी मिल पाती है। सरकार निजी अस्पतालों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के भले ही बड़े-बड़े दावे करे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सिस्टम की नाकामी और लापरवाही मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करती रहती है। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों की बात कौन करे, राजधानी भोपाल में ही सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर निशांत वरवड़े के ड्राइवर की गर्भवती पत्नी की मौत हो गई। वह राजधानी के जेपी अस्पताल में भर्ती थीं, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। जेपी अस्पताल से हमीदिया जाने के लिए पहले तो एंबुलेंस नहीं मिली, फिर एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिली। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ गई और हमीदिया में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आमतौर पर हर मैटरनल डेथ का रिव्यू होता है, पर यह मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए एनएचएम की एमडी प्रियंका दास ने जांच कमेटी बनाई। सवाल उठता है कि कमेटी बनाने से क्या दिवंगत महिला जिंदा हो जाएगी। यह मामला हाईप्रोफाइल था, इसलिए कमेटी बना दी गई, वरना प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त सुविधा न होने और लापरवाही के कारण रोजाना न जाने कितनी मौतें हो जाती हैं। दरअसल, सरकार का सबसे अधिक फोकस अस्पतालों की ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बनाने पर है। अस्पतालों में सुविधाओं और मशीनों के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उनका फायदा मरीजों को नहीं मिल पाता है। इसकी वजह यह है कि न तो चिकित्सक हैं और न ही विशेषज्ञ। प्रदेश में 77 हजार डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि यहां सिर्फ 22 हजार डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। प्रदेश में 3400 लोगों पर एक डॉक्टर ही मौजूद है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में जिस रफ्तार से डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, उससे अधिक रफ्तार से बेहतर की तलाश में बाहर जा रहे हैं। ऐसे में डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड को पाने में राज्य को पांच से दस साल से अधिक का इंतजार करना पड़ेगा। मालूम हो कि डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार प्रति एक हजार व्यक्ति पर कम से कम एक चिकित्सक जरूर होना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को आंके तो स्थिति हद से ज्यादा चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों के 3278 पदों में से सिर्फ 1029 पर कार्यरत हैं। इनमें से भी इस साल 91 विशेषज्ञ रिटायर हो जाएंगे। वहीं चिकित्सा अधिकारियों के 1677 पद खाली हैं। दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा विभाग में 2890 पदों में से 863 पद खाली हैं। बीते सालों में प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन डॉक्टरों का प्रदेश छोड़ना ही सबसे बड़ी समस्या है। प्रदेश में हर साल तीन हजार के आसपास डॉक्टर हैं, लेकिन इनमें से हर साल 800 से ज्यादा प्रदेश छोड़ देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? सरकार ने शायद ही कभी इसको जानने की कोशिश की है। राजधानी के हमीदिया अस्पताल की ऊंची इमारत देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। लेकिन यहां मरीजों को न तो समय पर इलाज मिल पाता है और न ही जांच हो पाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार बड़ी-बड़ी इमारतें बनाकर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का कब तक दावा करती रहेगी।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 11, पृष्ठ-48, 1 से 15 मार्च, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

चीतों की चिंता

मप्र के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, उनमें अब सिर्फ 17 जीवित बचे हैं और 10 चीतों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन चीतों को भारत का मौसम रास नहीं आ रहा है या फिर कोई दूसरी वजह है, ये अब तक क्लीयर नहीं हो पाया है। यह चिंता का विषय है।

● **अरविंद मिश्रा,** जबलपुर (म.प्र.)

किसानों को मिलेगी राहत

हर साल किसानों की फसलें विभिन्न कारणों से खराब हो रही हैं। ऐसे में वह अपने खेतों में कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, जिसकी कोई प्रमाणिकता न हो। इसको देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने नैनो यूरिया को भरोसेमंद बनाने के लिए उस पर शोध शुरू कर दिया है।

● **अखिल तंवर,** भोपाल (म.प्र.)

सड़कों की मरम्मत

मप्र में सड़क–पुल के निर्माण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार दक्षिण–पश्चिम के कुछ राज्यों की तकनीक अपनाएगी। इससे प्रदेश की सड़कों को राहत मिलेगी। मप्र में हर साल हजारों किमी सड़कें थोड़ी सी बारिश और भारी वाहनों के दबाव से खराब हो जाती हैं।

● **संजय कुशवाह,** इंदौर (म.प्र.)

संकट में कांग्रेस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा न किसी तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जगा रही है और न जनता में उनके नेतृत्व को लेकर कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब कांग्रेस के समर्थक भी इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जिस तरह कांग्रेस खराब तैयारी के साथ लड़खड़ाती हुई चुनावी राजनीति में उतरती है और गुटीय झगड़ों को काबू में नहीं रख पाती और सबसे अहम यह कि वह जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाती, उससे उसका अपना कैडर ही बुझा हुआ है। राहुल की न्याय यात्रा से मिली गतिशीलता को कायम रखने के लिए कांग्रेस के पास ऐसा संगठन ही नहीं बचा है कि वह उसे चुनाव के लिए तैयार मशीन बना सके और भाजपा को चुनौती दे सके।

● **नवीन चौरसिया,** ग्वालियर (म.प्र.)

भाजपा बिठा रही सीटों का गणित

भाजपा 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार उसके सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई है। 2019 में भाजपा का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना (अब उद्धव गुट), तमिलनाडु में एआईएडीएमके और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ अलायंस था। हालांकि, महाराष्ट्र में शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजित गुट भाजपा के साथ आ गया है। महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।

● **राकेश्वर पांडे,** नई दिल्ली

एक्शन में मोहन सरकार

मप्र की मोहन यादव सरकार लगातार इनोवेशन कर रही है। राजधानी भोपाल से सरकार चलाने की जगह मुख्यमंत्री मोहन यादव संभागीय लेवल पर भी मॉनीटरिंग की व्यवस्था बना चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल को रामराज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम टैगलाइन दिया है। मोहन सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं, जिन पर खरा उतरने का सरकार प्रयास कर रही है।

● **प्रियांशी मेहतो,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

असमंजस में अकाली-भाजपा गठबंधन

पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी आम चुनाव से पहले भाजपा पंजाब में खुद को मजबूत करने के लिए शिरोमणि अकाली दल (बादल) के साथ गठजोड़ कर सकती है। यहां तक कहा जा रहा था कि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का श्री अकाल तख्त साहिब परिसर में बेअदबी मामलों में पंथ से माफी मांगने से पंजाब के राजनीति समीकरण बदलने वाले हैं। लेकिन अब पंजाब किसान यूनियनों की ओर से दिल्ली चलो आंदोलन से भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसानों और भाजपा शासित केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही है। भाजपा और शिअद दोनों ही इस पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिअद की एक बार फिर से एनडीए में वापसी होगी या नहीं, यह काफी हद तक इस बातचीत पर निर्भर करेगा। सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाला शिरोमणि अकाली दल (बादल) में विलय का ऐलान कर सकता है। अगर इन दोनों दलों का विलय हुआ तो फिर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होने की पूरी संभावना बन जाएगी। सुखदेव सिंह ढींडसा का इस समय भाजपा के साथ गठबंधन है। विलय होने के बाद वही शिअद और भाजपा के गठबंधन के सूत्रधार बनेंगे।

प्रियंका के लिए पिच तैयार!

आगामी आम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन में जुट गई हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों पर है कि एक तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए राजनीतिक पिच तैयार हो गई है। कहा जा रहा है कि प्रियंका को कांग्रेस रायबरेली से अपना उम्मीदवार बना सकती है। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का लंबे समय से सियासी नाता रहा है। 2014 में अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस के हिस्से आई, लेकिन वर्ष 2019 में सिर्फ रायबरेली पर ही कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रख पाई। अब सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने की संभावना है। वह पिछले चुनाव में भी सक्रिय रही थीं। सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में प्रियंका लगातार रायबरेली का दौरा करती रही हैं। ऐसे में इस सीट पर प्रियंका गांधी की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। यह सीट को कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहां से दो बार फिरोज गांधी, दो बार इंदिरा गांधी और चार बार से सोनिया गांधी सांसद रही हैं। 2014 के मोदी लहर में भी कांग्रेस इस सीट को जीतने में सफल रही। ऐसे में प्रियंका के लिए इसे मुफीद माना जा रहा है।

महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा खेला

देश में चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र में बड़े सियासी खेल की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के 12 विधायकों का पार्टी संग मोहभंग हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस के एक बयान के बाद इस्तीफे की झड़ी लगने की कयासबाजी होने लगी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व महाराष्ट्र में भाजपा ने एक बार फिर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के साथ उनके वफादार अमर राजुरकर ने भी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस के कई विधायकों का इस्तीफा भी तैयार बताया जा रहा है। इस बीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगे-आगे देखो होता है क्या वाला बयान सुर्खियों में है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के इस्तीफे से न केवल कांग्रेस, बल्कि महाविकास आघाड़ी (एमवीए) को भी तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की टूट का मतलब महाविकास आघाड़ी का अंत माना जा रहा है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पहले ही दो फाड़ हो चुकी है। सूबे में कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जिसमें बगावत नहीं हुई थी लेकिन अब कांग्रेस भी सदमे में है।

भाजपा में लैंड करेंगे पायलट ?

देश में करीब तीन माह बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे भाजपा में लैंड कर सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सचिन पायलट भाजपा में जाएंगे या नहीं, इसका जवाब वे खुद ही दे सकते हैं, लेकिन हाल ही में जिस प्रकार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की जमकर तारीफ की है। गौरतलब है कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते हुए सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पीवी नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों एवं दूरदर्शिता ने देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती, दिशा एवं गति प्रदान की। पायलट के इस ट्वीट के बाद कहा जा रहा है कि वे जल्द ही कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं।

फिर साथ टीडीपी-भाजपा

आम चुनाव 2024 की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी जोड़-घटाव का दौर भी जोर पकड़ता दिख रहा है। एक ओर जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए में रोज नए साझेदारों के जुड़ने की खबरें आ रही हैं। राजनीतिक हलकों में हवा है कि आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकती है। पार्टी सूत्रों की मानें तो टीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात लगभग पूरी हो गई है और जल्द ही गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 10 सीटें मांगी हैं। हालांकि टीडीपी पहले ही अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन कर चुकी है।

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक दोस्ती काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि माइक-1 और माइक-3 की दोस्ती काफी गहरी हो गई है। कई बार इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन इन्होंने जैसे कसम खा ली है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस दोस्ती के बारे में बताया जाता है कि इनमें से एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और दूसरी राज्य पुलिस सेवा की। इन दोनों की दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये जहां भी समय मिलता है, एक-दूसरे के हो जाते हैं। कई बार होटलों में जाते और आते हुए देखा भी गया है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि माइक-1 की पिटाई कई बार उनकी पत्नी ने भी की है। लेकिन साहब हैं कि वे अपने प्यार को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आलम यह है कि जहां इन दोनों के प्यार के किस्से अन्य अधिकारी चटखारे लेकर सुनाते नहीं थकते हैं, वहीं माइक-1 की करतूतों की भी कहानी लंबी है। बताया जाता है कि साहब ने खुलेआम सट्टे-जुए की इजाजत दे रखी है। इसका असर यह हो रहा है कि उनके क्षेत्र में सट्टे-जुए का गोरखधंधा चरम पर है। अगर कोई सट्टा-जुआ खिलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश भी करता है तो साहब का नाम सुनते ही पीछे हट जाता है। सूत्रों का कहना है कि साहब की इन करतूतों की शिकायत वरिष्ठों तक भी पहुंच गई है। देखना यह है कि साहब का बाल बांका हो पाता है या नहीं।

मैं हूं ना...

शीर्षक पढ़कर सबसे पहले आपको मामा की याद आ गई होगी या फिर शाहरुख खान की। क्योंकि प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में एक माननीय का प्रसिद्ध डायलॉग था- मैं हूं ना...। और इसी नाम से शाहरुख खान की एक फिल्म भी थी। लेकिन इन सबके इतर यह डायलॉग इन दिनों मालवा क्षेत्र के एक जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, मालवा क्षेत्र के एक जिले के पुलिस कप्तान ने इस डायलॉग को कोडवर्ड बना लिया है। सूत्रों का कहना है कि साहब ने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर रखा है कि अगर जिले में कहीं भी शराब और माइनिंग का परिवहन होता दिखे तो उसे रोकने की कोशिश न करें। बाकी जो कुछ भी हिसाब-किताब है, उसे मैं देख लूंगा। बताया जाता है कि साहब ने जिले में माफियाओं के साथ जुगलबंदी कर ली है। इस कारण जिले में शराब और माइनिंग का गोरखधंधा तेजी से पनप रहा है। माफिया साहब के प्रभाव से इस कदर प्रभावित हो गए हैं कि अगर उन्हें कोई रोकता है तो वे तत्काल साहब को फोन लगा देते हैं और साहब सामने वाले से कह देते हैं कि इन्हें जाने दो, मैं हूं ना...। एक तरफ सरकार सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और दूसरी तरफ अधिकारी अवैध कामों को संरक्षण दे रहे हैं।

मेरा दर्द न जाने कोई...

मीराबाई के प्रसिद्ध भजन की उपरोक्त पंक्तियां इन दिनों एक प्रमोटी आईएएस पर सटीक बैठ रही हैं। दरअसल, साहब कुछ महीनों बाद ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में साहब की कोशिश यह है कि एक बार उन्हें किसी जिले की कलेक्टरी मिल जाए। सूत्रों का कहना है कि साहब कलेक्टरी के लिए काफी बेचैन हैं और इधर-उधर हाथ-पांव भी मार रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहीं दाल गलती नहीं दिख रही है। जानकार तो यह भी बताते हैं कि 2011 बैच के प्रमोटी आईएएस अफसर इस कदर उतावले हो गए हैं कि उन्होंने दो लोगों को पैसे भी खिला दिए हैं लेकिन काम नहीं हो पाया है। सूत्रों का कहना है कि साहब अभी भी थके नहीं हैं और लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि कहीं न कहीं फिर से जुगाड़ लग जाए और उन्हें कलेक्टरी मिल जाए। सूत्रों का कहना है कि कई लोग साहब को यह बता चुके हैं कि कलेक्टरी मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन साहब हैं कि मानते नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि अकेले साहब ही नहीं बल्कि कई और ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, जो कलेक्टर बनने के लिए पॉकेट में पैसा लेकर चल रहे हैं। लेकिन हर किसी की दाल कहां गलती है। सूत्रों का कहना है कि दो जगह रकम डूबने के बाद भी साहब को लग रहा है कि कोई न कोई उनकी इच्छापूर्ति करवा सकता है। इसके लिए वे ऐसे माध्यम को तलाश रहे हैं जहां उनका पौव्वा लग जाए और अंत भला तो सब भला की तर्ज पर साहब को किसी जिले की कलेक्टरी मिल जाए।

हारे का सहारा, सुदामा हमारा

जपता फिरूं मैं नाम तुम्हारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा... इसी तर्ज पर इस समय प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में स्लोगन चल रहा है कि हारे का सहारा सुदामा हमारा...। इस स्लोगन पर मुहर उस दिन और ठीक से लग गई, जब सबसे कमाऊ विभाग के ठेकेदार अपनी समस्याओं से परेशान होकर मंत्रालय स्थित विभागीय अपर मुख्य सचिव से मिलने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। तब ही उन्हें किसी विभागीय अधिकारी ने सलाह दी कि सुदामा से मिल लें। पहले तो यह सुन ठेकेदार चौंक गए, फिर क्या था। वह सब लामबंद होकर नाथूद्वार पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी सारी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। बताया जाता है कि नाथूद्वार पहुंचने पर सुदामा ने ठेकेदारों से यह तक कह डाला कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके सारे काम पूरे होंगे। मोहन के सुदामा से मिलकर ठेकेदारों में आशा की उम्मीद जाग गई। यहां यह बता दें कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी, जो सिंहस्थ कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हीं के प्यारे सुदामा और मोहन की नजदीकियां पूरी गलियारों में चर्चा बनी हुई है।

जंगल में दखल

प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद जंगल महकमे में अब सबकुछ जंगल कानून की तरह ही हो रहा है। जिस तरह जंगल में राजा शेर के शासन की कमान चालाक सियार संभाल लेता है, उसी तरह वर्तमान सरकार में वन महकमे की कमान एक खनिज ठेकेदार के भाई और दलाल ने संभाल रखी है। विभाग के नए नवेले मंत्रीजी पहली बार मंत्री बने हैं। उन्हें मंत्रीगिरी आती है कि नहीं, यह तो कोई जानता नहीं है, लेकिन उनके विभाग पर एक दूसरी संप्रदाय और व्यापमं घोटाले के ठेकेदार के भाई ने कब्जा कर लिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मंत्रीजी ने ही विभाग को ठेके पर दे दिया है। क्योंकि मंत्रीजी को समझ नहीं आ रहा है। इसमें सच्चाई क्या है, यह तो मंत्रीजी ही जानें, लेकिन जानकारों का कहना है कि मंत्रीजी के करीबी ठेकेदार अन्य सप्लायरों के साथ मिलकर जमकर कमाई करने की योजना बना रहे हैं। यह बात ऊपर तक पहुंच गई है कि राम के राज में अकबर की एंट्री मंत्रीजी ने कैसे कर रखी है। दूसरे जनाब हैं जिनका निकनेम चुन्नू है। वह एक झाबुआ क्षेत्र में माइनिंग में जमकर माल कूट रहे ठेकेदार के भाई हैं।

वाकई में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि...

शासन-प्रशासन में सुचिता लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई कठोर कदम उठाए हैं। इस कड़ी में मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए थे कि वे अपने स्टाफ में ऐसे लोगों को रखें जो पाक-साफ हों। लेकिन संघ, सरकार और संगठन के निर्देशों को दरकिनार कर कई मंत्रियों ने अपनी निजी पदस्थापना में मनपसंद का स्टाफ रख लिया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी संघ मंत्रियों के स्टाफ की मनमानी पर सवाल उठाता रहा है। मंत्रियों के स्टाफ की करतूतों के कारण कई बार सरकार की फजीहत भी हुई है। इसलिए इस बार मंत्रियों के स्टाफ रखने के लिए गाइडलाइन मुख्यमंत्री कार्यालय से बनाई गई है। लेकिन मुख्यमंत्री की नाक के नीचे गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हो रहा है।

केंद्रीय संगठन ने निर्णय लिया था कि मंत्री की निजी पदस्थापना में जो स्टाफ पहले मंत्रियों के यहां पदस्थ रहा है, उसे पुन: निजी पदस्थापना में नहीं रखा जाए। यहां यह बता दें कि कैबिनेट मंत्री की निजी पदस्थापना में 12 पद होते हैं, जिसमें विशेष सहायक, निज सचिव, सहायक ग्रेड, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी, जिसमें जमादार, भृत्य, फर्राश, चौकीदार की पदस्थापना होती है। मंत्री चाहें तो निजी पदस्थापना में वह अपने पसंद के प्राइवेट लोगों को भी मंत्री रहते तक रख सकते हैं। यही हाल स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्रियों का भी है। इक्का-दुक्का परिवर्तन के साथ। 10-12 हफ्तों से मंत्रियों की निजी पदस्थापना में काम कर रहे कई कर्मचारियों ने तो वापस अपने विभाग का रुख कर लिया है। परंतु कई ऐसे हैं जो आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय के कर्मचारियों ने मंत्रालय पुल में पोस्टिंग करा ली है और अपने विभाग में दस्तखत करके वापस मंत्रीजी की सेवा में लग जाते हैं। यह सब मंत्रालय में हर संवर्ग का अधिकारी देख रहा है और समझ रहा है। इसका आभास मुख्यमंत्री सचिवालय को भी हो चुका है। परंतु मंत्री के मनमर्जी के कर्मचारियों को मंत्रीजी हटाने से असहमत हैं। ऐसे में अगर आदेश नहीं हुए तो आने वाले समय में उनको ईएल, सीएल और मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा। कई तो अपने विभाग से प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभाग में जाकर मंत्रीजी के यहां सेवाएं दे रहे हैं। इस खोखले आदेश का क्या मतलब है?

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चाहते हैं कि मंत्री अपने स्टाफ में नए अधिकारियों व कर्मचारियों को ही रखें। लेकिन भाजपा के केंद्रीय संगठन के निर्देश और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वीटो भी मंत्रियों के यहां उनके चहेते स्टाफ की पोस्टिंग नहीं रोक पा रहा है। पहले मंत्रियों के यहां पदस्थ रहे विशेष सहायक समेत अन्य स्टाफ की पदस्थापना की फाइल मुख्यमंत्री ने लौटाई तो मंत्रियों ने इस स्टाफ को अपने यहां पदस्थ करने के लिए नया रास्ता निकाल लिया। पहले इन अफसर-कर्मचारियों का अपने विभाग में डेपुटेशन कराया, फिर अपने यहां ज्वाइनिंग करा ली। वहीं कई ओएसडी, निज सहायक और निज सचिव बिना किसी आदेश के अब भी मंत्रियों के यहां धड़ल्ले से सेवाएं दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये अधिकारी और कर्मचारी विभाग से अवकाश पर हैं। गौरतलब है कि मंत्रियों के यहां चहेते स्टाफ की पदस्थापना का मामला कैबिनेट की बैठक में भी उठ चुका है। बुंदेलखंड और चंबल के मंत्रियों ने यह मामला उठाते हुए कहा था कि पुराना स्टाफ काम समझता है, नए स्टाफ को फिर से काम समझना होता है, इससे दिक्कत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पुराने स्टाफ की फिर से पदस्थापना करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि ऊपर से ऐसे आदेश हैं।

सरकार की पाबंदी के बाद मंत्रियों ने मन चाहा स्टाफ रखने के लिए ऐसा रास्ता निकाला जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पहला मामला सत्यशुभ्र मिश्रा का है। मिश्रा महिला बाल विकास विभाग में अधिकारी हैं। पिछले कार्यकाल में मंत्री इंदर सिंह परमार के यहां विशेष सहायक के तौर पर पदस्थ थे। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने नस्ती लौटाई, तो महिला बाल विकास विभाग से आयुष विभाग में डेपुटेशन कराया, फिर से मंत्री स्टाफ में पदस्थ किए गए। इंदर सिंह परमार के पास आयुष मंत्रालय भी है। वहीं भरत व्यास स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य संवर्ग के अधिकारी हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार के यहां पदस्थ थे। इस बार नियमों के पैच में पदस्थापना उलझी तो स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा विभाग में डेपुटेशन कराया। फिर मंत्री के यहां जम गए। इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। ऐसे ही अनेकों उदाहरण सामने हैं।

कई कर्मचारी ऐसे हैं, उन्हें मंत्रियों के यहां रहने की बीमारी लग चुकी है। उन्होंने जीवनभर नौकरी ही मंत्रियों की निजी पदस्थापना में की है। आखिर मंत्रियों की निजी पदस्थापना रहने से गाड़ी-घोड़ों, नौकर-चाकर, रुतबा और लक्ष्मी का वास बनने के कारण उन्हें यही नौकरी रास आती है। हमारे पास तो ऐसे कई उदाहरण हैं, जो अपने पैसे देकर मंत्री के यहां पोस्टिंग कराते हैं और बाद में जिसकी निजी पदस्थापना में रखे गए हैं, उन्हें भी पैसा कमाकर खुद भी कमा लेते हैं। मंत्रियों को गुर और जासूसी बताने का काम यही कर्मचारी कई दशकों से करते आ रहे हैं। इनके मुख्य काम फाइलों में सेटिंग करना, मंत्रीजी से अनुमोदन कराना और दूसरों को परेशान करना है। इसी के नाम पर यह अपनी सेवाएं देते रहते हैं और इस बात का एहसास हर एक मंत्री को है। पर उन्हें पता है अनुभवी निजी पदस्थापना में रहने वाले कर्मचारी के ही माध्यम से ही वह अपने विभाग को सोचे हुए मंसूबों से आगे ले जाएंगे।

● **कुमार विनोद**

सशर्त मन पसंद स्टाफ रखने की छूट

उधर, सूत्रों का कहना है कि अब सरकार ने अपने मंत्रियों को सशर्त मनपसंद स्टाफ रखने की छूट प्रदान कर दी है। इसकी वजह से अब मंत्रियों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। अब मंत्री अपनी पसंद के अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने स्टाफ रखने की कवायद में लग गए हैं। हालांकि शर्त के मुताबिक उन अधिकारी एवं कर्मचारी को स्टाफ में नहीं रखा जा सकेगा जो पूर्व की सरकार के मंत्री के स्टाफ में रहा हो। दूसरे मंत्रियों के साथ काम कर चुके निज सचिव एवं निज सहायक और विशेष सहायकों को जरूर अपने साथ रखने की इसमें छूट दी गई है। यही नहीं स्टाफ में रखे गए संबंधित कर्मचारी की ईमानदारी की जिम्मेदारी भी मंत्री को ही लेनी होगी।

2 माह में आईएएस के रिकॉर्ड तबादले

मप्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की, जबकि 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल बना और 30 दिसंबर को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। मुख्यमंत्री बने मोहन यादव को दो महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान उनका सबसे अधिक फोकस सुशासन, जीरो टॉलरेंस और नई जमावट पर रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने छोटी-छोटी खामी पर अफसरों को चलता कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दो महीने के कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान 179 आईएएस के तबादले किए गए हैं। दरअसल, एक तो चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश, दूसरा अफसरों की लापरवाही और तीसरा नई जमावट के तहत प्रदेश में अफसरों का तबादला किया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने वर्षों से शासन के बड़े पदों पर बैठे अफसरों को दरकिनार कर युवा अफसरों को बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। इसी के कारण प्रदेश में आईएएस अफसरों के रिकॉर्ड तबादले किए गए हैं। मप्र की नई सरकार ने 2 महीने के भीतर 179 आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने थोकबंद आदेश जारी नहीं करते हुए टुकड़ों में 29 आदेश जारी किए हैं। तबादलों से प्रदेश में पदस्थ आधे से ज्यादा अधिकारी प्रभावित हुए हैं। क्योंकि आईएएस की पदक्रम सूची के अनुसार कुल 384 आईएएस अधिकारी हैं। जिनमें से दो दर्जन से अधिक अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। 179 अधिकारियों के तबादला आदेशों में 96 अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा। 45 के प्रमोशन के बाद उसी जगह नई पदस्थापना की गई। जबकि 36 अधिकारियों को प्रभार सौंपे गए।

प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में लंबे समय से कोई बड़ा कसावट लाने जैसे निर्णय नहीं लिए गए। कई अधिकारी ऐसे हैं, जो नई जिम्मेदारी के इंतजार में थे। नई प्रशासनिक जमावट में इसका खासा ध्यान रखा गया है। मप्र के विकास के लिए प्रशासन की नई टीम तैयार हो रही है। जो प्रत्याशित स्वभाविक है। प्रदेश में 13 दिसंबर 2023 को नई सरकार के गठन के बाद 15 दिसंबर को आईएएस का पहला तबादला आदेश प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का निकाला गया। इसके बाद तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ। 12 फरवरी तक 27 आदेश जारी हो चुके थे। जिनमें 172 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। खास बात यह है कि इन तबादला आदेशों में मुख्य सचिव वीरा राणा का भी आदेश शामिल है। 19 फरवरी को 28वां तबादला आदेश जारी किया गया, जिसमें एक जिले के कलेक्टर समेत 5 आईएएस अधिकारी बदले गए हैं। अभी तक कुल 179 अधिकारियों की बदली हो चुकी है। इनमें प्रमोशन के बाद जारी किए गए 45 अधिकारियों के तबादला आदेश भी शामिल हैं। पिछले महीने 1 जनवरी को तीन अलग-अलग आदेशों में 40 अधिकारियों की पदोन्नति के बाद नई पदस्थापना की गई। 10 जनवरी को एक अधिकारी और 8 फरवरी को 4 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए। हालांकि इन अधिकारियों की नई पदस्थापना भी उसी स्थान पर ही रही।

ज्यादातर तबादले मंत्रालय या विभागाध्यक्ष स्तर पर हुए हैं। जिलों में सिर्फ 12 कलेक्टर बदले गए हैं। हालांकि यह प्रशासनिक जमावट तंत्र में कसावट लाने की मंशा से की गई है। जिसमें लंबे समय से लूपलाइन में पड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन स्तर पर काफी विचार के बाद यह निर्णय लिए गए हैं। यह बात अलग है कि प्रदेश में अधिकारियों के तबादले राजनीतिक मुद्दा रहा है। सरकार ने अभी तक सिर्फ 12 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। जिनमें गुना, होशंगाबाद, उज्जैन, बैतूल, शाजापुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, हरदा, छिंदवाड़ा और श्योपुर जिले हैं। गुना और हरदा कलेक्टर हादसों की वजह से बदले गए।

वहीं सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार जल्द ही एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने जा रही है। सूत्रों का कहना है की तबादले की सूची बनकर तैयार है। कई विभागों के प्रमुखों के साथ ही फील्ड में पदस्थ आईएएस और आईपीएस अफसरों के थोकबंद तबादले होंगे। इनमें दर्जनभर से अधिक कलेक्टर और एसपी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर अफसरों की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी।

● **अरविंद नारद**

वीरा राणा बनी रहेंगी सीएस

मुख्य सचिव वीरा राणा 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगी। इसी माह के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव की घोषणा भी संभावित है। इसके पहले उन्हें सेवावृद्धि दी जा सकती है। दरअसल, ऐसा नहीं होता है तो फिर अगला मुख्य सचिव सरकार अपनी पसंद से पदस्थ नहीं कर पाएगी। वरिष्ठता

के आधार पर चुनाव आयोग को तीन नाम प्रस्तावित करने होंगे और फिर उसकी सहमति से ही पदस्थापना होगी। सामान्यतः ऐसे मामलों में वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना होती है। वीरा राणा को भी वरिष्ठता के आधार पर ही आयोग की सहमति से मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया था और फिर चुनाव उपरांत सरकार ने उन्हें पूर्णकालिक मुख्य सचिव नियुक्त किया। चुनाव में सीधे तौर पर तो मुख्य सचिव की कोई भूमिका नहीं होती है पर कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण होने के कारण आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन वे ही सुनिश्चित कराते हैं। चुनाव के दौरान वे प्रतिनियुक्ति पर आयोग के अधीन माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद यह दूसरा अवसर है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके पहले मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की दूसरी सेवावृद्धि की अवधि चुनाव के समय पूरी हुई थी और सरकार ने तीसरी सेवावृद्धि दिलाने के स्थान पर वरिष्ठता के आधार पर आयोग की सहमति से 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया था।

विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 163 सीटें जीतने के बाद अब भाजपा मप्र की 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी के साथ मिलकर मिशन 29 के अभियान में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में अबकी बार 400 पार के लक्ष्य के लिए बिना सुकून जीत का जुनून भाजपा में देखने को मिल रहा है।

अबकी बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ

डॉ. मोहन यादव जब से मप्र के मुख्यमंत्री बने हैं वे लगातार सक्रिय हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बिना रूके बैठकें, दौरें और सभाएं कर रहे हैं। मोदी-शाह की ही तरह सत्ता और संगठन की यह जोड़ी विधानसभा की बड़ी जीत से संतुष्ट नहीं आ रही है, बल्कि उस जीत के बाद और बड़ी जीत को लोकसभा चुनाव में हासिल करने में जुट गई है। वैसे भी सत्ता का सफल राजनीतिज्ञ वो होता है जो चुनाव में अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय नए-नए सपनों को बेचना जानता हो। उपलब्धियां मन में संतोष पैदा करती हैं जबकि सपनों को हासिल करने के लिए सक्रिय होकर काम करना पड़ता है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को वही सपना दिखा दिया है। उन्हें बताया गया है कि जीत का जुनून हो तभी जीत संभव होती है और जब तक ऐसा न हो जाए तब तक सुकून और शांति से नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं है कि खुद मोदी-शाह की जोड़ी भी सपने बेचकर शांत भाव में घर बैठ जाते हैं।

अब मोदी-शाह की तरह मप्र में मोहन-विष्णु (वीडी शर्मा) की जोड़ी बिना सुकून जीत के जुनून में लिपटी दिख रही है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में डेढ़-दो महीने की देर है, और पिछले एक-डेढ़ महीने में पूरा विमर्श बदल गया है। अब मप्र भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भाजपा इस बार 400 से अधिक सीटें जीतेगी। उनका कहना है कि इस अभियान में भाजपा प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतेगी। भाजपा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में मिशन 2024 में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि हमेशा मिशन मोड में रहने वाली भाजपा ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। मप्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भाजपा राज्य में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुट गई है। भाजपा का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों जीता जाए। इसके लिए पार्टी में रणनीति बनने लगी है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर भाजपा का और एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट समेत सभी 29 सीटों को जीतने के लिए भाजपा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर ही काम करेगी। जानकारों की मानें तो विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की घेराबंदी की जाएगी।

370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने मप्र के दौरे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे मप्र की सभी 29 लोकसभा सीटें भाजपा के लिए चाहिए। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, इसके बाद प्रचंड जीत हमारी होगी। शाह ने कहा कि कांग्रेस में जिन कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं हो रही है, वे भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाए। बैठक में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्रों के मंत्री, प्रबंध समिति, कोर समिति, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कलस्टर प्रभारी, संगठन प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी शामिल रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार की जनहित की अच्छी योजनाओं और कामों को जन-जन तक पहुंचाएं इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने का काम करें। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। भ्रमित हो रहा है इसलिए उन्हें जोड़ने का काम करें। कांग्रेस मुक्त बूथ के लिए काम करें। हर बूथ पर 370 नए मतदाताओं को जोड़ना है। कांग्रेस मुक्त बूथ तैयार करने हैं। मतदाताओं से अधिक से अधिक संवाद करें, योजनाओं के बारे में बताएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें।

ऐसे में पार्टी ने यहां पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दिया है। तभी जाकर भाजपा के लिए लोकसभा की राह आसान हो पाएगी। 2003 के बाद भारतीय लोकतंत्र में यह देखा गया है कि विधानसभा और लोकसभा में एक जैसे पैटर्न पर चुनाव नहीं होते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा कर्नाटक में भी अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भाजपा पार्षद से लेकर लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत करती है। वह किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। खास बात यह है कि छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का साथ मिलता है। जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का भी हौंसला बुलंद हो जाता है। पार्टी के आलाकमान की कोशिश है कि वे इस जीत को लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भाजपा मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का किला भेदने में सफल हो पाई है। भाजपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में भी वह इसे बरकरार रखें।

भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे को पूरा करने को लेकर वो तैयार हैं और उसको अपने-अपने राज्यों में पूरा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। मप्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि भाजपा के अधिवेशन में फिर से तीसरी बार वापसी को लेकर प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास बोल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वोटरों तक पहुंच रहे हैं। भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट की बहुत चर्चा होती है। वह यही है जो प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने के लक्ष्य के रूप में दिया है। कैसे जोड़ना है यह भी बताया गया है। कहा गया है कि पहली बार मतदाता सूची में जुड़े एक भी वोटर अछूते न रहें। हर लाभार्थी तक पहुंचे। नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में सीटों पर जीत-हार का अंतर 25 हजार से एक लाख के बीच ही होता है। दूसरी तरफ का फर्क देखिए। देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने राजीव गांधी के समय 414 का आंकड़ा छुआ था। तब देश में कुल वोटर की संख्या 38 करोड़ थी और वोट डालने वाले लगभग 24 करोड़ थे। कांग्रेस ने कुल वोटिंग का लगभग 50 फीसदी हासिल किया था। बड़ी हैरानी की बात है कि तब से लेकर अब तक कांग्रेस चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में उसके वोटरों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है।

हर बूथ पर 51 प्रतिशत वोट का टारगेट

भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि 2004 के संप्रग काल में कांग्रेस को साढ़े दस करोड़ वोट मिले थे तो 2009 में 11.91 और 2019 में 11.94 करोड़। जबकि कुल वोटरों की संख्या में लगभग तीनगुनी वृद्धि हो चुकी है। 2024 के चुनाव में वोटरों की संख्या लगभग 98 करोड़ होगी। भाजपा 1984 के लगभग दो करोड़ वोटरों के मुकाबले 1019 में 23 करोड़ पर पहुंच चुकी है और अब इसे कम से कम दोगुना करने की तैयारी है। अपने काम और प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे भाजपा की नई रणनीति कुल वोटरों का पचास फीसदी हिस्सा लेने की है। अगर यह संभव हुआ तो एक ऐसा इतिहास बनेगा किसी भी लोकतंत्र के लिए उदाहरण होगा। अगर मप्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हर बूथ पर 51 प्रतिशत वोट शेयर के टारगेट की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले तीन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के रिजल्ट का एनालिसिस कर पार्टी ने यह पॉलिसी बनाई है। पार्टी ने जिला टोली और मंडल टोली भी बनाई है। यहां प्रवासी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा, जो क्षेत्र में जाकर संपर्क करेंगे। संगठन के कामों में सुधार कराएंगे। इससे पहले, 2023 के मप्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यही रणनीति अपनाई थी। इसमें भी हर बूथ पर 51 प्रतिशत वोट हासिल करने का टारगेट तय किया था। इसमें पार्टी को 48.55 प्रतिशत वोट मप्र में मिले। दूसरे राज्यों या जिलों के भाजपा कार्यकर्ता चुनाव के समय अन्य राज्य या जिलों में जाते हैं। इन्हें पार्टी किसी बूथ या अन्य क्षेत्र की जिम्मेदारी देती है। इसे प्रवासी कार्यकर्ता कहते हैं। प्रवासी कार्यकर्ता अपने गांव, नगर के धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और अमृत सरोवर पर साफ-सफाई भी करेंगे। स्थानीय वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और नेता के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने भी पहुंचेंगे।

राष्ट्रीय अधिवेशन में मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। मोदी ने मंडल प्रभारियों को हर एक पन्ना प्रमुख से 30 दिन में कम से कम एक बार मिलने को कहा है। मोदी चाहते हैं कि भाजपा हर वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंचे। इसके लिए सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को कहा गया है। देश में 10 लाख 35 हजार बूथ हैं, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 1900 बूथ। अगर हर बूथ पर 370 वोट जोड़े गए, तो एक लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोट जोड़ने होंगे और पूरे देश में 38 करोड़ वोटर जोड़ने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को हर लाभार्थी तक पहुंचकर प्रधानसेवक का प्रमाण पहुंचाने को कहा। लाभार्थी के साथ मिलने पर कार्यकर्ताओं को नमो एप के सहारे लाभार्थी को मोदी की चिट्ठी भी देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 साल के काम और पांच साल के प्लान के साथ हर मतदाता तक पहुंचने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से संपर्क के समय पंथ, परंपरा को दरकिनार रखना होगा। किसी कारण यदि कोई मतदाता अभी तक भाजपा के साथ नहीं जुड़ नहीं पाया है, तो उन्हें भी इस बार साथ में जोड़ने के लिए काम करना होगा। प्रदेश में राष्ट्रीय अधिवेशन के संकल्पों का क्रियान्वयन कैसे करना है इसका निर्णय प्रदेश कार्यसमिति में होना है। देश में अबकी बार 400 पार के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय अधिवेशन में रोडमैप तैयार कर लिया है। अब प्रदेश इकाईयों को उस रोडमैप पर काम करना है। ऐसे में मप्र में मिशन 29 के लिए रणनीति बनाने भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक जल्द होने वाली है। इस बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन के रोडमैप पर चर्चा होगी और उसके क्रियान्वयन का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

चींटी की चाल, मास्टर प्लान धड़ाम

दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाने की मांग

विधायक शर्मा ने बताया, भोपाल अपनी खूबसूरती, प्राकृतिक वातावरण और शांति के कारण देशभर के लोगों के निवास और व्यवसाय का केंद्र बनते जा रहा है। इसीलिए भोपाल का मास्टर प्लान दिल्ली-एनसीआर और मुंबई-बेंगलुरू की तर्ज पर ही बनना चाहिए। इस प्लान में ज्यादा से ज्यादा एफएआर लागू कर हाईराइज बिल्डिंग को प्रमोट करना चाहिए। प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार चलें तो लोग मजबूरी में अवैध निर्माण को प्रोत्साहित होंगे। पूर्व में भी एफएआर कम होने के कारण भोपाल में 5 हजार से अधिक लोगों ने कंपाउंडिंग करवाई है और हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है। मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कंपाउंडिंग की जरूरत कम से कम पड़े और लोग लीगल निर्माण के लिए प्रोत्साहित हों। मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस नेता ज्ञानचंदानी ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि नए मास्टर प्लान मे बैरागढ़ से सीहोर रोड तक की जमीनों का उपयोग कृषि से हटाकर कैचमेंट में प्रस्तावित किया है, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से दिक्कतें हो रही हैं। बैरागढ़ की आबादी तीन गुना तक बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से मास्टर प्लान में कोई प्लानिंग नहीं है।

एक बार फिर राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान धड़ाम हो गया है। 19 साल बाद भोपाल के मास्टर प्लान को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन 23 फरवरी को उसे रोक दिया गया। अब भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट नए सिरे से बनेगा। यह साल 2047 की आबादी के हिसाब से तैयार होगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कृष्णा गौर समेत भोपाल के सांसद-विधायकों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मौजूदा ड्राफ्ट को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नकार दिया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग में कहा कि राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान जनप्रतिनिधियों के दिए गए सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। राजधानी का सुव्यवस्थित विकास हो और नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं सुलभ तरीके से मिल सकें, इसके लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। बता दें कि मौजूदा ड्राफ्ट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद अब यह नए सिरे से मास्टर प्लान तैयार होगा। भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट चार बार बन चुका है। दो बार तो प्रकाशित होने के बाद खारिज हुआ है।

गौरतलब है कि भोपाल मास्टर प्लान-2031 में आई आपत्तियों पर सुनवाई पिछले साल 9 अगस्त से 5 सितंबर तक हुई थी। आखिरी चरण में जमकर हंगामा हुआ था। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी समेत किसानों ने कृषि भूमि को कैचमेंट एरिया में शामिल करने समेत कई बिंदुओं पर नाराजगी जताई थी। क्रेडाई ने भी कई मुद्दों पर आपत्तियां ली थीं। इससे पहले सरकार ने मास्टर प्लान का ड्राफ्ट 2 जून को जारी कर दिया था। ड्राफ्ट जारी होने के 30 दिन के अंदर कुल 3005 आपत्ति और सुझाव मिले थे। इनमें बड़ा तालाब किनारे बसाहट, बाघ एरिया समेत कई रहवासी इलाकों को लेकर आपत्तियां आई थीं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव केवीएस चौधरी कोलसानी ने दावे-आपत्तियों पर सुनवाई की थी।

भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 1995 में जारी किया गया था, जो 2005 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से मास्टर प्लान का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, बीच में तीन बार मास्टर प्लान को लेकर कवायदें होती रहीं। 2021 में तो इसे लेकर दावे-आपत्ति भी बुलाए गए थे। हालांकि, इसमें कई बड़े संशोधन किए जाने थे। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया, टाइगर मूवमेंट एरिया, सड़कों आदि को लेकर यह संशोधन थे। इसके चलते यह ड्राफ्ट जारी नहीं हो सका था। इस साल फिर से मास्टर प्लान को लेकर सारी कवायदें हुईं, लेकिन फिर से यह खारिज कर दिया गया।

भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट अब नए सिरे से बनेगा। 2031 के ड्राफ्ट को मंत्री, सांसद और विधायकों ने खारिज कर दिया है। अब यह साल 2047 की आबादी के हिसाब से तैयार होगा। दिसंबर-24 तक इसकी प्रोसेस पूरी होगी, फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर नया ड्राफ्ट बनेगा। मौजूदा ड्राफ्ट पर विधायकों की नाराजगी और आपत्तियां ही भारी पड़ी थी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो ड्राफ्ट को शहर की 35 लाख आबादी के साथ धोखा बताया था, जबकि मंत्री कृष्णा गौर ने भी आपत्ति ली थी।

साल 2047 तक की आबादी के लिए भोपाल का मास्टर प्लान बनाने की योजना अब राजधानी को हाईराइज भवनों की ओर ले जाएगी। 2031 के लिए जो ड्राफ्ट बना था, उसे कैंसिल कर दिया गया है। इसमें प्लानिंग एरिया 1016.90 वर्ग किमी था। अब भोपाल जिले में प्लानिंग एरिया बढ़ाने का विकल्प ज्यादा बचा नहीं है। इसलिए 23 साल बाद यानी 2047 तक के लिए नगर योजना बनानी है तो शासन को जनसंख्या घनत्व को बढ़ाना होगा। इसके अलावा नई प्लानिंग में मेट्रो ट्रैक के आसपास का घनत्व भी बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में मेट्रो को भी रफ्तार मिल सके। दावा ये है कि मास्टर प्लान दिसंबर 2024 तक लागू कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि प्लानिंग एरिया में बदलाव किए तो मास्टर प्लान को दिसंबर 2024 तक ला पाना मुमकिन नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त से सितंबर तक 6 चरण में ऑनलाइन सुनवाई की गई थी। जिसमें विधायक शर्मा ने कई सवाल उठाए थे। उन्होंने साफ कहा था कि प्रस्तावित मास्टर प्लान बिना भौतिक सत्यापन किए शहर की परिस्थितियों को समझे बिना ही आंख बंद करके बना दिया गया है। यह शहर की 35 लाख आबादी के साथ धोखा है। 60-70 वर्षों से लेकर 100 साल तक पुराने गांव हैं, जो कि अब नगर निगम सीमा में है। उनकी भूमि एग्रीकल्चर थी। अब उनकी भूमि को ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट में डाल दिया गया। जिसके कारण वह अपनी भूमि पर खेती से संबंधित भी कोई उपक्रम या डेयरी आदि भी संचालित नहीं कर पाएंगे।

● **रजनीकांत पारे**

न्यायायिक जांच पर सवाल...

मप्र में बीते डेढ़ दशक में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण हुए बड़े हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। अपनों को खोने का दर्द उनके परिवार के लोग अभी भी झेल रहे हैं। जिनके कारण यह दर्द मिला, उन दोषियों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने जनमानस के जख्म पर मरहम लगाने के लिए ऐसे बड़े मामलों में न्यायायिक जांच आयोग गठित की थी। इनकी रिपोर्ट भी आईं लेकिन अब तक किसी भी दोषी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जांच आयोग में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ऐसे में अब लोग सवाल करने लगे हैं कि किसकी मजाल है जो न्यायायिक जांच आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सके।

गौरतलब है कि न्यायायिक जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा-3 के तहत गठित होती हैं। फिर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। न्यायिक आयोग बनाए जाते हैं। ये आयोग इसलिए गठित किए जाते हैं, ताकि जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसकी असलियत जनता के सामने आ सके। आयोग जांच करता है। जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है.. ? असलियत ये है कि आयोग की रिपोर्ट विभागों में धूल खाती है। प्रदेश में 15 साल में 8 आयोगों की रिपोर्ट आई हैं और वे धूल खा रही हैं। जबकि इस दौरान 4 सरकारें आईं, लेकिन एक भी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। मप्र में 6 बड़े हादसों में 374 मौतें हुई हैं। किसी में मजिस्ट्रियल तो किसी में ज्यूडिशियल जांच के आदेश हुए। हर हादसे के बाद जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का सरकारी ऐलान हुआ, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई।

जब भी कोई बड़ी घटना-दुर्घटना होती है सरकार न्यायायिक जांच आयोग का गठन कर देती है। आयोग के अध्यक्ष, सचिव, दो क्लर्क, एक स्टेनो, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर आदि के वेतन, इसके अलावा यात्रा भत्ता, खाने-पीने का खर्च, दो कम्प्यूटर, स्टेशनरी, पूरा दफ्तर का सामान, दो गाड़ियों का खर्च, इस तरह एक महीने कम से कम लाखों रुपए खर्च करते हुए करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वह कहां खो जाती है इसकी सुध किसी को नहीं रहती है। 15 साल में राज्य में चार सरकारें सत्ता में रहीं। इसमें तीन बार भाजपा और डेढ़ साल कांग्रेस का शासनकाल रहा। इस कार्यकाल में राज्य में कई बड़ी वारदातें हुईं। सरकार ने इसकी जांच के लिए 8 आयोग बनाए। आयोगों ने सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन ये रिपोर्ट फाइलों में कैद हो गईं। 15 साल बाद भी सरकार ये रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं पहुंचा सकी है, जबकि मंत्रालय से विधानसभा की दूरी महज आधा किमी है। 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब नई सरकार में ही जिम्मेदारी तय होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इनमें से पेटलावद में मोहर्रम जुलूस रोकने की घटना की जांच रिपोर्ट सरकार ने विधानसभा में रखी थी। अन्य आयोगों की अनुशंसाओं पर कार्यवाही चल रही है। मंदसौर गोलीकांड, वृद्धावस्था पेंशन घोटाला समेत कई जांच आयोगों की रिपोर्ट फाइलों में बंद हैं।

वर्ष 2008 से लेकर अभी तक सरकार ने 9 मामलों में आयोग का गठन कर जांच करवाई है। इनमें से 8 की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन वे धूल खा रही हैं। सरकार ने 18 फरवरी 2008 को सामाजिक सुरक्षा व वृद्धावस्था पेंशन योजना की अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग बनाया था। आयोग ने 15 सितंबर 2012 को रिपोर्ट सबमिट की। 15 साल में सरकार रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रख सकी। इसमें कई नेता, अफसर घेरे में हैं। कई बार सवाल भी उठे, पर हर बार सरकार ने कार्यवाही की बात कही। वहीं मंदसौर गोलीकांड में 6 जून 2017 को 5 किसानों की मौत के बाद सरकार ने 13 जून 2018 को जांच के लिए रिटायर जज जेके जैन की अध्यक्षता में जैन आयोग बनाया। आयोग ने 13 जून 2018 को रिपोर्ट दी। पूर्व विधायक पारस सखलेचा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखना जरूरी है, पर सरकार जानबूझकर नहीं रख रही। वहीं भोपाल में यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव की रिपोर्ट आयोग ने 24 फरवरी 2015 को सबमिट की। गैस राहत विभाग में कार्यवाही चल रही है। भिंड गोली चालन में जांच आयोग ने 31 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट सबमिट की। जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही चल रही है। गोलपुरा-2 मानमंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के मामले में आयोग ने 9 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दी, यह गृह विभाग में पड़ी है। पेटलावद के विस्फोट मामले की जांच रिपोट आयोग ने 11 दिसंबर 2015 को मुख्य सचिव को भेजा। यह गृह विभाग को भेजा गया। पेटलावद में मोहर्रम जुलूस रोकने की घटना की जांच आयोग ने 20 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दी। 5 जुलाई 2019 को यह विधानसभा के पटल पर रखा गया। मंदसौर में घटित घटना की जांच आयोग ने 14 जून 2018 को गृह विभाग को भेजा। लेकिन इन रिपोर्ट के मिलने के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई।

● श्याम सिंह सिकरवार

मिल रही तारीख पर तारीख

विदिशा जिले में करीब दो साल पहले हुए लटेरी गोलीकांड में आदिवासी की मौत के मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आदिवासी की मौत के मामले में जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल फिर एक बार बढ़ा दिया गया है। गोलीकांड में पिछले दो सालों से जांच आयोग की रिपोर्ट पर बस तारीख पर तारीख मिलती आ रही है। 9 अगस्त 2022 को विदिशा के लटेरी के खटयापुरा में लकड़ी चोरी के शक में वनकर्मियों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना में चैन सिंह नामक आदिवासी की मौत हो गई थी। हालांकि पूरी घटना के दौरान तीन लोग गंभीर तौर पर घायल भी हुए थे। मामले के दौरान मृतक के परिजनों ने वनकर्मियों पर जानबूझकर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट तीन महीने के अंदर सौंपी जानी थी, लेकिन जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है।

अर्थं शरणम् गच्छामि

500 बिलियन डॉलर होगी उप्र की अर्थव्यवस्था

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पिछले महीने जनवरी में की गई एक रिसर्च में बताया गया है कि 2028 तक उप्र की अर्थव्यवस्था 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। उप्र की इस आर्थिक ताकत को बनाने में सबसे अधिक अगर कोई मदद करेगा तो वह धार्मिक पर्यटन ही होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल 2024 के खत्म होने तक उप्र में धार्मिक पर्यटन से 4 लाख करोड़ का कारोबार होगा। इससे राज्य सरकार को राजस्व के रूप में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए प्राप्त होगा। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट का अनुमान है कि आने वाले चार-पांच सालों में अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थक्षेत्र बनकर उभरेगा जहां सालाना 5 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटक रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस तरह अयोध्या भविष्य में आगरा को पीछे छोड़ प्रदेश का नंबर वन पर्यटन केंद्र बन जाएगा। इसके अलावा काशी, मथुरा और प्रयागराज तो अपनी तरह से देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते ही हैं।

चाणक्य नीति में कहा गया है कि सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलं अर्थः। अर्थस्य मूलं राज्यं। अर्थात् सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। उप्र में चाणक्य की यह नीति पूरी तरह से चरितार्थ होती दिख रही है। 2017 में जबसे राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से सुख के मूल धर्म को ही प्रमुखता से स्थापित करने का प्रयास ही नहीं हो रहा, बल्कि धर्म के मूल अर्थ को भी प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। 19 फरवरी को उप्र ने एकसाथ 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का भूमिपूजन करके अपनी बीमारू राज्य और काऊ बेल्ट वाली छवि को सफलता से बदलने का प्रयास किया है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि उप्र में कांग्रेसियों, समाजवादियों और बहुजनवादियों के शासन में जिस धर्म को राज्य से दूर रखा गया, वही धर्म अब उप्र की आर्थिक समृद्धि का वाहक बन गया है। केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने और उसके बाद राज्य में 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद धर्म से दूरी के बजाय धर्म से नजदीकी दिखाने की कोशिश की गई। यह नजदीकी ऊपरी तौर पर तो राजनीतिक ही लग रही थी लेकिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरीडोर और अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद उप्र की अर्थव्यवस्था को धर्म का पंख लग गया है। काशी में सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरीडोर ही नहीं बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण काशी की आधारभूत संरचना में भारी भरकम निवेश किया गया।

बिजली, सड़कें, गलियां, घाट, पोखरे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सबको हजारों करोड़ रुपए के निवेश से निखारा गया। बाबा विश्वनाथ में आस्था के कारण तीर्थयात्री और पर्यटक तो पहले भी कम नहीं आते थे लेकिन काशी में भारी भरकम पूंजी निवेश ने उसे एक आकर्षक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया है। मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, और बहुत हद तक वो इसमें सफल भी रहे हैं। हस्तकला संकुल, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सहित अंतरराष्ट्रीय मानक की सुविधाएं विकसित होने से काशी की कला और संवाद परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मंच मिला है। मोदी शुरू से ही काशी के औद्योगिकीकरण से अधिक उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं और देशी-विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के रूप में उसका परिणाम भी अब दिखने लगा है।

इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक और राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि उप्र के लिए आर्थिक रूप से भी वरदान साबित होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही प्रापर्टी के बड़े कारोबारी और होटल व्यवसायी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। 19 फरवरी को लखनऊ में निवेश के जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उनमें अकेले अयोध्या में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी मिली। इसमें लोढा ग्रुप द्वारा तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से एक लक्जरी रेसिडेन्शियल सिटी बनाने का प्लान है तो कई बड़े होटल, रिसोर्ट खोलने का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इसी तरह काशी में 15 हजार करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का भूमिपूजन हुआ जिसमें फाइव स्टार होटल से लेकर अन्य होटल और रिसोर्ट बनेंगे। लखनऊ के भूमिपूजन समारोह में जिन निवेशकों ने होटल, रिसोर्ट या रियलिटी सेक्टर में निवेश करने का वादा किया है उनमें सबसे अधिक काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयाग में ही निवेश का प्रस्ताव है। रियलिटी सेक्टर में निश्चित रूप से नोएडा सबसे आगे है लेकिन तीर्थक्षेत्रों में निवेशकों का उत्साह बताता है कि भारत में धार्मिक यात्राएं ही व्यापार की सबसे प्रबल संभावना पैदा करती हैं। यह बात पूंजी निवेशक अब अच्छे से समझने लगे हैं। इसलिए उप्र की योगी सरकार ने अगर धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास पर ध्यान दिया है तो इसका जबर्दस्त आर्थिक लाभ भी प्रदेश को होता दिखाई दे रहा है। 19 फरवरी के भूमिपूजन में प्रदेश के प्रमुख सात तीर्थस्थानों पर 86 हजार करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, जिनका भूमिपूजन किया गया। इसमें काशी में 15 हजार करोड़, मथुरा में 13,500 करोड़ और अयोध्या में लगभग 10 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिला दें तो करीब 40 हजार करोड़ का निवेश इन्हीं तीन तीर्थस्थानों में होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह निवेश इन तीनों तीर्थस्थानों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पटल पर मजबूत होने में मदद करेगा।

काशी, मथुरा, अयोध्या के अलावा प्रदेश की योगी सरकार ने अन्य प्रमुख तीर्थक्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया है। इसमें विंध्याचल में कॉरीडोर का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। योगी सरकार मथुरा वृंदावन कॉरीडोर पर भी काम कर रही है। देवीपाटन, नैमिषारण्य के साथ ही कुंभ नगरी प्रयाग में भी आधारभूत ढांचे के विकास पर निरंतर काम हो रहा है। अगले साल 2025 में प्रयाग में महाकुंभ होने वाला है जिसे देखते हुए अभी से योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य की धर्म से करीबी का परिणाम यह हुआ है कि हर तीर्थक्षेत्र में निवेशक पहुंच रहे हैं। अभी तक प्रदेश सरकारों की ओर से ताजमहल को ही प्रमुखता से प्रचारित किया जाता था जिसका लाभ आगरा को मिला। लेकिन अब मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयाग, विंधाचल, देवीपाटन, नैमिषारण्य, कुशीनगर, सारनाथ, चित्रकूट पर ध्यान देने से पर्यटकों में यहां जाने की उमंग भी पैदा हो रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

अमूल की तरह सांची बनेगा ब्रांड

पांच सेक्टर्स में सहयोग करेगा अमूल

मप्र स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन सबसे पहले दूध के संकलन के लिए गांव-गांव में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन करेगा। इनका गठन गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की मदद से किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 10 हजार दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 25 हजार की जाएगी। एक समिति के गठन पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे। दूध संकलन से लेकर अन्य उत्पादों के निर्माण तक गुणवत्ता पर पूरा फोकस किया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अमूल की तरह मानक निर्धारित किए जाएंगे। दुग्ध संघ के कर्मचारियों की नियुक्ति और क्षमता निर्माण गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के सहयोग से किया जाएगा। मप्र स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन के चुनाव प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। गुजरात में प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर फेडरेशन के निर्धारित समय पर चुनाव होते हैं। जबकि मप्र में फेडरेशन के चुनाव नहीं कराए जाते। प्रशासनिक अधिकारियों को ही फेडरेशन में प्रशासक बनाकर बैठा दिया जाता है। दुग्ध सहकारी समिति स्तर से दुग्ध विक्रय तक की समस्त गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।

गुजरात के अमूल की तर्ज पर मप्र के सांची का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सांची डेयरी प्लांटों को भी अपग्रेड किया जाएगा और प्रदेश में होने वाले दुग्ध उत्पादन और दूध से तैयार होने वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहमदाबाद में मप्र के दूध उत्पादकों से दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए, सांची एवं अमूल की संयुक्त सहभागिता की संभावनाओं पर विचार करने हेतु विस्तृत बैठक में भाग लिया था। बैठक में मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादकों के हित में एवं सहकारिता प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, विपणन आदि के संबंध में मप्र एवं गुजरात के सहकारी दुग्ध महासंघों एवं दुग्ध संघों की संयुक्त सहभागिता का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए थे। दुग्ध उत्पादकों के हित में गुजरात और मप्र संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। मप्र के दूध उत्पादकों से दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए सांची और अमूल की संयुक्त सहभागिता की संभावनाओं पर विचार करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। अब डॉ. मोहन यादव सरकार ने मप्र स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन के ब्रांड सांची का बड़े स्तर पर प्रदेश में विस्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है।

सांची का विस्तार गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के ब्रांड अमूल की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने, दूध खरीदी पर दूध उत्पादक किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। इस संबंध में मप्र स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच उज्जैन में होने जा रही इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन होगा। इन्वेस्टर्स समिट एक और दो जून को उज्जैन में आयोजित की जाएगी। अमूल पांच सेक्टर्स में सांची का सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही डॉ. मोहन यादव का फोकस प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, अत्याधिक दूध की मात्रा को संकलित करने और दूध उत्पादकों को दूध के सही दाम देने पर है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉ. यादव पिछले महीने अहमदाबाद में गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि गुजरात के मिल्क फेडरेशन के सहयोग से सांची ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास दो विकल्प थे। पहला, सांची ब्रांड को पूरी तरह से अमूल टेकओवर कर ले। दूध के संकलन से लेकर उत्पादों का निर्माण व उनकी बिक्री और प्रबंधन का काम अमूल संभाले। इसके बदले वह सरकार को एक निश्चित लाभांश दे। दूसरा, अमूल के मार्गदर्शन में सांची ब्रांड का विस्तार किया जाए। अमूल बाहर सांची की मदद करे, प्रबंधन में उसका कोई दखल नहीं होगा। मप्र के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कई दौर की चर्चा के बाद दूसरा विकल्प चुना। अमूल सिर्फ सांची का मार्गदर्शन करेगा, प्रबंधन आदि में उसका कोई दखल नहीं होगा। पशुपालन के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर निराश्रित गौवंश के संरक्षण को लेकर कार्ययोजना बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने 25 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यशाला आयोजित करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इस दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के मद्देनजर कार्यशाला की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब यह कार्यशाला 6 मार्च को आयोजित की जाएगी।

सांची के प्रबंध निदेशक सतीश कुमार एस का कहना है कि नियमों के मुताबिक हम अतिरिक्त दूध दूसरी सहकारी समितियों को बेच सकते हैं। फिलहाल अमूल प्रदेश के दूध उत्पादकों की प्रस्तावित सहकारी समितियों से दूध की खरीद कर रहा है। हमारा प्रयास है कि अमूल यह दूध हमारे जरिये खरीदे। इससे एक ओर सहकारिता की भावना को मजबूती मिलेगी वहीं दूसरी ओर दोनों के प्रतिस्पर्धा की स्थिति टालने और सहयोग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मप्र के उज्जैन में अमूल का एक संयंत्र है जबकि दो अन्य स्थानों पर वह सहयोगी उपक्रमों के माध्यम से दूध की पैकिंग करता है। डेयरी उद्योग के सूत्रों का कहना है कि अमूल असंगठित क्षेत्र के दूध उत्पादकों से सांची की सहकारी समितियों की तुलना में अधिक कीमत देकर दूध की खरीद कर रहा है।

● **बृजेश साहू**

चुनावी बॉन्ड पर सर्वोच्च न्यायालय भले ही रोक लगा दे, गैर भाजपा दल भाजपा की चाहे जितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन यह तय है कि चुनावी रण के खर्च के लिए धन जुटाने की कोई और राह जरूर खोज ली जाएगी। भारत ने अमेरिका-ब्रिटेन का पूंजीवादी उदारीकरण अपना लिया तो वहां के राजनीतिक दलों को मिलने वाली दान संस्कृति भारत में प्रभाव क्यों नहीं जमाती?

राजनीतिक दलों को चंदा

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में विवादास्पद चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। यह बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों के लिए धन का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। इस योजना ने 2018 से राजनीतिक दलों के खजाने में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। लाभार्थियों में, सत्तारूढ़ भाजपा पहले नंबर पर रही है। जिसे लगभग 55 फीसदी का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। यह लगभग 6,565 करोड़ रुपए आंकी गई है। चुनाव आयोग और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। यह बॉन्ड, गुमनाम दान की अनुमति देते हैं। राजनीतिक फंडिंग का एक प्रमुख घटक रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय दल वित्तीय सहायता के लिए इन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भाजपा के लिए, चुनावी बॉन्ड उसकी कुल आय का आधे से अधिक हिस्सा है, जो राजनीतिक अभियानों को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देता है।

पांच साल पहले जिस चुनावी बॉन्ड को चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने और चुनावों में कालाधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए उस पर रोक लगा दी है। दरअसल चुनावी बॉन्ड के विरोधियों को उसे लेकर सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दान देने वाले लोगों के नाम का खुलासा नहीं हो रहा था। चुनावी बॉन्ड की अधिसूचना इसके लिए दानदाता को अपनी गोपनीयता की सहूलियत देती थी। चुनावी बॉन्ड देने वाले का नाम सूचना के अधिकार के दायरे से भी बाहर था। ऐसे में आरोप लगता था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले दरअसल बॉन्ड के रूप में रिश्वत दे रहे हैं और अपने कारोबारी या औद्योगिक हितों के लिहाज से बदले में सत्ताधारी दल से पसंदीदा नीतियां बनवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद **चुनावी बॉन्ड विरोधियों** का यह कहना कि अब पता चल पाएगा कि बॉन्ड के जरिए दान देने वाले लोग सचमुच दान दे रहे थे या फिर अपने हितों की रक्षा की भी मांग कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने योजना को असंवैधानिक बताया

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस तरह की फंडिंग के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है। कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला और राजनीति में तथाकथित काले धन पर अंकुश लगाने में चुनावी बॉन्ड की प्रभावकारिता के बारे में आपत्ति व्यक्त की। चुनावी बॉन्ड बिक्री के 28वें चरण में तेलंगाना का हैदराबाद अव्वल रहा, 377 करोड़ की बिक्री हुई।

गांधीजी ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम लोगों से चंदा लेने की शुरुआत की। हालांकि उस दौर में भी बिड़ला और बजाज जैसे औद्योगिक घराने कांग्रेस के बड़े दानदाता थे। लेकिन आम लोगों से चंदा लेने के पीछे भावना यह थी कि लोग इसके जरिए आंदोलन से तो जुड़ेंगे ही, उनका नैतिक दबाव आंदोलन कर रही कांग्रेस पर भी रहेगा। इसलिए वह लोकविरोधी फैसले नहीं ले पाएगी आजादी के बाद के दिनों में चाहे समाजवादी धारा के दल हों या जनसंघ या फिर वामपंथी, सब क्राउड फंडिंग या आम लोगों के जरिए ही धन जुटाते थे। लेकिन जैसे-जैसे भारत में औद्योगीकरण बढ़ता गया, औद्योगिक घराने भी चुनावी चंदा देने में आगे रहने लगे। निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी दलों को ही हुआ। एक दौर तक देश और राज्यों की सत्ता के लिए अपरिहार्य बनी रही कांग्रेस को इसीलिए सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलता रहा।

चुनावी बॉन्ड को लेकर जारी घमासान के बीच पता चला है कि इसके जरिए सबसे ज्यादा दान भाजपा को मिला है। भाजपा को सबसे ज्यादा धन मिलना आजादी के बाद से ही जारी परिपाटी का विस्तार कहा जा सकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक विगत पांच वर्षों में चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा 6,566 करोड़ का दान भाजपा को मिला है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 1,123 करोड़ रुपए का दान मिला। तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 1093 करोड़ रुपए की रकम मिली। 774 करोड़ रुपए के दान के साथ इस सूची में बीजू जनता दल चौथे नंबर पर है। जबकि पांचवे नंबर पर डीएमके है, जिसे 617 करोड़ रुपए मिले हैं। जाहिर है कि जिसके पास जितनी सत्ता है, उसी अनुपात में उसे चंदा मिला है। इसमें दो राय नहीं है कि मौजूदा चुनावी परिदृश्य में राजनीति शाहखर्ची का पेशा हो गया है। अकूत धन के बिना चुनाव लड़ना और राजनीतिक दल चलाना आसान नहीं है। शायद इसीलिए अब चुनावी प्रचार अभियान के लिए मीडिया ने कारपोरेट बमबारी का विश्लेषण दिया है। जाहिर है कि यह खर्च कारोबारी और औद्योगिक घरानों से ही आ सकता है। आम जनता से मिलने वाले चंदे या दान से राजनीति करना आज के दौर में मुश्किल है। यही वजह है कि चुनावों में काले धन का इस्तेमाल बढ़ा है।

चुनाव आयोग की तमाम सख्ती के बावजूद अब भी चुनावों में काले धन का भरपूर इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि जो चुनावी चंदा देगा, वह अपने हित की बात तो करेगा ही। चुनावी बॉन्ड

को खारिज किए जाने के बाद गैर भाजपा दलों ने भाजपा को कटघरे में खड़े करने की कोशिश जरूर की है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके हमला बोला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके हाथ पाकसाफ हैं? सवाल यह भी है कि क्या वे अगर भाजपा की तरह प्रभावी होते और सत्ता में उनकी हनक होती तो क्या वे आम लोगों के चंदे के आधार पर ही अपनी राजनीति करते? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। बेशक चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह की राजनीति आज के दौर में हो रही है, जिस तरह से अर्थ तंत्र का बोलबाला बढ़ा है, चुनावी बॉन्ड ना सही किसी और रूप में धन तो राजनीति की दुनिया में आएगा ही।

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है चुनावी बांड? चुनावी बॉन्ड साल में चार बार यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। इसे जारी करने का अधिकार देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही है। स्टेट बैंक अपनी चुनी हुई 29 शाखाओं के जरिए इसे जारी करता है जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, पटना, रांची, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरू स्थित शाखाओं में ही जाकर इसे खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड को खरीदने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29ए के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को ही है। चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए राजनीतिक दलों के लिए एक और शर्त है। वह शर्त है कि उन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान कम से कम एक फीसदी वोट हासिल किए हों।

यह बॉन्ड खास तरह से काम करता है। चुनावी बॉन्ड जिन महीनों में जारी होता है, उसके जारी होने के दस दिनों के भीतर कोई कॉरपोरेट, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इसे खरीद सकता है। इन बॉन्ड की वैधता पंद्रह दिनों की होती है। ये बॉन्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ मूल्य के होते हैं। बॉन्ड को

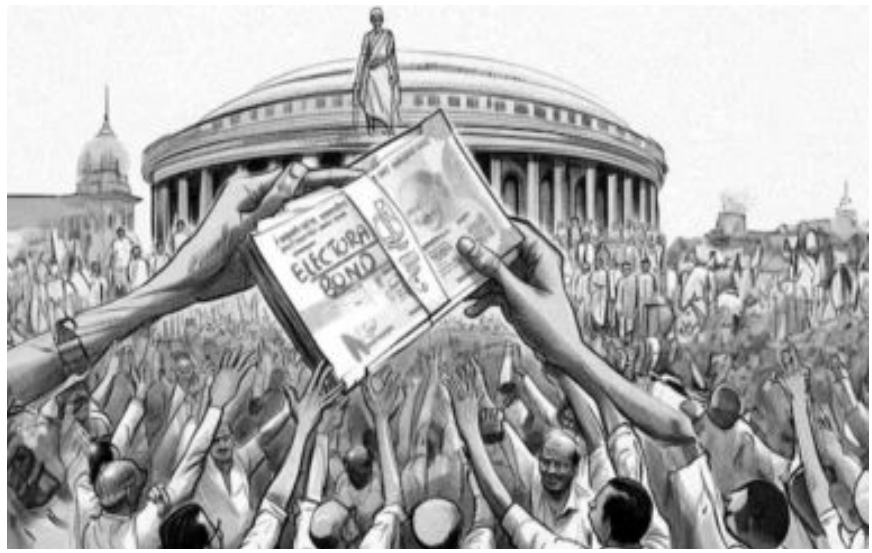

नगद नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए खरीदने वाले को अपना केवाईसी भी करानी होती है। अक्सर चुनावों की फंडिंग में अवैध धन के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। इसे ही सफेद बनाने के लिए साल 2017 में मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने का फैसला किया था। लेकिन इस योजना को 14 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव सुधारों की दिशा में काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनौती दी थी।

एडीआर की इस याचिका पर तीन अक्टूबर 2017 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इसी दिन जया ठाकुर और सीपीआईएम ने भी इस याचिका में खुद को शामिल करने की अर्जी लगाई। इस बीच 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इस योजना को अधिसूचित करके लागू कर दिया। शुरू में बॉन्ड की बिक्री के लिए 70 दिनों की मियाद रखी गई थी, जिसे 7 नवंबर 2022 को बढ़ाकर 85 दिन कर दिया गया। इस बीच 16 अक्टूबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सुनवाई के लिए भेजा। इसके पंद्रह दिन बाद पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। लगातार तीन दिनों की सुनवाई के बाद दो नवंबर 2023 को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 15 फरवरी 2014 को अपना फैसला सुनाया। फैसले में चुनावी बॉन्ड को सर्वोच्च अदालत ने असंवैधानिक घोषित करते हुए उस पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने भी इस योजना की खामियों को गिनवाते हुए कहा है कि इस योजना के जरिए राजनीति और धन के बीच सांठगांठ को बढ़ावा मिलता है।

देखने की बात यह है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में जिस तरह जीवन के हर क्षेत्र पर पैसे का बोलबाला बढ़ा है, उसकी वजह से पैसे के राजनीतिक इस्तेमाल और राजनीति पर पैसे का प्रभाव जरूरी बुराई बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को देखिए। वहां ताकतवर उम्मीदवार वही माना जाता है, जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। चंदा वहां आम वोटर और समर्थक भी देते हैं, लेकिन चंदे का बड़ा हिस्सा कारपोरेट घराने ही देते हैं। जिसे ज्यादा पैसा मिलता है, उसे ही चुनावी दौड़ में आगे माना जाता है। इसके उलट इस प्रक्रिया को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो जीत रहा होता है, उसे ही सबसे ज्यादा दान मिलता है।

● **सुनील सिंह**

राजनीतिक दलों को कितना मिला

चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद से, भाजपा की आय में वृद्धि हुई है और यह अपने प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पछाड़कर भारत की सबसे धनी पार्टी बन गई है। जिसकी किस्मत में कुछ सालों को छोड़कर गिरावट देखी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में चुनावी बॉन्ड आने के बाद भाजपा की आय दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 1,027 करोड़ रुपए से 2,410 करोड़ रुपए हो गई, जबकि कांग्रेस की आय भी 199 करोड़ रुपए से बढ़कर 918 करोड़ रुपए हो गई। वित्तवर्ष 2021-22 में भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलने वाला फंड बढ़कर 1,033 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कांग्रेस को मिलने वाला फंड 236 करोड़ रुपए से घट गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, भाजपा की कुल आय 2,360 करोड़ रुपए थी, जिसमें लगभग 1,300 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से आए थे। इसके विपरीत, कांग्रेस की कुल आय घटकर 452 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें चुनावी बॉन्ड से 171 करोड़ रुपए शामिल थे। पिछले वित्तीय वर्ष में अन्य दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अलग-अलग राशि प्राप्त हुई। टीएमसी को 325 करोड़ रुपए, बीआरएस को 529 करोड़ रुपए, डीएमके को 185 करोड़ रुपए, बीजेडी को 152 करोड़ रुपए और टीडीपी को 34 करोड़ रुपए मिले। हालांकि, इस अवधि के दौरान समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई योगदान नहीं मिला। चुनावी बॉन्ड में लगभग 50 फीसदी धनराशि कॉरपोरेट्स से आती है, जबकि बाकी अन्य स्रोतों से आती है।

पीएम आवास बना फांस

चार साल से होम लोन की किस्त और मकान का किराया दोनों भर रहा हूं। वेतन का 70 फीसदी हिस्सा केवल इसी में जा रहा है। बच्चों की छोटी-छोटी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाता तो शर्मिंदा महसूस करता हूं। मप्र टूरिज्म विभाग में काम करने वाले राहुल तल्खी ने इस तरह अपना दर्द बयां किया। राहुल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भोपाल के 12 नंबर योजना में फ्लैट बुक किया था। उस समय नगर निगम अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि एक साल में फ्लैट का पजेशन मिल जाएगा। राहुल ने बैंक से लोन लेकर 20 लाख रुपए नगर निगम को दिए। 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, न तो बिल्डिंग बनी ना ही निगम के अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि कब तक मकान का पजेशन मिलेगा।

राहुल ऐसे अकेले नहीं हैं। ऐसी कहानी मप्र के 40 शहरों में पीएम आवास योजना (शहरी) में मकान बुक कराने वाले हजारों लोगों की है। इन लोगों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लॉन्च की थी। मकसद ये था कि शहरों में सभी के पास मकान हो, लेकिन मप्र में निगम के ठेकेदारों व निगम अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को अधर में लटका दिया। जब पीड़ित परिवारों से बात की तो उनका दर्द फूट पड़ा। उनका कहना था कि अपने मकान का सपना पूरा करने के लिए बैंक से 20 से 25 लाख का लोन लेकर निगम में जमा कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने से अब मकान का किराया भी चुका रहे हैं और हर माह 15 से 20 हजार रुपए की बैंक को किस्त भी दे रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इस दोहरे खर्च में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उनके लिए घर चलाना भी मुश्किल साबित हो रहा है।

भोपाल की रहने वाली विजय लक्ष्मी पटौदिया ने इस योजना में अपनी बेटी के लिए 3 बीएचके फ्लैट बुक कराया था। उनकी बेटी दिल्ली में रहती है और वह भोपाल आना चाहती है। पटौदिया कहती हैं कि नगर निगम ने एक साल में प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा किया था। इसके लिए हमने बैंक से लोन लिया है। बैंक अधिकारी मकान की रजिस्ट्री करवाने का दबाव बना रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि रजिस्ट्री जमा नहीं की तो लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब उन्हें कौन बताए कि नगर निगम ने फ्लैट ही नहीं बनाया तो रजिस्ट्री कहां से होगी। लोकेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं, 2017 में नगर निगम ने बड़े-बड़े दावे कर फ्लैट्स की बुकिंग शुरू की थी। 2018 में मैंने 12 नंबर प्रोजेक्ट में आवास बुक कराया था। उस वक्त 18 माह में प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा किया था, लेकिन 6 साल बाद भी आवास कब तक बनेंगे, ये खुद निगम अधिकारी नहीं बता पा रहे। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो निगम ने ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर उसका टेंडर निरस्त कर दिया था, अब नई कंपनी को टेंडर दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी दिसंबर तक काम खत्म करने का वादा किया जा रहा है। मैं पिछले 6 साल से मकान का लोन और घर का किराया दोनों चुका रहा हूं।

नगर निगम के 40 शहरों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर शहर में आवासों की क्वालिटी को लेकर हितग्राही लगातार आपत्ति जताते रहे हैं। राहुल नगर में आवास लेने वाले मितेश गीते बताते हैं, निगम ने कहा था कि पार्किंग, गार्डन, सीसीटीवी सर्विलांस, कम्युनिटी हॉल और रेरा के नियमानुसार मल्टी का मेंटनेंस भी होगा। अलॉटमेंट के पहले ही 6 माह का मेंटेनेंस की राशि जमा करा ली गई, लेकिन मकान का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा। नई मल्टी में सीपेज की भी समस्या है। पूरे प्रदेश में सबसे बुरे हाल जबलपुर के हैं। यहां 3984 मकानों की बुकिंग हुई, लेकिन अब तक सिर्फ 119 लोगों को ही पजेशन मिल पाया है। इंदौर में 12448 में सिर्फ 3700 और भोपाल में 7755 मकानों की बुकिंग में सिर्फ 2521 मकानों के पजेशन हो पाए हैं। जिन कॉन्ट्रैक्टर को निर्माण का जिम्मा दिया गया था, उनके काम की सुस्त गति को देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब फिर अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए नई कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर 2024 तक अधूरे मकानों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। वजह ये है कि पहले भी सरकार कई दफा डेडलाइन बढ़ा चुकी है।

प्रदेश में प्रोजेक्ट पिछड़े तो इसकी समयसीमा बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दी गई। कई निकायों के सामने इस समयसीमा में भी इन प्रोजेक्ट को पूरा करना बड़ी चुनौती है। भोपाल के तीन, विदिशा का एक, इटारसी का एक और टीकमगढ़ का एक प्रोजेक्ट कई सालों से अधूरा था, ठेकेदार इन्हें समय पर बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे तो निगमों ने इन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर इन्हें हटा दिया। अब नए कंपनी के माध्यम से इन प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाएगा। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन के चुनाव भी एक बड़ी वजह रही कि लोगों ने यहां फ्लैट बुक कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। महापौर बनने से पहले भी मैं देख रहा था कि मटेरियल के दाम में बढ़ोतरी होने से ठेकेदार काम से हाथ खींच रहे थे। हम लगातार बैठक कर इन प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

● **लोकेश शर्मा**

40 शहरों में चल रही योजना

40 शहरों में वन-बीएचके, टू-बीएचके और थ्री-बीएचके फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। शहरी गरीबों को वन बीएचके फ्लैट सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकायों में एमआईजी-एलआईजी फ्लैट प्रोजेक्ट से फंड जुटाने की योजना बनाई गई। इसके पीछे मंशा थी कि इन प्रोजेक्ट में फ्लैट बिकने के बाद जो बचत होगी, उससे गरीबों को सस्ते आवास दे दिए जाएंगे। लेकिन गरीबों के आवास की बुकिंग के पास राशि नहीं दी तो एलआईजी-एमआईजी जैसे प्रोजेक्ट में फ्लैट की संख्या के हिसाब से बुकिंग नहीं आई। इंदौर जैसे शहर में 50 प्रतिशत तो जबलपुर जैसे शहर में 10 से 15 प्रतिशत ही बुकिंग मिली। प्रोजेक्ट में बुकिंग के पास लोग समय पर पैसा जमा नहीं कर पाए। इससे नगरीय निकायों के सामने ठेकेदारों को भुगतान का संकट खड़ा हो गया। इससे काम की रफ्तार भी धीमी हो गई।

वन विभाग के दागियों पर मेहरबानी

जंगल महकमे के शीर्ष अधिकारी कुछ चहेते अफसरों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। शीर्ष अधिकारी गंभीर वित्तीय मामले में घिरे आईएफएस अधिकारियों को बचाने के लिए आरोप पत्र जारी करने के बजाय शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। जिनके खिलाफ आरोप पत्र जारी भी कर दिए गए हैं, उनके विरूद्ध आगे की कार्यवाही पेंडिंग कर दी जा रही है। विभाग के शीर्ष अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण आरोपित अधिकारी धीरे-धीरे रिटायर भी होते जा रहे हैं। विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सद्भावना दिखाते हुए पेंशन भी स्वीकृत कर रहा है। मसलन, एम काली दुर्रई, देवेंद्र कुमार पालीवाल, प्रभात कुमार वर्मा जांच कार्यवाही के लंबित रहते हुए सेवानिवृत्त हो गए और अब उनके समस्त देयकों के भुगतान करने पर उदारता बरती जा रही है। दागी अफसरों को बचाने के लिए शीर्ष अधिकारी क्यों उदारता बरत रहे हैं, शोध का विषय है।

खंडवा सर्किल में पदस्थ सीसीएफ आरपी राय के खिलाफ 10 जून 2019 को आरोप पत्र जारी हुआ था। आरोप था कि वन मंडल इंदौर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चोरल में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई थी। जांच के दौरान राय अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहे। इसके कारण 6 लाख 93 हजार 361 रुपए की राजस्व हानि हुई थी। अभी इनसे वसूली नहीं हुई है। मामला विभाग में ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। राय गत वर्ष मई महीने में सेवानिवृत्त हो गए। यही नहीं, विभागीय मंत्री की विशेष कृपा होने के कारण इनसे 6 लाख 93 हजार की वसूली नहीं हो पाई। बालाघाट सर्किल में पदस्थ सीसीएफ एपीएस सेंगर के खिलाफ 24 अगस्त 2022 को आरोप पत्र जारी हुआ। मामला तब का है, जब वे टीकमगढ़ के डीएफओ हुआ करते थे। इन पर आरोप है कि भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया। खरीदी में गड़बड़ी हुई। इनके खिलाफ आरोपपत्र भी बन गया परंतु प्रशासन-1 शाखा ने उदारता दिखाते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर उन्हें बालाघाट सर्किल में प्राइम पोस्टिंग दे दी गई है। दुर्भाग्य जनक पहलू यह है कि विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत नहीं कराया है। यही नहीं, बल्कि सेंगर को बालाघाट सर्किल की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई।

1996 बैच के आईएफएस अधिकारी एम काली दुर्रई प्रतिनियुक्ति पर हॉर्टिकल्चर में पदस्थ रहे। यहां पदस्थ रहते हुए दुर्रई ने किसानों की सब्सिडी देने के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। इसके चलते उन्हें कमिश्नर हॉर्टिकल्चर पद से हटाया गया। मूल विभाग वन विभाग में लौटते ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के जांच अफसर सीके पाटिल को जांच के लिए 2 साल का पर्याप्त समय मिलने के बाद भी विभागीय जांच कम्प्लीट नहीं कर पाए और वे रिटायर हो गए। राजनीतिक दबाव के चलते विभाग के अफसर उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही नहीं कर पाए। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले देयकों का भुगतान भी उदारता से किया जा रहा है।

डीके पालीवाल सीसीएफ शिवपुरी के पद से रिटायर हुए हैं। इनके पेंशन के भुगतान पर आपत्ति की गई है, क्योंकि धार और फिर गुना डीएफओ पद रहते हुए आर्थिक गड़बड़ी कर शासन को नुकसान पहुंचाया है। धार में पदस्थ रहते हुए पालीवाल ने एक रेंजर का समयमान वेतनमान का फिक्सेशन अधिक कर दिया। जब मामला संज्ञान में आया, तब तक पालीवाल वहां से स्थानांतरित हो गए थे। विभाग ने अतिरिक्त भुगतान के लिए राशि वसूलने के नोटिस सेवानिवृत्त रेंजर को भेजा तो कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला देते हुए फिक्सेशन करने वाले अफसर पालीवाल से 3,00,000 की वसूली करने के आदेश दिए। इसी प्रकार गुना में कैंपा फंड की राशि से गड़बड़झाला करने का भी आरोप है। इनके खिलाफ पूर्व एसीएस वन अशोक वर्णवाल ने आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। वर्णवाल के निर्देश पर विभाग ने उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया किंतु बड़े अफसरों के चहेते होने की वजह से आरोप-पत्र को शोकॉज नोटिस परिवर्तित कर दिया गया है। बजट शाखा ने उनके पेंशन जारी करने पर आपत्ति लगाई है किंतु शीर्ष अफसरों ने शोकॉज नोटिस जारी कर उनके पेंशन और समस्त देयकों के भुगतान के रास्ते प्रशस्त कर दिए।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

वर्मा हो गए सेवानिवृत्त

2001 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रभात कुमार वर्मा जनवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं। वे जब 2020 में वन विकास निगम में पदस्थ थे तब आर्थिक गड़बड़ियों के चलते उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया। यही नहीं, विभाग ने 4 जनवरी 2022 को वन विकास निगम के एमडी को पत्र लिखकर गड़बड़ियों से संबंधित प्रचलित नस्ती उपलब्ध कराने के निर्देश दिए किंतु नस्ती उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनके मामले में निर्णय नहीं हो सका। वे सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। जांच लंबित रहते हुए उनके देयकों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू है। वहीं छिंदवाड़ा पूर्व में पदस्थ डीएफओ बृजेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ 21 जुलाई 2022 को नियम 10 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था। इन पर आरोप है कि स्थानांतरण नीति के विरूद्ध जाकर कर्मचारियों के तबादले किए। आरोप पत्र का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। भोपाल मुख्यालय में पदस्थ भारत सिंह बघेल को आरोप पत्र 22 मई 2006 को जारी किया गया था। बघेल ने अपने प्रभाव अवधि के दौरान पूर्व लांजी क्षेत्र में प्रभार अवधि में राहत कार्य अंतर्गत कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की थी। इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर मामला संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। शासन को संघ लोक सेवा आयोग के उत्तर की अपेक्षा है। बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले में गैर वनभूमि और बिगड़े वन में पौधारोपण कराने में करोड़ों के वनीकरण क्षतिपूर्ति घोटाले में शामिल आईएफएस नवीन गर्ग को डीएफओ दक्षिण सागर (सामान्य) वनमंडल से मप्र ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है।

चैटिंग की आड़ में चीटिंग का खेल

देश के युवाओं में ऑनलाइन डेटिंग का चस्का बढ़ा है। इस मामले में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। इसी आदत के कारण वे रोमांस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। डेटिंग स्कैम को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। एक्सपोजर मैनेजमेंट कंपनी टेनेबल की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले एक साल में लगभग दो-तिहाई (66 प्रतिशत) भारतीय वयस्क ऑनलाइन डेटिंग या रोमांस स्कैम का शिकार हुए हैं। इनमें से 81 प्रतिशत को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जितनी जानकारी वे अपने शोध के दौरान जुटा पाए, उसके अनुसार ऐसी धोखाधड़ी के चलते होने वाला यह नुकसान करीब 1.3 करोड़ डॉलर था। लेकिन, वे यह भी मानते हैं कि यह एक सतही अनुमान है। वास्तविक रकम इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है।

इसी से मिलते-जुलते आंकड़े पिछले साल भी आए थे। उनमें भी यही बताया गया था कि भारत के 66 प्रतिशत वयस्क, ऑनलाइन डेटिंग या रोमांस स्कैम का शिकार बन चुके हैं। लेकिन, तब पैटर्न अलग था। पिछले साल, इस तरह की ठगी में बहुत ज्यादा पैंतरेबाजी नहीं थी, बस दोस्ती और रोमांस का कॉकटेल तैयार किया जाता और शिकार को पिला दिया जाता था। वह या तो भावनाओं के बहाव में, या फिर लालच में फंस जाता और ठगा जाता। बीते साल, इन शिकारों की जितनी रकम स्कैमर्स की जेब में गई, उसके हिसाब से हर व्यक्ति को औसतन 7,966 रुपए की चपत लगी। इस तरह के घोटालों में होता यह है कि स्कैमर मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर अपने प्रोफाइल में आकर्षक व्यक्तित्व वाले फोटो लगाकर, खुद को यूएस या यूके जैसे किसी देश में रहने वाले रईस कारोबारी या अधिकारी के रूप में पेश करते हैं और इन साइटों पर अपने लिए जीवन साथी तलाश रही, ज्यादातर तीस के पार वाली, महिलाओं को टारगेट करते हैं।

सामान्य बातचीत पहले दोस्ती में बदलती है और फिर रोमांस में। इसी बीच परदेसी पार्टनर उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है। प्रियतम के पहले उपहार का इंतजार करती प्रेयसी को एक कॉल आता है। कॉलर बताता है कि वह कस्टम से बोल रहा है और उसके लिए एक गिफ्ट आया है। उसे गिफ्ट के लिए कस्टम ड्यूटी भरनी होगी। फिर टारगेट को एक बैंक नंबर देकर उसमें एक विषम रकम जमा करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि राउंड फिगर अमाउंट संदेह पैदा कर सकता है। अक्सर टारगेट को विक्टिम में बदलने में देर नहीं लगती। दूसरा तरीका स्कैमर यह आजमाता है कि वह टारगेट को भावनाओं में इतनी गहराई तक ले जाता है कि टारगेट उससे बहुत जुड़ाव महसूस करने लगता है। फिर एक दिन वह इमरजेंसी बताकर उससे एक बड़ी रकम उधार मांग लेता है और रकम मिलने के बाद शिकार से संबंध पूरी तरह तोड़ लेता है। तीसरे तरीके में उसे वह अपनी फर्म या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पार्टनर बनाने का प्रस्ताव रखता है और मोटे मुनाफे का सपना दिखाता है। हर टारगेट की भावनात्मक व आर्थिक स्थिति और रिश्ते की गहनता के आधार पर स्कैमर तय करते हैं कि किस पर कौन सा तरीका लागू होगा। अगर टारगेट ऐसे जाल में नहीं फंसता, तो फिर स्कैमर सीधे एक्सटॉर्शन पर उतर आता है और मांगी हुई रकम न देने पर उसकी फोटो और चैट को पब्लिश करने की धमकी देने लगता है। इस तरह के मामले इतने बढ़ गए थे कि पिछले साल अगस्त में सरकार को जनता के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ी कि वे इस तरह के स्कैम में न फंसें।

अब चूंकि ये तरीके बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए स्कैमर्स ने अपने पैटर्न को थोड़ा बदला है। बाकी सब तो पहले की तरह रहता है, लेकिन इन नए तरीकों में जो बुनियादी फर्क आए हैं, वे ये हैं कि एक तो इसमें मैट्रिमोनियल वेबसाइट की जगह टिंडर, बंबल जैसी डेटिंग साइट या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प जैसे एप्प का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरा इसमें अब सिर्फ भावुक महिलाओं को ही शिकार नहीं बनाया जाता, बल्कि हर वो स्त्री-पुरुष टारगेट हो सकता है, जो ऊबा हुआ है या अकेला है और ऑनलाइन प्यार की तलाश में है। जो शिकार बनाया जा रहा है उसका जेंडर हो सकता है, लेकिन स्कैमर का कोई जेंडर नहीं होता। हो सकता है कि हर प्रोफाइल के पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा हो। तीसरा सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि संभावित शिकार से दोस्ती या रोमांस करते हुए, उससे एकदम से या सीधे पैसा नहीं मांगा जाता। बल्कि उसे एक सुनहरे भविष्य का विश्वास दिलाया जाता है। इस तरह के घोटालों के शिकार बनने वालों में भोले-भाले, अल्पज्ञानी व्यक्ति नहीं, बल्कि काफी उच्च शिक्षित प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेसमैन, नेता आदि होते हैं।

● **राकेश ग्रोवर**

तेजी से बढ़ती दिखने वाली कीमतें

शिकार का भरोसा जीतने के लिए वे उसे कुछ कॉइन गिफ्ट देने में भी पीछे नहीं रहते। घोटाले में प्रदर्शित क्रिप्टो कॉइन और उनकी तेजी से बढ़ती दिखने वाली कीमतें दोनों ही फर्जी होते हैं। लेकिन, शिकार के पास संदेह करने की कोई वजह नहीं होती और वह अच्छी खासी रकम निवेश के रूप में दांव पर लगा देता है। एक बार उसके पास से पैसा निकलने की देर है, उसके बाद तो न उसे मुनाफा नजर आता है, न निवेश के लिए प्रेरित करने वाला हितैषी दोस्त। ऐसे स्कैमर्स का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। तमाम जागरूकता अभियानों और सुरक्षा कवचों के बावजूद, ये ठग हमेशा पात-पात ही साबित होते हैं। इसीलिए ठगे जाने वालों की संख्या और ठगी की रकम लगातार बढ़ती ही जा रही है। वर्ष 2019 में रोमांस स्कैम में लोगों ने 493 मिलियन डॉलर गंवाए, वहीं 2022 में यह रकम बढ़कर 1.3 बिलियन डॉलर हो चुकी है।

जलसंकट की आहट

देश में अभी गर्मी की दस्तक भले ही नहीं हुई है, लेकिन जल संकट की आहट शुरू हो गई है। जबकि गर्मी आने में अभी एक महीना बाकी है। आशंका जताई जा रही है कि देश के कई राज्यों में गर्मी में भयंकर जलसंकट हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जलवायु परिवर्तन से मानसून कमजोर होने के कारण दक्षिण भारत के राज्यों के साथ ही दिल्ल, मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में जलसंकट का सबसे अधिक असर पड़ेगा। दरअसल, इन राज्यों में पोखर, तालाब, छोटी नदियां और झीलें तेजी से सूख रही हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में मानसून और उस पर निर्भर जल संसाधनों पर बुरा असर पड़ा है। पूरे भारत में कई बड़ी नदियों के सूखने के साथ भारत को जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह का गंभीर जल संकट कभी नहीं देखा गया है।

भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि देश के पास सिर्फ 4 प्रतिशत जल संसाधन है। ये भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले देशों में से एक बनाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में गर्मियों के आते ही पानी भारत में सोने की तरह कीमती चीज बनती जा रही है। नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में भारतीय जल संकट का सामना करते हैं। अपनी पानी की जरूरतों के लिए भारत की अनियमित मानसून पर निर्भरता इस चुनौती को और बढ़ा रही है। इससे लाखों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में हैं। फिलहाल, 60 करोड़ भारतीयों पर गंभीर जल संकट मंडरा रहा है और पानी की कमी और उस तक पहुंचने में आने वाली मुश्किलों की वजह से हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2030 तक देश में पानी की मांग, उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 6 प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान है।

यदि पानी का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाले देशों की बात करें तो उसमें भी भारत शामिल है, जो कि हर साल 40,000 करोड़ क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी का उपभोग कर रहा है। जबकि हाल ही में एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस में भी जलसंकट का सबसे ज्यादा सामना कर रहे 17 देशों की लिस्ट में भारत को 13वां स्थान दिया है। जो देश में बढ़ते जलसंकट को दर्शाता है। वहीं नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2050 तक पानी की किल्लत और गुणवत्ता में आती गिरावट का सामना करने वाले इन नदी बेसिनों का यह आंकड़ा बढ़कर 3,061 पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नाइट्रोजन प्रदूषण और बढ़ते दबाव के चलते इन सबबेसिनों में या तो पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा और यदि होगा तो वो इतना दूषित होगा कि इंसानों और दूसरे जीवों के उपयोग के लायक नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि पानी की कमी और उसकी गुणवत्ता में आती गिरावट से वैश्विक स्तर पर 680 से 780 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, जो पिछले अनुमान से करीब 300 करोड़ ज्यादा है।

40,000 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी का उपभोग

यदि पानी का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाले देशों की बात करें तो उसमें भी भारत शामिल है, जो कि हर साल 40,000 करोड़ क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी का उपभोग कर रहा है। जबकि हाल ही में एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस में भी जलसंकट का सबसे ज्यादा सामना कर रहे 17 देशों की लिस्ट में भारत को 13वां स्थान दिया है। जो देश में बढ़ते जलसंकट को दर्शाता है। वहीं नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2050 तक पानी की किल्लत और गुणवत्ता में आती गिरावट का सामना करने वाले इन नदी बेसिनों का यह आंकड़ा बढ़कर 3,061 पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नाइट्रोजन प्रदूषण और बढ़ते दबाव के चलते इन सबबेसिनों में या तो पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा और यदि होगा तो वो इतना दूषित होगा कि इंसानों और दूसरे जीवों के उपयोग के लायक नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि पानी की कमी और उसकी गुणवत्ता में आती गिरावट से वैश्विक स्तर पर 680 से 780 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, जो पिछले अनुमान से करीब 300 करोड़ ज्यादा है। वैज्ञानिकों का अंदेशा है कि नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में कई उप-बेसिन पानी की भारी कमी का केंद्र बन सकते हैं।

एक नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते अगले 26 वर्षों में दुनियाभर में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। वैज्ञानिकों का अंदेशा है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर नदियों के एक तिहाई उप-बेसिनों को नाइट्रोजन प्रदूषण के चलते साफ पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि पानी की यह कमी और गुणवत्ता में आती यह गिरावट 2050 तक पहले की अपेक्षा 300 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकती है। आशंका है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण नदी स्रोत इंसानों और अन्य जीवों के लिए असुरक्षित हो जाएंगे। मतलब की दुनिया जो पहले ही जलसंकट के दौर से गुजर रही है, उसके सामने मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। बता दें कि अपने इस अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने वैश्चिक स्तर पर नदियों के 10 हजार से ज्यादा उप-बेसिनों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण के मुताबिक बेतहाशा बढ़ते नाइट्रोजन प्रदूषण ने न केवल पानी की कमी का सामना करने वाले नदी बेसिनों की संख्या में इजाफा किया है, साथ ही पानी की गुणवत्ता पर भी असर डाला है।

गौरतलब है कि नदियों के यह उप-बेसिन एक प्रकार की छोटी घाटियां होती हैं, जो स्वच्छ पानी का एक बड़ा स्रोत होती हैं। इन नदी घाटियों में बड़े पैमाने पर शहरी आबादी और आर्थिक गतिविधियां केंद्रित होती हैं। ऐसे में इनके जलमार्गों के दूषित होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक 2010 में वैश्विक स्तर पर करीब एक-चौथाई यानी 2,517 उप-बेसिन पानी की कमी और गुणवत्ता में आती गिरावट से जूझ रहे थे।

● **प्रवीण सक्सेना**

घड़ियाल-मगरमच्छ की जान पर खतरा

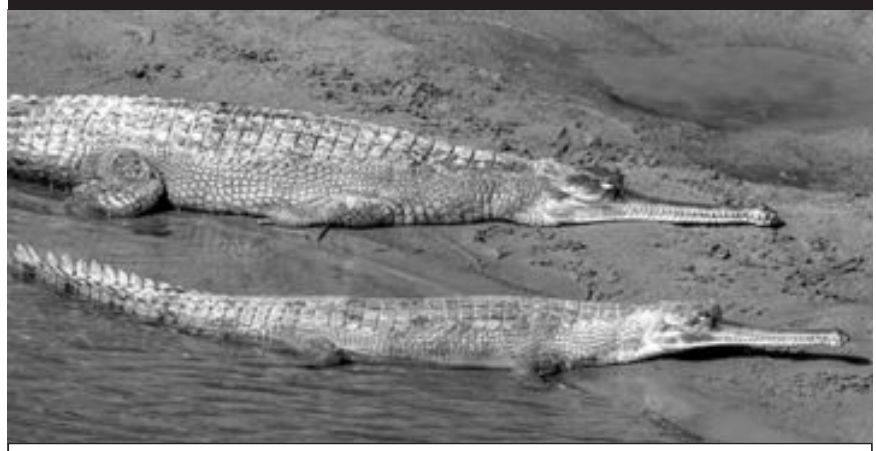

मप्र में रेड गोल्ड यानी लाल सोना... मतलब रेत का कारोबार करोड़ों का है। ये अवैध कारोबार न सिर्फ माफिया को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है बल्कि जलीय जीवों के लिए जानलेवा बन रहा है। मप्र में सोन नदी में प्रतिबंध के बावजूद निरंतर रेत का अवैध खनन हो रहा है। जिससे नदी में रहने वाले घड़ियालों, मगरमच्छों और कछुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है। ऐसे में अवैध खनन को रोकने में विफल रहा सीधी जिला प्रशासन अब सोन घड़ियाल अभयारण्य के कुछ क्षेत्र को डिनोटिफाई करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। तर्क है, यह कदम उस क्षेत्र में उठाया जा रहा है, जहां घड़ियाल या अन्य जलीय जीव नहीं हैं। रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचंद्र डाड का कहना है कि मुख्यमंत्री की मीटिंग में यह विषय उठा था। बताया गया है कि डिनोटिफाई का प्रस्ताव भेजा है।

गौरतलब है कि सोन घड़ियाल अभयारण्य प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत घड़ियाल संरक्षण व जनसंख्या वृद्धि हेतु स्थापित किया गया। सोन नदी का 161 किमी, 23 किमी बनास नदी व 26 किमी गोपद नदी का क्षेत्र मिलाकर कुल 210 किमी क्षेत्र को 1981 में अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। 43 साल पहले बने सोन अभयारण्य में रेत खनन का रास्ता बनाने के लिए घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुओं और पक्षियों के घर उजाड़ने की तैयारी चल रही है। सीधी जिले में प्रशासन ने सोन घड़ियाल अभयारण्य के कुछ क्षेत्र को डिनोटिफाई करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। तर्क है, यह कदम उस क्षेत्र में उठाया जा रहा है, जहां घड़ियाल या अन्य जलीय जीव नहीं हैं। सोन घड़ियाल अभयारण्य के अधीक्षक निकुंज पाण्डेय का कहना है कि हमने प्रस्ताव नहीं भेजा, एक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है। लोगों की रेत की जरूरतें पूरी करने के बाद संभव हुआ तो कुछ हिस्सा डिनोटिफाई हो सकता है। देखेंगे कि वन्य प्राणियों को नुकसान न हो।

जानकारों का कहना है कि इस इलाके में घड़ियालों को बसाने के ठोस प्रयास नहीं हुए। पन्ना टाइगर रिजर्व 2008 में बाघविहीन हो गया, तब इसे बसाने की कोशिश हुई और सफलता मिली। इस क्षेत्र में रेत खनन का रास्ता खोलना ठीक नहीं है। मामला सामने आया तो अफसर अब बगलें झांक रहे हैं। रिटायर्ड सीसीएफ एसपी तिवारी का कहना है कि ऐसा हुआ तो ईको सिस्टम खराब होगा। 2005 में मैं लखनऊ से घड़ियाल लाया था। अगले साल सोन घड़ियाल अभयारण्य के जोगदहा घाट पर 50-60 बच्चे पैदा हुए थे। वन्य प्राणियों को बचाना चाहिए। इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली रेत है। इस पर रेत कारोबारियों की पहले से नजर है। बताते हैं कि अभी 210 किमी का यह क्षेत्र खनन के लिए प्रतिबंधित है। कारोबारी सोन नदी के कुछ हिस्से से रेत निकाल रहे हैं, लेकिन यहां वे मनमुताबिक खनन नहीं कर पा रहे। सरकार की मंजूरी से कारोबारियों को रेत खनन की मंजूरी मिल जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर एमपी ताम्रकार की मानें तो घड़ियाल के रहवास उजाड़ने की बजाय बसाने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा करना पर्यावरण से खिलवाड़ है। सोन घड़ियाल अभयारण्य के जिम्मेदारों ने रिजर्व एरिया में घड़ियालों को बसाने के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया था। कड़े संघर्ष के बाद 2009 में बाघ बसाए। सरकार चाहती तो 2008 में इसे भी डिनोटिफाई कर देती, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण बाघों का संसार बसा।

चंबल में घड़ियालों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट आया है। इस साल चंबल नदी में नवंबर महीने से ही पानी कई जगहों पर 2 से 5 फीट तक रह गया है। बाढ़ न आने से किनारों की सारी रेत नदी के बीच में आ गई है। यानी इस साल घड़ियालों के पास कोई घर नहीं है। घड़ियालों को धूप सेकने और अंडे देने के लिए 1 से डेढ़ मीटर मोटी रेत की परत चाहिए होती है। लेकिन इस बार किनारों में पर दो से ढ़ाई फीट ही रेत है। इस स्थिति में घड़ियालों को अंडे देने में भी परेशानी आएगी। इस संकट को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग मुरैना ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से मदद मांगी है। वन विभाग की मानें तो चंबल में किसी भी तरह पानी छुड़वाना जरूरी हो गया है।

चंबल नदी में इस समय 1400 के करीब घड़ियाल हैं। 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब चंबल नदी नवंबर में ही सूखने लगी है। हर साल चंबल नदी में बारिश के दौरान जल स्तर 136 से 139 मीटर तक पहुंच जाता था। लेकिन इस साल यह जल स्तर 130 मीटर भी नहीं पहुंच पाया था। नदी में पानी की कमी और वेग कमजोर होने से किनारों की सारी रेत धीमे बहाव के कारण नदी के बीच के गड्ढ़ों में जमा हो गई है। हाल ही में नदी में हुए 65 किलोमीटर के सर्वे के दौरान यह बात वन विभाग को पता चली। नदी के बीच धार में इतनी रेत एकत्रित हो गई है कि यहां बोट चलना भी मुश्किल हो गई है। जबकि किनारे रेत से खाली दिखाई दे रहे हैं। नदी के पारिस्थितिक तंत्र में यह बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। क्योंकि फरवरी महीने में वन विभाग नदी में बोट के जरिए ही जलीय जीवों की गणना करता है। जबकि नवंबर महीने से ही नदी में बोट चलने लायक पानी नहीं है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

घड़ियालों को चाहिए इतनी रेत

चंबल अभयारण्य पर पिछले 30 सालों से शोध कर रहे विशेषज्ञ डॉ. ऋषिकेश शर्मा के मुताबिक घड़ियाल रेत में अंडे देते हैं। इसके लिए घड़ियाल 45 से 60 इंच तक गहरे गड्ढे खोदते हैं। धूप सेंकने के लिए घड़ियालों को डेढ़ मीटर ऊंचे रेत के टीले चाहिए। डॉ. शर्मा के अनुसार रेत भी कम है और पानी भी। ऐसे में घड़ियालों की नेस्टिंग साइड खराब होने का खतरा बढ़ गया है। मजबूरन घड़ियाल कम रेत या मिट्टी खोदकर अंडे देंगे। जिससे अंडों को उचित तापमान नहीं मिलेगा और अंडे खराब हो जाएंगे। पानी की कमी और किनारों पर रेत न आने से वन विभाग के होश उड़ गए हैं। वन विभाग ने डब्ल्यूआईआई को इस संकट से अवगत कराया है। इसके बाद डब्ल्यूआईआई नवंबर महीने में चंबल के जल स्तर की रीडिंग लेगा। इसके बाद तय होगा कि केंद्र सरकार को बताया जाए कि कोटा बैराज से चंबल में पानी छोड़ना आवश्यक है।

अवैध कालोनियों पर कैसे कसे लगाम...?

मप्र में साढ़े तीन हजार करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट अवैध

यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि मप्र के 50 फीसदी से ज्यादा सरकारी हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट अवैध हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सरकारी प्रोजेक्टों में बिक्री भी नियमों-प्रावधानों को ताक पर रख की जा रही है। यह मामला रेरा कानून से जुड़ा है। राजधानी का हाल यह है कि भोपाल नगर निगम के 16 प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनकी लागत भी डेढ़ हजार करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा अलग-अलग नगरीय निकायों में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए लागत के सरकारी प्रोजेक्ट भी अवैध है। दरअसल, इसका खुलासा भी रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के हाउसिंग प्रोजेक्ट की संख्या के आधार पर हुआ। रेरा में नगरीय प्रशासन के तहत आने वाले 50 फीसदी प्रोजेक्ट का पंजीयन ही नहीं है। मामले पर रेरा भी एक्शन की तैयारी में है। रेरा में सरकारी एजेंसियों की मनमानी को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। सूत्रों की मानें तो रेरा ने भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग से हाउसिंग प्रोजेक्ट का खाका मांगा है। बता दें कि रेरा कानून के तहत बिना पंजीयन सरकारी या निजी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अवैध की श्रेणी में आता है।

राजधानी में करीब ढाई साल पहले तत्कालीन संभागायुक्त के निर्देश पर शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में कट रही अवैध कालोनियों के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ था। बिना डायवर्सन व बिना अनुमति से अवैध कालोनी विकसित करके बेचने वालों के खिलाफ शहर के तमाम थानों में मामले दर्ज किए गए थे। नगर निगम प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने 292 सी मप्र नगर पालिका अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों पर सैकड़ों लोगों के खिलाफ शहर के मिसरोद, कोलार, रातीबड़, सूखी सेवानिया, खजूरी सड़क, बिलखिरिया, छोला मंदिर, अयोध्या नगर थाने में 150 से अधिक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से अब तक सिर्फ कालोनाइजरों से वसूली की गई, लेकिन एक पर भी एफआईआर नहीं की गई है।

बिना किसी शासकीय अनुमति के नगर निगम सीमा क्षेत्र में 92 अवैध कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इसका खुलासा नगर निगम और नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा कलेक्टर को सौंपी गई रिपोर्ट में हुआ है। इसमें पांच थाना क्षेत्र की कालोनियों को चिन्हित किया गया है। कालोनाइजर, बिल्डर और किसानों के द्वारा न तो टीएंडसीपी से नक्शा अनुमोदित कराया गया है और न ही कालोनी विकास की अनुमति ही ली गई है। तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने इन पर वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र को पत्र लिखा है। कलेक्टर ने पत्र में कहा है कि मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिका निगम द्वारा दी गई सूची अनुसार व्यक्तियों, संस्था, बिल्डर, कालोनाइजर द्वारा आम जनता को भ्रामक जानकारी एवं धोखा देकर भवन-भूखंड का विक्रय किया जा रहा है। थाना रातीबड़ में बरखेड़ी कलां में सुनीता गुप्ता, कमल सिंह, चमेली बाई, प्रेमचंद कौल, प्रभात जैन, रीना बंसल, रीना जैन, अंकिता सिंह, एमआर पंडित, सीमा श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश मारण, मांगीलाल, वेलसम्मा, निर्मला सराठे, अल्का ठाकुर, राजकुमार गौर, मोरीलाल, एएंड कंपनी पीयूष गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, सुषमा सक्सेना, राधाकृष्ण शर्मा, करण सिंह, ग्राम गौरा सुरेश मेनन, ग्राम खुदागंज नवाब खान, ग्राम बरखेड़ी खुर्द वंदना तिवारी, मोहन कुमार, बरखेड़ी कलां मुकेश गोयल, ग्राम गौरा यूनिट वेजय रियल्टर्स प्रालि डायरेक्टर अनिल विश्वकर्मा, बिशनखेड़ी दुर्गा श्रीवास्तव, गौरव सिंह चौहान, गगन कुमार सिंह, दुर्गा श्रीवास्तव, ग्राम गौरा मुंशीलाल, गजराज सिंह, नवाबजादा नादिर रसीद, राजकुमार मोटवानी, ग्राम बरखेड़ी खुर्द मदन गोपाल भावसार, योगिता चौरसिया, त्रिलोक सिंह, चंदनपुर विनोद शर्मा, ग्राम बरखेड़ी खुर्द जयप्रकाश गुप्ता, जितेंद्र रघुवंशी, उषा रघुवंशी, महेश सबरीकर, भास्कर दत्त, सेवनियां गौड एआईएम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स पार्टनर कैलाश मारण आदि बिना अनुमति अवैध कालोनियां खड़ी कर रहे हैं।

थाना ईंटखेड़ी में लांबाखेड़ा में राजमल पुत्र रामचरण, शाहवर हफीज खां, सुभाष यादव, विकार अजीम, दीवान सिंह, मो. लियाकत, अजीज खां, रामबदन प्रसाद वर्मा, रफतउल्ला खां, करन सिंह, राजाराम, मुन्नी देवी, चंद्रमोहन शर्मा, द्रौपदी बाई, मेसर्स रायल एसोसिएट मुमताज अहमत, मो. अशलम खां, कालूराम, मो. साहिद खान, अब्दुल हमीद, अभिषेक मालवीय शामिल हैं। इसी तरह थाना अयोध्या नगर में हथाईखेड़ा में उमा चौकसे, धर्मेंद्र कुशवाहा, रामरती चौकसे, डालचंद, संतोष पुत्र नंदराम, समीर मोहम्मद, खेजड़ा बरामद केएस पांडेय, सैयद अदनान, टीकाराम, कोलुआ कलां राजेश व मनीष चौकसे, नरेला शंकरी कमला बाई के द्वारा अवैध कालोनियों का निर्माण किया गया है। थाना निशातपुरा में ग्राम पलासी में अशोक कुमार, मशकूरू उल्लाह, विकास जैन, मुजफ्फर खान, ग्राम बड़वई में मनोज कुमार, राकेश कुमार शर्मा, अब्दुल जहीर बेग और नेवरी में अनिल नेमा के द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। वहीं, थाना छोला में ग्राम खेजड़ा बरामद सिराज व अन्य, मालीखेड़ी विनोद कुशवाहा, अजहर खान, कल्लू साहू, मनोज कुशवाहा, सुरेश लोधी, द्वारका पिता शंकरलाल, छोला कालूराम साहू द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। किसी भी शहर का सुनियोजित विकास करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है। लेकिन मप्र में शहरों का विकास तो धड़ाधड़ किया जा रहा है, लेकिन मास्टर प्लान रसूखदारों के कारण मंत्रालय में अटका हुआ है। इस कारण मप्र के शहरों का विकास बेतरतीब तो हो रहा है। दरअसल, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों का मास्टर प्लान अब तक तैयार नहीं हुआ है। जबकि इन शहरों में मेट्रो लाइन, सड़कों, नालियों और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो यहां के मास्टर प्लान की अवधि वर्ष 2005 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद 18 वर्ष में नया मास्टर प्लान अब तक नहीं बन पाया है। अमृत योजना के तहत वर्ष 2035 तक के लिए मप्र के 34 शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाना है। इंदौर और जबलपुर शहर का हाल यह है कि वहां भी बिना मास्टर प्लान के अनियोजित विकास हो रहा है। भोपाल की चूनाभट्टी कोलार रोड 6 लेन बनाने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन सड़क से लगे आवासीय क्षेत्रों में भवन निर्माण का फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) नहीं बढ़ाया गया है। चूनाभट्टी में अब भी एफएआर 0.75 निर्धारित है। घनी आबादी होने के बाद भी कम एफएआर होने के कारण भूमि का समुचित तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे निर्माण कार्य कम हो रहे हैं और शासन को राजस्व क्षति हो रही है। चूनाभट्टी के रहवासियों ने शासन से एफएआर बढ़ाने की मांग की है। मास्टर प्लान न बनने से यह समस्या आ रही है।

● **विकास दुबे**

क्या कांग्रेस लौट पाएगी सत्ता में ?

आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की धुरी रही कांग्रेस, आजादी के बाद अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी। एक वक्त था जब इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को केंद्र की सत्ता में पूरे 25 सालों तक कोई सीधी टक्कर देने वाला भी नहीं था। आज आलम ये है कि केवल 3 राज्यों की सत्ता में कांग्रेस की मौजूदगी है। वहीं भाजपा का परचम हर तरफ लहरा रहा है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि रोजाना किसी न किसी राज्य में पार्टी के नेता हाथ का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस फिर से मजबूती से खड़ी होकर सत्ता में लौट पाएगी?

● राजेंद्र आगाल

वर्तमान समय में कांग्रेस अपने सबसे बूरे दौर से गुजर रही है। लेकिन कांग्रेस टूटती-बिखरती रही है, पर कभी खत्म नहीं हुई। अपनी स्थापनाकाल से लेकर अभी तक कांग्रेस करीब 70 बार टूटी है, आगे भी ऐसा हो तो आश्चर्य की बात नहीं। करीब 50 नई पार्टियां इस संगठन से निकलकर बनीं। इनमें से कई निष्क्रिय हो गए तो कईयों का आईएनसी और जनता पार्टी में विलय हो गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन 1967 में हुआ जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम आईएनसी (आर) रखा। 1971 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इसका नाम आईएनसी कर दिया। इस समय कांग्रेस में टूट तो नहीं हो रही है, लेकिन नेताओं की भगदड़ मची हुई है। लोकसभा चुनाव की छाया में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जिस दिन कांग्रेस का कोई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल नहीं होता है। इन सबके बावजूद मजबूत भाजपा को अगर किसी की चुनौती से डर है तो वह है कांग्रेस। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी ?

देश में सबसे अधिक दिनों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस कभी लंबे समय तक विपक्ष में नहीं बैठी है। इस कारण वह विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। अपने शासनकाल के दौरान देश में मनमानी करने वाली कांग्रेस ने आपातकाल भी लगाया था, लेकिन आज वह ईडी, सीबीआई और आईटी के छापों को राजनीति से प्रेरित बताकर भाजपा को कोस रही है। ऐसे में कांग्रेस का ध्यान अपने संगठन को मजबूत करने से भटक गया है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि एक-एक कर राज्यों से कांग्रेस से सत्ता छिनती जा रही है और पार्टी के कद्दावर नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक पलायन कर रहे हैं।

1977 तक केवल कांग्रेस

आजादी के बाद 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 1977 तक देश पर केवल कांग्रेस का शासन था। इस साल हुए चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीन ली। हालांकि तीन साल के अंदर ही 1980 में कांग्रेस वापस गद्दी पर काबिज हो गई। 1989 में कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1991, 2004, 2009 में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता हासिल की। आजादी के बाद कांग्रेस कई बार विभाजित हुई। करीब 50 नई पार्टियां इस संगठन से निकलकर बनीं। इनमें से कई निष्क्रिय हो गए तो कईयों का आईएनसी और जनता पार्टी में विलय हो गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन 1967 में हुआ जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम आईएनसी (आर) रखा। 1971 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इसका नाम आईएनसी कर दिया।

कांग्रेस के आरंभिक इतिहास के दो-तीन तथ्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए। 1920 से पूर्व कांग्रेस के कद्दावर नेता तिलक थे। वे जीतें या हारें; और उनके विचार चाहे जो हों, कांग्रेस का मतलब तिलक था। 1920 से कांग्रेस गांधी की हो गई और वह तब तक रही, जब तक नेहरू प्रधानमंत्री नहीं हो गए। नेहरू के प्रधानमंत्री होने के बाद कांग्रेस का मतलब था नेहरू। जो नेहरू के साथ नहीं था, वह कांग्रेस में भी नहीं टिक सका। फिर इंदिरा गांधी का जमाना आया। दो बार इंदिरा को कांग्रेस से लगभग बहिष्कृत ही कर दिया गया। पहली दफा जुलाई 1970 में, जब उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव को उनकी ही पार्टी ने निरस्त कर दिया। (इंदिरा ने जगजीवन राम का प्रस्ताव दिया था, सिंडिकेट ने संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया)। दूसरी दफा 1978-79 में देवराज अर्स के नेतृत्व में कांग्रेस दो फाड़ हो गई। इन दोनों बार कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी। 1978-79 में तो कांग्रेस सत्ता में भी नहीं थी। इंदिरा गांधी मुकदमे, गिरफ्तारी और संसद की सदस्यता गंवाने जैसी कार्रवाईयों से परेशान-हाल थीं। लेकिन कांग्रेस वहां रही, जहां इंदिरा रहीं। इन सब का राज आखिर क्या है?

1990 के दशक पर अब एक नजर डालें। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। चुनाव के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस आलाकमान और प्रधानमंत्री थे। इनके नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र में नेहरूयुगीन मिश्रित व्यवस्था की सोच को हटाकर उदारवादी नीतियां अपनाई गईं। सालभर बाद अयोध्या में विवादित मस्जिद के ढांचे को चरमपंथियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में भाजपा की तो बदनामी हुई ही; कांग्रेस की भी चौतरफा बदनामी हुई। कहा जाता है, प्रधानमंत्री राव उस रोज दिन में तब तक सोते रहे, जब तक मस्जिद ध्वस्त नहीं कर दी गई। इन सबके कारण कांग्रेस कमजोर होती गई। 1991 तक 244 सीटें लाने वाली कांग्रेस 1996 और 1998 में 140 और 141 पर अटकी रह गई।

ऐसे में एक बार फिर एक करिश्माई नेता की बात उठी और लौटकर लोग एक बार फिर उस पुराने घराने के पास आए। सोनिया से राजीव की मौत के बाद ही कांग्रेस की कमान संभालने का आग्रह किया गया था; लेकिन उन्होंने मजबूती से मना कर दिया था। लेकिन इस बार उन्हें तैयार किया गया। सोनिया ने कोई सत्ता नहीं हासिल की थी, कांटों का ताज संभाला था। कांग्रेस निष्प्राण थी। लोग उसकी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मरने की भविष्यवाणियां कर रहे थे। एक मृतप्राय पार्टी का नेतृत्व उन्होंने लिया था। 1999 के लोकसभा चुनाव में तो पारा और नीचे उतर गया, जब कांग्रेस को सिर्फ 114 सीटें मिलीं।

कांग्रेस ने 91 बार लगाया राष्ट्रपति शासन

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार के 6 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगने की नौबत आई थी। लेकिन अनुच्छेद 356 का कांग्रेस ने किस तरीके से उपयोग किया है, ये काफी दिलचस्प है। कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान सत्ता में रहते हुए 91 गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने का काम कर चुकी है। 1951 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते पंजाब में सरकार को बर्खास्त किया गया था और उसके बाद से विभिन्न राज्यों में कुल 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। नेहरू के काल में केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद द्वारा बनाई गई पहली वामपंथी सरकार को भी 1959 में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार और अनुच्छेद 356 की। महाराष्ट्र पहला राज्य नहीं है जहां भाजपा के शासन में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो। साल 2014 के बाद से देश के चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। आखिरी बार जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, वह जम्मू-कश्मीर था। जम्मू-कश्मीर में पिछले साल जून में भाजपा ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद यहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इससे पहले भी साल 2015 में विधानसभा चुनावों में एक खंडित फैसले के बाद सरकार गठन में विफलता के चलते जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन राज्य में लागू किया गया था। साल 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 26 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कांग्रेस के 21 विधायकों ने 11 भाजपा और दो निर्दलीय विधायकों के साथ हाथ मिलाया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया था। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में भी साल 2016 में दो बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। पहले 25 दिन और बाद में 19 दिन के लिए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 को सबसे ज्यादा 45 बार लागू किया। सबसे दिलचस्प है कि 1959 में जब इंदिरा ने केरल में कम्युनिस्ट सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से गिराया तो फिरोज गांधी ने भी इसका विरोध किया। हालत ये हुई कि इस घटना के विरोध में फिरोज गांधी फिर कभी प्रधानमंत्री आवास नहीं गए। जब उनकी मौत हुई, तब ही उनके पार्थिव शरीर को तीन मूर्ति ले जाया गया।

क्षत्रपों के अहंकार ने डुबोया कांग्रेस को!

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भाजपा की उम्मीदों और भरोसे को पंख लगा दिए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन राज्यों की हैट्रिक जीत को 2024 में भाजपा की लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक की गारंटी बताया है। इन नतीजों से भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के भीतर पहले से ही मौजूद भाजपा और मजबूत होगी और सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे में उठ सकने वाले असंतोष के स्वर न सिर्फ खामोश होंगे बल्कि सहयोगी भाजपा की इच्छानुसार सीट बंटवारे के हर फॉर्मूले को सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। बिहार की हाजीपुर सीट के लिए न चिराग पासवान बाल हठ कर सकेंगे और न ही उनके चाचा पशुपति पारस ही हाजीपुर न मिलने पर एनडीए से बाहर जाने की सोच सकेंगे। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी प्रसाद में जो मिलेगा उस पर ही खुश रहेंगे। कुछ इसी तरह उप्र में अनुप्रिया पटेल का अपना दल और ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा सीट बंटवारे को लेकर आंखें नहीं तरेर सकेंगे। महाराष्ट्र में भी भाजपा ही तय करेगी कि लोकसभा की 48 सीटों में सहयोगी दलों शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजीत पवार) कितनी और कौनसी सीटों पर लड़ेंगे। इस लिहाज से लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर आए विधानसभा चुनावों के इन नतीजों से न सिर्फ भाजपा का दबदबा बढ़ गया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पार्टी के भीतर और बाहर और बड़ा हो गया है। अब भाजपा नेतृत्व आसानी से मप्र में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीगगढ़ में रमन सिंह के विकल्प के तौर पर पार्टी में नया नेतृत्व तैयार कर सकता है, क्योंकि ये चुनाव इन क्षत्रपों के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी के निशान कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जीते गए हैं। भाजपा की अंदरूनी राजनीति में यह एक निर्णायक मोड़ है जब अटल आडवाणी युग के क्षेत्रीय क्षत्रपों की जगह पार्टी उत्तर भारत के इन तीन प्रमुख राज्यों में नया नेतृत्व विकसित करेगी। हालांकि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की भीड़ की वजह से यह एक चुनौती भी है लेकिन भाजपा का मौजूदा नेतृत्व इन चुनौतियों से बखूबी निपटना जानता है। उधर कांग्रेस के लिए ये नतीजे बेहद निराशाजनक हैं। सिर्फ दक्षिण भारत से तेलंगाना की जीत ने उसे कुछ राहत दी है। हालांकि यह भी सच है कि जब-जब कांग्रेस संकट में आई है उसे दक्षिण भारत ने ही सहारा दिया है। 1977 में जब पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, तब दक्षिण के तत्कालीन चारों राज्यों ने कांग्रेस का ही परचम लहराया था। सत्ताच्युत हुई इंदिरा गांधी को पहले कर्नाटक के चिकमंगलूर फिर तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मेडक सीट ने लोकसभा में भेजा।

कमलनाथ का खेल कैसा?

भाजपा में शामिल होने के कयासों को खारिज करते हुए कमलनाथ कह चुके हैं कि वह हमेशा कांग्रेस नेता थे, हैं और रहेंगे। खुद कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के लिए बैठकें ले रहे हैं, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ भाजपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं? कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में ही कई कांग्रेसी नेता भाजपा में क्यों शामिल हो गए? मप्र में यह अजीबोगरीब स्थिति दिखी है। जहां कमलनाथ कांग्रेस के लिए काम करते हुए दिखते हैं वहीं उनके बेटे नकुलनाथ भाजपा के मुख्यमंत्री का स्वागत करते दिखते हैं, वह भी उस कार्यक्रम का जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर नेता भाजपा में शामिल हुए। कुछ दिन पहले ही कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंचे और वो लोग तमाम भाजपा नेताओं से मिले थे। कई मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि कमलनाथ को भाजपा में स्विच करने की संभावना है और कांग्रेस के नेतृत्व ने उन तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं किया है। कुछ दिन पहले ही खबरें आई थीं कि कमलनाथ राज्यसभा सीट नहीं मिलने से असंतुष्ट हैं। कमलनाथ को हाल ही में कांग्रेस की मप्र इकाई के प्रमुख के रूप में हटा दिया गया था। पिछले साल राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। जब उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे तो कुछ दिन बाद कमलनाथ की ओर से कहा गया था कि वह हमेशा कांग्रेस नेता थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने गत दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पार्टी की बैठक ली थी। लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में दिखे थे। छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाग लिया, जहां उनके कार्यालय के अनुसार 1,500 से अधिक कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए।

सोनिया के नेतृत्व में यह पहला चुनाव था। लेकिन सोनिया ने सधे कदमों से अपनी राजनीति कायम रखी। उन्होंने क्षेत्रीय दलों और वामपक्ष से कांग्रेस का एक समन्वय किया। 2004 में सोनिया के समन्वय का थोड़ा कमाल जरूर दिखा। सीटें तो भाजपा से केवल सात अधिक थीं (145 सीटें कांग्रेस की थीं और 138 भाजपा की), लेकिन तालमेल और कूटनीति के तहत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को हटा देना एक बड़ी बात थी, जो सोनिया ने कर दिखाया था। इससे यह पता चलता है कि इस देश का राजनीतिक चरित्र क्या है। जनतांत्रिक ढांचे के बीच एक देवत्व (करिश्माई व्यक्तित्व या आस्था) इसे शायद चाहिए। यह न केवल कांग्रेस, बल्कि किसी भी भारतीय राजनीतिक दल को चाहिए। जब यह नहीं होता है, तब उसका सत्ता में आना असंभव हो जाता है। जनता अपने इन देवताओं को हटाना भी जानती है। जैसे इंदिरा और राजीव, वीपी, अटल या फिर सोनिया को हटाया। लेकिन उसे हर हाल में एक देवता चाहिए। उसे हाथ जोड़ने के लिए एक गोबर का गणेश ही सही, लेकिन चाहिए।

2009 में कांग्रेस 206 और भाजपा 116 पर आ गई। सात सीटों का फासला बढ़कर 90 का हो गया। कांग्रेस को और आगे बढ़ना था, लेकिन अचानक वह फिसल गई। उसे नए विचारों और खून की जरूरत थी। उस पर दलाल हावी होने लगे। कांग्रेस चौतरफा सुस्त हो गई थी और भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय कमान सौंप दी। यह एक प्रयोग था, जो आरएसएस कर रहा था। दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे चलने की राजनीति। अपनी रणनीति के मामले में मोदी ने जाने-अनजाने 1970-71 की इंदिरा गांधी की नकल की, फिर अपनी ही पार्टी के उस कल्याण सिंह का भी अनुसरण किया, जिसे अटल बिहारी ने घर बैठा दिया था। नतीजा हुआ 2014 में मोदी ने आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। भाजपा का पूर्ण बहुमत के साथ आना कांग्रेस की नाकामी का नतीजा था।

लगातार गिरता गया ग्राफ

यह क्यों हुआ? कांग्रेस 206 से अचानक 44 पर क्यों चली आई? कांग्रेस इस वक्त कुछ गरूर में चली गई। राहुल गांधी को नेता के रूप में खड़ा किया गया। उन्होंने अपने इर्द-गिर्द जो टीम बनाई, वह राजसी किस्म की थी। अंग्रेजीदां, चिकने-चुपड़े चेहरे और खानदानी पृष्ठभूमि। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद जैसे चेहरे कांग्रेस के लिए भार के सिवा कुछ नहीं हैं। इसमें ज्योतिरादित्य और जितिन तो अलग हो चुके और सचिन भी हो सकते हैं। हम यह कहने की स्थिति में हैं कि राजस्थान में गहलोत, कर्नाटक में सिद्धारमैय्या या छत्तीसगढ़ में बघेल जैसे नेता उन सबके मुकाबले कहीं उपयुक्त हैं। ज्योतिरादित्य, जितिन और सचिन के उदाहरण कुछ और संकेत करते हैं। राजनीति में सत्ता हासिल करना उद्देश्य अवश्य होता है, लेकिन वह तो पावर है, ताकत है, इसलिए उसे हासिल करना है। असली मकसद तो वे उसूल और विचार या कार्यक्रम हैं, जिनको पूरा करने के लिए सत्ता चाहिए। ये कैसे कांग्रेसी हैं, जो सत्ता के लिए कांग्रेस से सीधे भाजपा में मिल रहे हैं। इसका मतलब उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। पार्टी छोड़ना कोई गलत नहीं है। लोकतंत्र में इस प्रवृति का न होना ही गलत है। पार्टी की स्थिति से रंज होकर पहले भी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव भारी बहुमत से जीतकर भी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। लेकिन वह हिंदू महासभा में नहीं चले गए थे। 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने इकट्ठे पार्टी छोड़ी। उन लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। चरण सिंह, चंद्रशेखर जैसे जाने कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी; लेकिन उनमें से शायद ही कोई जनसंघ में गया। समान विचारों के दलों में उनका जाना हुआ, अथवा उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। शरद पवार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी ने भी पार्टी छोड़ी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस बनाई, वे भाजपा में नहीं गए। ज्योतिरादित्य और जितिन भाजपा में गए हैं। इन्होंने पार्टी तो छोड़ी ही है, विचार का भी परित्याग किया है। इस हिसाब से उनका जाना अधिक अच्छा है। सुना है, ये जितिन कुछ समय पूर्व से उप्र में ब्रह्म चेतना फैला रहे थे। इस आदमी को उसी वक्त पार्टी से निकाल देना था। लेकिन निकालेगा कौन? राहुल भी तो कभी-कभार ब्राह्मण बनने की कोशिश करते दिखते हैं।

अब कांग्रेसयुक्त भाजपा

पिछले एक दशक में जिस भारत ने आकार लिया है, उसमें कांग्रेस शासित भारत इतना पीछे छूट गया है कि पार्टी के अस्तित्व तक पर संकट खड़ा हो गया है। सत्ता में लौटना तो दूर की बात है, उसके मुख्य विपक्षी दल तक बने रहने की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र में एक सवाल उठाया था कि अगर भारत में कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता? तब भारत की बौद्धिक बिरादरी, इतिहासकारों और सोशल मीडिया की फौज आदि को जवाब तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा और इनमें कुछ ने उनके विचारों का समर्थन करने के इरादे से, कुछ ने विरोध करने के लिए और बाकी ने ट्रोल करने के इरादे से ऐसा किया। उधर, दिल्ली के सत्ता-गलियारों में इन दिनों अटकलों का एक नया खेल चल रहा है- कांग्रेस-युक्त भाजपा के लिए पार्टी छोड़ने वाला अगला कांग्रेसी कौन होगा? जहां भाजपा नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 सीटें पार करने का दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस इस असुविधाजनक सवाल से जूझ रही है कि क्या सबसे पुरानी पार्टी इस बार 50 सीटें पार कर पाएगी? 2014 के चुनावों को याद करें, जब कांग्रेस अब तक की सबसे कम 44 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 थोड़ा बेहतर था, जब उसने 52 सीटें जीती थीं और केरल और तमिलनाडु (द्रमुक के साथ गठबंधन में) ने उसे दक्षिण में कुछ बेहतर महसूस कराया था।

2024 में भी, अधिकांश जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कांग्रेस को केरल और संभवत: तेलंगाना को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में दोहरे अंक में प्रवेश करने में कठिनाई होगी। उत्तर-पश्चिम की जिस लहर ने पिछले दोनों अवसरों पर भाजपा को सत्ता में पहुंचाया था, वह पश्चिमी समुद्र तट से लेकर हिंदी पट्टी तक फैले विशाल क्षेत्र में फिर से ऐसा करने के संकेत दे रही है और इससे कांग्रेस लड़खड़ा रही है। सनद रहे कि 2019 में कांग्रेस ने उत्तर-पश्चिम बेल्ट के 10 राज्यों की 243 में से केवल छह सीटें जीती थीं। लेकिन कांग्रेस का चुनावी पतन 2014 में नरेंद्र मोदी के उत्थान के साथ ही शुरू नहीं हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी की

राहुल की नई यात्रा से उम्मीद कम

राहुल गांधी की पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा को उनकी दक्षिण से उत्तर यात्रा के बाद के कार्यक्रम के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका असली मकसद हिंदी पट्टी में जीत के बाद माहौल को और मजबूत करना था। पिछली यात्रा काफी सफल रही थी, राहुल के रास्ते में भारी भीड़ जुटी थी और उन्होंने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था और मोदी सरकार पर हमला बोला था। लेकिन इस बार की यात्रा, जो हार के बाद हुई है, जिसने कर्नाटक की जीत को भी फीका कर दिया है। यह यात्रा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। यह उन इलाकों से होकर गुजरी है, जहां कांग्रेस को अब भी उम्मीद है, जैसे उत्तर बंगाल, असम, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से। लेकिन कांग्रेस में असली चिंता लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी चुनावी रणनीति को लेकर है। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये यात्रा सही संदेश नहीं दे रही है, ऊपर से भाजपा सरकारों द्वारा बार-बार रोके जाने और कांग्रेस में आंतरिक समस्याओं ने इसे और कमजोर कर दिया है। कर्नाटक में जीत के बाद जब कांग्रेस का भाग्य फिर से अच्छा लगने लगा, तो राहुल गांधी की लंबी दाढ़ी और अडाणी-मोदी पर उनके हमले सुर्खियों में छाए रहे। लेकिन असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। इंडिया ब्लॉक चाहता था कि सीटों का बंटवारा हो और पूरे देश में मिलकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस पर टाल-मटोल की, क्योंकि उसे लगा कि मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव जीतने के बाद वो बेहतर सौदा कर सकती है। चुनाव हारने के बाद, सहयोगी दलों ने कांग्रेस को रैलियों और सीट-बंटवारे में देरी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे गठबंधन की रफ्तार धीमी हो गई। नीतीश कुमार और आरएलडी भी भाजपा के साथ चले गए।

हत्या के बाद जबर्दस्त सहानुभूति-लहर के बाद से कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है। इन चालीस वर्षों में, कांग्रेस ने केवल दो बार 200 सीटों को पार किया है। उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 1991 में था, जब चुनाव अभियान के बीच में राजीव गांधी की दुखद हत्या ने कहानी बदल दी थी। एकमात्र अन्य अवसर 2009 में आया, जब डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व को जनता का समर्थन मिला। लेकिन घटती संख्या के इतर, परेशान करने वाला यह सवाल भी बना हुआ है कि खुद को चुनाव जीतने के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए कांग्रेस ने पिछले दशक में क्या किया?

कांग्रेस नेता भाजपा के संस्थागत वर्चस्व की ओर इशारा करेंगे- चाहे वह चुनाव आयोग हो, ईडी हो, मीडिया हो या चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव और चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस जैसे कदम हों। यह सच है कि राज्यसत्ता की मदद से भाजपा को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर भारी बढ़त मिल गई है। लेकिन एक आकर्षक और एकजुट विकल्प के रूप में खुद को फिर से खड़ा करने में कांग्रेस की असमर्थता ने क्या उसके पतन में योगदान नहीं दिया?

साथी दल छोड़ रहे हाथ

देश में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज है। भाजपा ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी मैदान में है। उधर कांग्रेस को चुनाव से पहले ही एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन से भी कुछ साथी छिटक गए हैं। कांग्रेस ने पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनावों में जीत की उम्मीद में 2024 के लोकसभा चुनावों समेत अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया था। उन्हें लगा कि कुछ हिंदी राज्यों में जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था, क्योंकि कई चीजें एक साथ दांव पर लगाना कभी अच्छा नहीं होता। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनकी जीत से उनके साथी दलों को भी फायदा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। पार्टी में फूट पड़ गई है, कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनके सहयोगी दल भी उनसे दूरियां बना रहे हैं। कुछ दलों ने कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया है, भले ही वे पहले कांग्रेस का साथ दे रहे थे। हालांकि, ऐसा करने के पीछे केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का दबाव भी एक कारण है, लेकिन असल समस्या ये है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़, मप्र और राजस्थान में चुनाव हार गई। अगर महाराष्ट्र के नेता अशोक चव्हाण और राजस्थान के आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय भाजपा की तरफ देख रहे हैं और टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं, तो इसकी वजह ये है कि कांग्रेस अपने ही भीतर टूट रही है। गलत रणनीतियों और घमंड की वजह से पार्टी इस हाल में पहुंच गई है।

क्या हिंदुत्व का असर कम कर पाएंगे राहुल?

भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के सहारे माहौल को गरमाने में लगी है? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देशभर से राम भक्तों का अयोध्या आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे उत्तर भारत में भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटरों की लामबंदी का माहौल बनता दिख रहा है। देशभर से आने वाले राम भक्तों के साथ गोधरा जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। भाजपा हिंदू भावनाओं को उभारकर उत्तर भारत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उप्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मप्र, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में अधिकतम सीटें जीत ली थीं। इन राज्यों में भाजपा की सीटों में होने वाली कमी उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अयोध्या के सहारे पैदा किए जा रहे हिंदुत्व की नई लहर को रोक पाएगी? पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इसका काफी असर पड़ा था। इस बार भाजपा समर्थक दावा कर रहे हैं कि हिंदुत्व के तूफान में मोहब्बत की दुकान उड़ जाएगी। राहुल गांधी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है।

2019 के बाद से भले ही कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी, लेकिन पिछले साल मई में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को कर्नाटक में हराकर उसने वापसी की उम्मीद जगाई थी। भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियां, भले ही वो कांग्रेस के मजबूत होने से सहमत नहीं थीं, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी से इंडिया ब्लॉक बना। लेकिन कांग्रेस को लगा कि अगर वो छत्तीसगढ़ और मप्र जीत लेती है तो उसे और भी फायदा होगा। राजस्थान में हार के बावजूद भी अच्छी स्थिति रहने से कांग्रेस वापस आ गई का नारा और मजबूत होता और इसका इस्तेमाल सहयोगी दलों पर दबाव बनाने और अपनी कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती। लेकिन ये सोच गलत साबित हुई और कांग्रेस का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया।

2019 में मोदी के दोबारा चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी के कई मजबूत नेता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए। पिछले साढ़े तीन साल में कांग्रेस हर राज्य चुनाव हारती रही। थोड़ी राहत तब मिली जब दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में पार्टी जीत गई। ये उसी समय हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कर्नाटक में जीत ने कांग्रेस को अपने संगठन को दोबारा बनाने, राज्यवार रणनीति बनाने और गठबंधन तय करने का एक सुनहरा मौका दिया। जीत का समय नेतृत्व दिखाने और पार्टी को मजबूत बनाने का होता है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। लेकिन पुरानी समझ को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने सिर्फ दिसंबर के चुनाव पर ध्यान देने का फैसला किया। राहुल गांधी ने रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन पार्टी ने संगठन को ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिसंबर में जब कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तब तक राज्य इकाइयों ने संगठन को मजबूत करने में कोई खास काम नहीं किया था। खड़गे के अध्यक्ष बनने के एक साल बाद भी एआईसीसी में बदलाव नहीं किया गया था, जिससे पार्टी में उत्साह नहीं दिखा। जल्दबाजी में किए गए अधिकांश बदलावों से पार्टी को अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बढ़ रही है स्वदेशी की शक्ति

आत्मनिर्भर बनने के संकल्प पथ पर दौड़ रहे भारत ने हर क्षेत्र में स्वदेशी का झंडा बुलंद किया है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल भारत अब खुद बना रहा है, वहीं युद्ध पोत और हल्के लड़ाकू विमान से लेकर घातक ड्रोन तक बनाकर पूरी दुनिया में स्वदेशी गुणवत्ता का लोहा मनवाया है। अपनी स्वदेशी तकनीक के बूते चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया बल्कि अब रक्षा उत्पादों के निर्यात का आंकड़ा 23 गुना बढ़ाते हुए पहले के 686 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2022-23 में 16000 करोड़ से ऊपर करने में सफलता अर्जित की है।

केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और तकनीक के बूते आत्मनिर्भर बनने की राह पर दौड़ रहा है। स्वावलंबी भारत अभियान के जरिए स्वदेशी सोच को मिली तरजीह के कारण ही स्वदेशी हथियारों, मिसाइल, हल्के फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम में दुनिया अब दिलचस्पी दिखा रही है। आज भारत 85 से अधिक देशों को स्वदेशी हथियार और उपकरण, कलपुर्जे निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत अभियान की बदौलत हथियारों के आयात पर होने वाले खर्च में भी गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 में रक्षा क्षेत्र पर खर्च होने वाले कुल लागत में से 46 प्रतिशत हथियारों और सिस्टम पर खर्च हुआ था। दिसंबर 2022 में यह खर्च गिरकर 35.6 प्रतिशत पर आ गया।

भारत ने चांद पर कदम रख पूरी दुनिया को एक तरह से चौंका दिया है। शुद्ध स्वदेशी उपकरणों से लैस इसरो का चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण कर भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसी तरह सूरज को समझने के लिए इसरो ने आदित्य एल-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। यह देश का पहला अंतरिक्ष अभियान है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य एल-1 सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास बिंदु लैंग्रेज पॉइंट वन जिसे एल-1 कहा जाता है, वहां स्थापित होगा। यानी सूर्य की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। सूर्य को समझने के लिए यह यान 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

स्वदेशी की बदौलत भारत अंतरिक्ष की दुनिया में भी तेजी से तरक्की कर रहा है। देश का अंतरिक्ष बाजार वर्ष 2040 तक 40 से 100 अरब डॉलर के पार होने की उम्मीद है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन कंपनी आर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दुनिया के चार देशों ने छह मसौदे पर इसरो के साथ करार किया है। अंतरराष्ट्रीय मिशन को अंजाम देने से भारत को 14.01 करोड़ डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 100 से अधिक स्टार्टअप चल रहे हैं। वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी बढ़कर 10 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन निर्मित कर लेगा। मालूम हो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को 175000 लाख करोड़ रुपए करना है। वहीं रक्षा निर्यात को बढ़ाते हुए इसी समयावधि में 35000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

रक्षा मंत्रालय ने 2020 में 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाई थी। यह उपकरण अब भारत में ही बन रहे हैं। 3700 रक्षा उत्पाद भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। 2024 में और 351 सामानों का निर्माण भारत में स्वदेशी तकनीक से होने लगेगा। इसरो द्वारा तैयार निसार उपग्रह से समुद्र स्तर, भूजल, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और पृथ्वी में हर घड़ी हो रहे बदलाव की जानकारी मिलने लगेगी। वर्ष 2024 के अंत तक इस मिशन को अंजाम दिया जाना है। इसरो ने वर्ष 2024 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। मिशन से पहले रोबोट व्योममित्रा को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। मिशन के लिए वायुसेना के चार पायलटों की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। भारतीय वायुसेना को इस साल फरवरी में पहला स्वदेशी फाइटर जेट तेजस एम के-1ए मिल सकता है। वायुसेना को कुल 83 जेट मिलने हैं। इसके लिए एचएएल से 48000 करोड़ रुपए का करार भी किया गया है।

देश में 5जी लांच होने के बाद 6जी की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कहा था कि भारत की कोशिश 6जी क्षेत्र का लीडर बनने की है। स्वावलंबी भारत अभियान के कर्ताधर्ताओं का मानना है कि भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यहां की जनसंख्या जितनी है, उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज भारत के लिए जितने भी आपूर्तिकर्ता देश हैं, वे हमारी जरूरत को शायद ही पूरा कर सकते हैं। दरअसल दूसरे देशों पर निर्भर रहने की कीमत चुकानी पड़ती है जो मौजूदा दौर में हमारे देश के हित में नहीं है। रक्षा सामग्री, अनाज, कम्प्यूटर, मोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल है या फिर ऑटोमोबाइल, हर तरफ हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

देश की विकास दर लगातार बढ़ रही

गौरतलब है कि नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए देश में 1,60,480 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों का संचालन हो रहा है। शिक्षा का बाजार जो 2020 में 180 अरब डॉलर था, वर्ष 2030 तक 320 अरब डॉलर होने की संभावना है। मेक इन इंडिया के तहत देश में 34 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। केंद्र की योजना है कि वर्ष 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 75 किया जाना है। स्वदेशी तकनीक और हमारी युवा मेधा के बदौलत भारत हर दिन प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में भारत अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाते हुए देश की विकास दर के लक्ष्य को 6.5 प्रतिशत से आगे पहुंचाने के साथ-साथ वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा। इसके लिए महंगाई को नियंत्रित रखने, सरकारी कर्ज को बढ़ाने से रोकने, निर्यात बढ़ाने, व्यापार घाटा कम करने, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के प्रयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय चरित्र के नवनिर्माण के लिए भी मजबूत पहल करनी होगी।

शुरु-शुरु में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गिनती करते थे कि चुनावों में कितने पूर्व कांग्रेसियों को भाजपा का टिकट मिला, लेकिन अब यह गिनती करना उन्होंने बंद कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा की एक्स पर की गई टिप्पणी भाजपा की वर्तमान दशा का बाखूबी बयान करती है। उन्होंने लिखा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी की कांग्रेस और मोदी की कांग्रेस के बीच होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब यह तो नहीं था कि सारे कांग्रेसी भाजपा में शामिल कर लिए जाएं, और उन्हीं को राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं की टिकट देकर भाजपा को ही कांग्रेस बना दिया जाए।

राहुल कांग्रेस बनाम मोदी कांग्रेस

सत्ता की इस अंधी चाह में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों वाली भाजपा कहीं खो गई है। कांग्रेस मुक्त भारत की जगह पर भाजपा मुक्त भारत हो गया है। जनसंघ के परिवारों से निकले भाजपा के कार्यकर्ता डॉ. मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. रघुबीर, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के सिद्धांतों और आदर्शों वाली भाजपा खोज रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनता पार्टी से टूटकर बनी भाजपा को उसी तरह अपने प्रचारक भेजना जारी रखा था, जैसे जनसंघ में संघ के प्रचारक पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। वे पार्टी में विचारधारा का संचालन करते थे। वे अब भी पार्टी में संगठन महामंत्रियों के पद पर विराजमान हैं, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें पार्टी में लाया गया था, वह काम अब गैरजरूरी सा हो गया है। क्योंकि पार्टी का लक्ष्य अपने एजेंडे को लागू करने के लिए चुनावी राजनीति में नेहरू परिवार की कांग्रेस पर विजय को बरकरार रखना है।

जनसंघ परिवारों से आए भाजपा कार्यकर्ताओं की सोच कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी ने साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करके वह हासिल कर लिया, जो पहले के सभी नेता नहीं कर पाए थे। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर में दो निशान (जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा), दो विधान (जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान) दो प्रधान (जम्मू-कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री) के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगाई। अनुच्छेद-370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का वह लक्ष्य अटल-आडवाणी की भाजपा छह साल सत्ता में रहने के बावजूद हासिल नहीं कर सकी थी। लेकिन दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी ने सबसे पहला काम यही किया, अब न वहां दो संविधान हैं, न दो निशान। वजीर-ए-आला का पद तो पहले ही खत्म हो गया था।

भाजपा के लिए चुनौती कम नहीं

भाजपा भले ही 400 पार का नारा लगा रही है, मगर इसे पाना आसान काम नहीं है। वर्तमान को देखकर यह कतई नहीं कहा जा सकता कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा के विजय रथ को लगाम दे सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि खेल अभी उतना आसान नहीं है जितना भाजपा की ओर से दावे किए जा रहे हैं। जो लोग दुहाई दे रहे हैं कि राम मंदिर मसले के बाद पूरा देश राम मय हो गया है और भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी, यह ऐसा सोचने वालों की महज कोरी कल्पना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश खुश और संतुष्ट है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले भी गदगद हैं। लेकिन वोट को लेकर राम मंदिर निर्माण का असर अधिकाधिक हिंदी प्रदेशों पर ही पड़ेगा, जहां पहले से ही भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। कहने का आशय यह है कि इस मुद्दे का जितना अधिकतम फायदा मिलना था, 2019 के चुनाव में मिल चुका है। 2024 में भाजपा के लिए यह मुद्दा कोई खास करिश्मा करेगा इसमें संदेह है। यही कारण है कि मंदिर उद्घाटन और राम के नाम का खुलेआम राजनीतिकरण कर सत्ता की हैट्रिक लगाने का सपना देखने वाली भाजपा भी इंडिया गठबंधन से सहमी हुई है। इसी असुरक्षा का नतीजा था कि जिस नीतीश कुमार के लिए भाजपा ने अपने दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए थे, अब खुशी-खुशी रेड कारपेट बिछाकर उनकी अगवानी करनी पड़ी है।

नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि उन्होंने भाजपा को कांग्रेस बना दिया। लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए, उन्होंने बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को भाजपा में लाकर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस के अनेक जमीनी नेता नीतियों के कारण कांग्रेस के साथ नहीं थे, वे सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए कांग्रेस के साथ थे। भाजपा के विस्तार की कोशिश तो अटल और आडवाणी ने भी की थी। याद कीजिए 1980 में भाजपा का गठन करते समय अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीवादी समाजवाद को पार्टी की विचारधारा बनाया था। वह जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सभी कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री रहे मोहम्मदिल करीम छागला और नामी वकील राम जेठमलानी को मुंबई में पार्टी के स्थापना मंच पर लेकर आए थे। लालकृष्ण आडवाणी ने मुसलमानों का दिल जीतने के लिए पाकिस्तान जाकर जिन्ना

विपक्ष में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा

इंडिया गठबंधन में सपा, आप, राजद, डीएमके, झामुमो जैसी बड़ी और स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभाव रखने वाली पार्टियां शामिल हैं। पिछली बार भाजपा के 37 प्रतिशत वोट के मुकाबले अकेले कांग्रेस को 20 प्रतिशत वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 189 ऐसी सीट थीं जहां कांग्रेस की भाजपा से सीधी टक्कर थी। अबकी बार इन सीटों में से कई पर समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। पिछली बार पूर्वोत्तर में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन अबकी बार ऐसा नहीं होने वाला। मणिपुर हिंसा, असम मेघालय विवाद के नजरिए से देखें तो कांग्रेस मतदाताओं पर असर डाल रही है। हाल में आया मिजोरम विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बात का प्रमाण है। इसी प्रकार उप्र, मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी भाजपा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले चुनाव में कर चुकी है जिसका एकमात्र कारण मोदी का नेतृत्व रहा है। लेकिन इस बार अगर इन राज्यों में संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा होता है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए 2019 की तुलना में मुकाबला कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत में छह राज्य आते हैं और इनमें पांच राज्यों से लोकसभा में 129 सदस्य चुने जाते हैं। भाजपा के सामने अब लक्ष्य केवल जीत का नहीं बल्कि विपक्ष की करारी हार का भी खड़ा हो गया है। भाजपा पश्चिम बंगाल में 2014 में दो सीट के मुकाबले साल 2019 में 18 सीटों पर और उड़ीसा में एक सीट से आठ सीटों पर जीत दर्ज कर वहां के मजबूत गढ़ में दाखिल हुई थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खाली हाथ रह गई थी।

की तारीफ की थी। लेकिन वे दोनों ही सफल नहीं हुए, क्योंकि हिंदू ऐसी भाजपा की कल्पना नहीं करते थे, जो सत्ता के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता करे। भाजपा के श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में कूदने के बाद हिंदू फिर से भाजपा से जुड़ने लगे थे। लेकिन वाजपेयी और आडवाणी ने सत्ता के लिए एनडीए बनाकर भाजपा के तीनों प्रमुख मुद्दों से समझौता किया।

नरेंद्र मोदी संघ की भट्टी में तपे हुए विचारधारा के पक्के भाजपाई हैं, वह भाजपा को इसलिए सत्ता दिला पाए क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देशभर के हिंदुओं का विश्वास जीता था। लेकिन 2014 में मोदी के नेतृत्व में आई हिंदू क्रांति तब तक अधूरी थी, जब तक जम्मू-कश्मीर से 370 नहीं हटाया गया। 2014 से 2019 तक मोदी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, भाजपा के तीनों ही मुद्दों पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन तीन तलाक जैसे मुद्दे पर बिल पास करवाकर उन्होंने एक प्रतिबद्धता दिखा दी कि वह कट्टरपंथी मुस्लिमों के आगे कतई नहीं झुकेंगे। यह एक संकेत था कि जैसे ही दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, वह भाजपा के तीनों एजेंडों श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने और समान नागरिक संहिता का काम पूरा करेंगे। इसके बावजूद 2019 के चुनाव से पहले भारी तादाद में कांग्रेसी भाजपा से जुड़े, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ नहीं थी, उनकी विचारधारा सिर्फ सत्ता थी। दोबारा सत्ता में आते ही मोदी ने तीन महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर से 370 को हटाकर जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजली दे दी।

2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भगदड़ मची है। भाजपा के सामने पहले से भी बड़ा जनादेश हासिल करके समान नागरिक संहिता का एजेंडा पूरा करना और फिर मथुरा काशी के मंदिर मुक्त करवाना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस और अन्य दलों के नेता अपनी-अपनी पार्टियां छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 1996 और 1998 में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने अपने तीनों मुद्दों से समझौता किया था। अब भाजपा अपने तीनों मुद्दों पर कायम रहते हुए राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के नेताओं को भाजपा में आने और भाजपा के साथ आने को मजबूर कर रही है। जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलसी शहनाज गनई, पंजाब के कांग्रेसी नेता अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़, हरियाणा के अशोक तंवर, हिमाचल में हर्ष महाजन, उत्तराखंड के विजय बहुगुणा और किशोर उपाध्याय, उप्र के जगदम्बिका पाल और रीता बहुगुणा, मप्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा, आंध्र प्रदेश के किरण कुमार रेड्डी, कर्नाटक के एसएम कृष्णा, इनमें कई कांग्रेसी नेता अपने-अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष, पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री, कांग्रेस के महासचिव रहे एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, पूर्व कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और दो-दो प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद जब भाजपा का दामन थाम लेते हैं, तो क्या यह नहीं दर्शाता कि वे और उनका परिवार विचारधारा के कारण कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, या सत्ता के कारण। जब तक नेहरू परिवार उन्हें सत्ता दिला सकता था, तब तक वे कांग्रेस के साथ थे, जैसे ही उन्हें लगा कि अब नरेंद्र मोदी उन्हें सत्ता दिला सकते हैं, तो वे भाजपा में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण का अगर लोकसभा का टिकट फाइनल हो जाता तो वे कांग्रेस में रहते।

दलबदल करके भाजपा में शामिल होने वालों का कोई दीन, ईमान और विचारधारा नहीं है। सत्ता में हिस्सेदारी ही उनका लक्ष्य है। मोदी समर्थकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस से कौन भाजपा में शामिल हो रहा है, उनका मकसद मोदी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता है। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर रहे, हिंदुओं के लिए यही काफी है। हां, भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को तब जरूर तकलीफ होती है, जब नरेंद्र मोदी भाजपा में शामिल होते ही नारायण राणे, अशोक चव्हाण, आरपीएन सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में लाकर मंत्री बना देते हैं, जिनके परिवारों के साथ उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया, उन्हें रातों-रात उनका नेता बना देते हैं। समाज में यह आम धारणा है कि कांग्रेस या अन्य दलों से भाजपा में शामिल होने वालों को उच्च सदन का सदस्य नहीं बनाना चाहिए, वे चुनाव जीतकर आएं, तभी उन्हें सरकार में शामिल किया जाना चाहिए। वरना लगता है कि मोदी भाजपा को कांग्रेस ही बना रहे हैं।

● **विपिन कंधारी**

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राजनीति में ऐसी जोड़ी है जो बड़ी से बड़ी जीत से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि उस जीत के बाद और बड़ी जीत को हासिल करने में लग जाती है। 2001 में जब संघ-भाजपा ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात की कमान सौंपी थी तब उनको भी ये अनुमान नहीं था कि एक दिन यही मोदी न केवल गुजरात की कलह को ख़त्म कर पार्टी को अजेय बना देंगे बल्कि भाजपा को उसके इतिहास की अनवरत बड़ी से बड़ी जीत दिलाते जाएंगे।

बिना सुकून जीत का जुनून

गुजरात में मोदी और शाह की जोड़ी ने जो जीत दर जीत हासिल की, वही क्रम उन्होंने केंद्र में भी दोहरा दिया। 2014 से बड़ी जीत 2019 में मिली और अब 2023 में वो पिछली जीत से भी बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं। वो जीत चाहते हैं और उन्हें जीत मिल जाती है, ऐसा होता नहीं है। जीत और सीट का जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं, साम-दाम-दंड-भेद वाली नीति चतुष्टय का इस्तेमाल करते हैं। अंतत: असंभव से दिखने वाले उनके लक्ष्य संभव सी जीत में बदल जाते हैं। बीते 10 सालों के दौरान विधानसभा चुनावों में भी तीन-चार मौके ही ऐसे आए हैं जब उनका गणित गड़बड़ाया हो। वरना वो जो तय करते हैं, उसे हासिल करते हैं। हासिल करते ही अगला लक्ष्य निर्धारित करके उसे पाने में जुट जाते हैं।

यही कारण है कि जब अमित शाह ने 2013 में पार्टी की चुनावी कमान संभाली तो पूर्ण बहुमत का संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। उस समय वो बतौर चुनाव को-आर्डिनेटर ही काम कर रहे थे लेकिन उनकी हैसियत पार्टी अध्यक्ष से कम न थी। जब अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह टारगेट दे रहे थे तब पार्टी में ही किसी को भरोसा नहीं था कि भाजपा को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। उस समय तक मोदी सबसे पॉपुलर लीडर भले बन चुके थे फिर भी 282 सीटें अपने अकेले के बूते जीतना इतना आसान तो नहीं था?

पार्टी में नेता दाहिने बायें से यही कहते रहे कि पूर्ण बहुमत का लक्ष्य है तो सबसे ज्यादा सीटें तो आ ही जाएंगी। लेकिन दूसरी ओर मोदी-शाह की जोड़ी ने स्वतंत्र रूप से इतना तगड़ा कैम्पेन चलाया कि जनता पर जादू चल गया। सोशल मीडिया हो या मीडिया, सब पर मोदी छा गए। चुनाव के 4 महीने पहले से उनकी रैलियां शुरू हो गईं। वो लोग जानते थे कि दिल्ली का रास्ता उप्र से होकर ही जाता है इसलिए सबसे अधिक फोकस उप्र पर ही किया। खुद मोदी बनारस से प्रत्याशी बनकर पहुंच गए और परिणाम आया तो विपक्ष से अधिक पार्टी के नेता चौंक गए। पूर्ण बहुमत मिल चुका था।

आमतौर पर जो दल सत्ता में रहता है तो दूसरी बार या तो वह हारता है या फिर उसकी सीटें कम होती हैं। इसे राजनीतिक लोग एंटी इनकम्बैंसी कहते हैं। लेकिन 2019 में मोदी-शाह की जोड़ी ने 2014 से बड़ी जीत हासिल करते हुए 303 सीटें जीत ली। यह 2014 के 282 से 21 सीट अधिक थी। अब 2023 में वो दोनों 370 सीट जीतने का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। तो क्या यह सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तैयार किया गया आंकड़ा है या सचमुच तीसरी बार उनकी सबसे बड़ी जीत होने जा रही है?

जनकल्याण योजनाओं की पहुंच और भविष्य

ऐसा आंकलन लगाने वाले लोग शायद इतिहास से भी कट चुके हैं और वर्तमान का अहसास नहीं कर रहे। ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता, जनकल्याण योजनाओं की पहुंच और भविष्य को लेकर सकारात्मकता को भी नहीं देख पा रहे हैं और वह इस सच्चाई को नजरअंदाज करना चाहते हैं कि चुनाव में काम और नाम यानी चेहरे की विश्वसनीयता अहम होती है। ऐसे लोग इतिहास के उस पन्ने से भी अनजान बन रहे हैं जो बताता है कि सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस वोटर संख्या के लिहाज से आज भी वहीं खड़ी है जहां आज से चालीस साल पहले थी। भाजपा के अधिवेशन में फिर से तीसरी बार वापसी को लेकर प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास बोल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वोटरों तक पहुंच रहे हैं। भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट की बहुत चर्चा होती है। वह यही है जो प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने के लक्ष्य के रूप में दिया है। कैसे जोड़ना है यह भी बताया गया है। कहा गया है कि पहली बार मतदाता सूची में जुड़े एक भी वोटर अछूते न रहें।

अब तक का इस जोड़ी की जीत का ट्रैक रिकार्ड देखें तो यह सिर्फ कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का सांकेतिक लक्ष्य नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा है तब उनके पास निश्चित रूप से पूरा खाका तैयार होगा। वो दोनों जानते हैं कि 37.36 प्रतिशत वोट और 303 सीट जीत लेने के बाद इसके आगे एक-एक सीट पर बढ़ने के लिए जीती हुई सीटों के साथ हारी हुई सीटों पर फोकस करना होगा। वो ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रणनीति बना लेने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए कैडर या पार्टी वर्करों का आक्रामक होकर मैदान में उतरना जरूरी होता है। कैडर या पार्टी वर्कर को आक्रामक बनाने के लिए उनके मन में संतोष नहीं बल्कि असंतोष की आग जलानी होती है। उनके सामने नया लक्ष्य रखना होता है ताकि वो जो हासिल हुआ है उस पर संतोष करने के बजाय नए लक्ष्य को पाने में लग जाएं। इसलिए दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुद नरेंद्र मोदी ने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने कई नए-नए लक्ष्य रख दिए। जैसे, अगले कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मोदी जानते हैं कि संघ पृष्ठभूमि के भाजपा वर्करों के लिए राष्ट्र सबसे पहले होता है। इसलिए राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र के विकास से जुड़ी बातें जितना उनके मन को प्रभावित करेंगी, उतना दूसरा कुछ नहीं।

वैसे भी सत्ता का सफल राजनीतिज्ञ वो होता है जो चुनाव में अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय नए-नए सपनों को बेचना जानता हो। उपलब्धियां मन में संतोष पैदा करती हैं जबकि सपनों को हासिल करने के लिए सक्रिय होकर काम करना पड़ता है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को वही सपना दिखा दिया है। उन्हें बताया गया है कि जीत का जुनून हो तभी जीत संभव होती है और जब तक ऐसा न हो जाए तब तक सुकून और शांति से नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं है कि खुद मोदी-शाह की जोड़ी भी सपने बेचकर शांत भाव में घर बैठ जाते हैं। मोदी भले ही 73 साल के हो गए हों, दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हों लेकिन चुनाव के लिए या चुनाव के दौरान वो ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं जो सुनने में भले असहज लगती हों लेकिन वह उनके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं और कम पढ़े-लिखे वोटरों को प्रभावित करती हैं।

शायद यही कारण है कि उत्तर भारत में सामान्य वोटरों के बीच अबकी बार से मोदी की गारंटी तक उनका क्रेज बना हुआ है। वैसे भी मोदी का राजनीतिक उभार ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक नेताओं की विश्वसनीयता बहुत गिर गई थी। हर नेता चोर होता है, जैसे जुमले आम हो गए थे। उस समय में मोदी ने जनता के बीच जो विश्वसनीयता अर्जित की है यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल वो राजनीति में उस जगह खड़े हैं जहां उनके द्वारा किया जाने वाला हर काम सही होता है। इसलिए पार्टी के भीतर और बाहर भी उनके द्वारा किए गए हर निर्णय को सही ठहराने का काम मीडिया और सोशल मीडिया का बड़ा वर्ग कर ही रहा है। फिर भी 370 का आंकड़ा पाना इतना भी आसान नहीं है। विपक्षी दल बिखरे हुए जरूर हैं लेकिन भाजपा का सारा जोर उत्तर भारत में ही है। 370 का आंकड़ा पाने के लिए उसे केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में संभावना पैदा करनी होगी। आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मोदी लहर चलानी होगी। फिर राजस्थान, मप्र, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी के भीतर की उथल-पुथल भी संभालनी होगी। लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने जो जोश अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरा है उसे देखकर लगता है कि वो 370 के अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। लक्ष्य हासिल होता है या पिछली बार की जीत से भाजपा नीचे चली जाती है, यह समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी शाह की जोड़ी इस चुनाव में विपक्ष विहीन लोकसभा का सपना संजोए हुए है।

लोकसभा चुनाव की शुरुआत में डेढ़-दो महीने की देर है, और पिछले एक-डेढ़ महीने में पूरा विमर्श बदल गया है। अब चर्चा यह हो रही है कि अबकी बार 400 पार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास सही साबित होगा या नहीं। लोगों की आशंका का आधार यह है कि राजीव गांधी की 414 सीट की जीत तो सहानुभूति लहर के कारण तब हुई थी जब हर राज्य में कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भाजपा के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की बैठक में भाजपा मुख्यमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी-अपनी रिपोर्ट दी। राज्यों में संगठन के स्तर पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी हैं, ये बताया गया। राज्य सरकारों ने जो बेहतरीन कदम उठाए हैं, उसको मुख्यमंत्रियों ने बताया।

● इन्द्र कुमार

कांग्रेस का गिरता ग्राफ

लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में सीटों पर जीत हार का अंतर 25 हजार से एक लाख के बीच ही होता है। दूसरी तरफ का फर्क देखिए। देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने राजीव गांधी के समय 414 का आंकड़ा छुआ था। तब देश में कुल वोटर की संख्या 38 करोड़ थी और वोट डालने वाले लगभग 24 करोड़ थे। कांग्रेस ने कुल वोटिंग का लगभग 50 फीसदी हासिल किया था। बड़ी हैरानी की बात है कि तब से लेकर अब तक कांग्रेस चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में उसके वोटरों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। 2004 के संप्रग काल में कांग्रेस को साढ़े दस करोड़ वोट मिले थे तो 2009 में 11.91 और 2019 में 11.94 करोड़। जबकि कुल वोटरों की संख्या में लगभग तीनगुनी वृद्धि हो चुकी है। 2024 के चुनाव में वोटरों की संख्या लगभग 98 करोड़ होगी। भाजपा 1984 के लगभग 2 करोड़ वोटरों के मुकाबले 2019 में 23 करोड़ पर पहुंच चुकी है और अब इसे कम से कम दोगुना करने की तैयारी है। अपने काम और प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे भाजपा की नई रणनीति कुल वोटरों का पचास फीसदी हिस्सा लेने की है। अगर यह संभव हुआ तो एक ऐसा इतिहास बनेगा किसी भी लोकतंत्र के लिए उदाहरण होगा।

क्या बघेल बच जाएंगे...?

महादेव सट्टा ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फंसते नजर आ रहे हैं। इस केस में उनका नाम तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय ही आया था लेकिन अब ईडी की चार्जशीट में भी उनका नाम शामिल किया गया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल को महादेव सट्टा एप के प्रमोटरों द्वारा 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद अब माना जा रहा है कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें कभी भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है।

महादेव सट्टा ऐप केस में आरोपी असीम दास ने अपने बयान में बघेल का नाम लिया है। उसने बताया है कि बघेल को चुनाव के दौरान महादेव ऐप प्रोमोटर्स की ओर से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बीच मुंबई से इस केस में पहली गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने दीक्षित कोठारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि कोठारी एक बेटिंग एप्लिकेशन का मुख्य संचालक है। उस पर विदेश में डोमेन रजिस्टर करवाकर भारत में बेटिंग ऐप चलाने का आरोप है। आरोपी असीम दास के ठिकाने से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए गए थे। ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में असीम दास के अलावा शुभम सोनी, अमित अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह के भी नाम दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की करीब 1,700-1,800 पन्नों की नई चार्जशीट एक जनवरी को दायर की गई थी। इसमें पांच लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। इनमें कथित कैश कूरियर असीम दास, पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव, ऐप से जुड़े एक प्रमुख कार्यकारी शुभम सोनी और अन्य शामिल हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि पीएमएलए अदालत द्वारा 10 जनवरी को इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने की उम्मीद है।

ईडी की चार्जशीट के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ईडी ने विधानसभा चुनाव के समय राज्य में चुनाव को प्रभावित करने के लिए भूपेश बघेल का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि, जिस असीम दास के बयान के आधार पर उनका नाम जोड़ा गया उस असीम दास ने खुद कहा था कि उससे ये बयान दबाव डालकर लिया गया है। भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे केसों में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन समेत विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी की जांच पहले से ही चल रही है। इसी कड़ी में अब भूपेश बघेल का नाम भी शामिल हो चुका है। अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह ईडी भूपेश बघेल को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। ऐसे में भूपेश बघेल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं।

बयान से पलट गए आरोपी

ईडी के वकील ने कहा कि पहली सप्लीमेंट्री शिकायत में पांच लोगों के नाम थे। आरोपियों में असीम दास, भीम सिंह यादव, अनिल कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी और शुभम सोनी शामिल हैं। पांडे ने बताया कि आरोपी असीम दास ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को 5 करोड़ 39 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने उसके बयान को अपनी शिकायत का हिस्सा बनाया था। इसके अलावा शिकायत में दो अन्य आरोपियों के बयान भी शामिल किए गए थे। हालांकि, बाद में तीनों आरोपी अपने बयान से पलट गए थे। वकील ने कहा कि आरोपी चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर की ओर से एक पत्र में कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 50 के तहत ईडी अथॉरिटी को जो भी बयान दिए गए थे, वे झूठे थे, लेकिन जब ईडी अधिकारी अदालत से अनुमति लेने के बाद उनसे जेल में मिलने गए, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि लिखे गए पत्र फर्जी थे और यह उनकी लिखावट नहीं है। सौरभ पांडे ने कहा, हमारे लिए अदालत को यह दिखाना जरूरी है कि हमने क्या बयान दर्ज किए हैं। हमने विशेष अदालत के सामने अपना बयान पेश किया था और वहां अपने विचार भी व्यक्त किए थे।

वहीं इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर साजिश रच रही है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है, वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूटरचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि, जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे उसने जेल से अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया है कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी राजनेता व उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने यह बयान भी वापस ले लिया है। यह किस दबाव में हो रहा है, उसे सब जानते हैं।

अब सवाल यह है कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपए बरामद किए थे उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। इसका मतलब है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसका मतलब यही है कि इसकी कूटरचना ईडी ने ही की थी। भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा है कि, ईडी ने दावा किया है कि चंद्रभूषण वर्मा ने भी अपना पहले का बयान वापस ले लिया है। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि ईडी मारपीट से लेकर धमकी देने तक हर हथकंडे अपनाकर मेरा व मेरे सहयोगियों का नाम लेने का दबाव बना रही है। ईडी के नए दस्तावेज से यह और स्पष्ट हो गया है। महादेव ऐप के घोटाले की जांच मैंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए खुद शुरू की थी। मैं चाहता था कि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो और युवाओं को जुआखोरी की ओर धकेल रहे इस अपराध पर रोक लगे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस जांच के आधार पर ही ईडी धन-शोधन का मामला बनाकर जांच कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ईडी ने जांच को अपराध की बजाय राजनीतिक दबाव व बदनामी का हथियार बना लिया है। महादेव ऐप के पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया है उससे साफ है कि इसका उद्देश्य अब असली अपराधियों को बचाने और राजनीतिक दुष्प्रचार कर भाजपा को फायदा पहुंचाने का ही रह गया है।

● रायपुर से टीपी सिंह

विचारधारा नहीं सत्ता ही लक्ष्य

अब राज ठाकरे का मन डोल रहा

पिछले दो सालों में सर्वाधिक राजनीतिक उठापठक महाराष्ट्र में देखने को मिली है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के भाजपा के साथ आने की अटकलों ने फिर से राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर राज ठाकरे एनडीए (महाराष्ट्र में महायुति यानी ग्रैंड अलायंस) का हिस्सा बनते हैं तो भाजपा को कितना फायदा होगा? महाराष्ट्र में राज ठाकरे भाजपा के साथ आएंगे या नहीं, इससे पहले बात भाजपा की। भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन (भाजपा, शिवसेना-शिंदे, एनसीपी अजित पवार) ने राज्य की 48 सीटों में से 45 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। महायुति गठबंधन के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार अब इसी टारगेट को लेकर राज्य में सियासी समीकरण बैठा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज ठाकरे महायुति के 45 सीटों को जीतने के लक्ष्य में मददगार हो सकते हैं। यही वजह है कि मुंबई भाजपा के नेताओं ने राज ठाकरे का मन टटोलना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) 17 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इससे पहले पार्टी ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था तो शिवसेना को नुकसान उठाना पड़ा था।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस से 50 साल से भी पुराना रिश्ता था। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, मिलिंद देवड़ा खुद भी कांग्रेस के सांसद रहे थे। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनके पिता एसबी चव्हाण भी मुख्यमंत्री रहे थे। इन दोनों जन्मजात कांग्रेसी नेताओं ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अशोक चव्हाण भाजपा से और मिलिंद देवड़ा शिवसेना से राज्यसभा का टिकट पा गए। तीसरे नेता बाबा सिद्दीकी अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए हैं। उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एनसीपी राज्यसभा की एक ही सीट जीत सकती है।

हालांकि प्रफुल्ल पटेल की मौजूदा राज्यसभा की अवधि 2028 तक थी, लेकिन शरद पवार ने उनको डिसक्वालीफाई करने की याचिका लगा रखी है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर एनसीपी कोटे की सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। अब प्रफुल्ल पटेल की खाली की हुई सीट पर बाद में उपचुनाव होगा। चव्हाण, देवड़ा और पटेल तीनों ही मूल रूप से कांग्रेसी हैं, जो राज्यसभा में एनडीए सांसद होंगे। तीनों पचास साल से भी ज्यादा समय से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े थे और भाजपा के साथ विचारधारा की लड़ाई मानते थे। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर फिर बड़ी भविष्यवाणी की है। खास बात यह है कि वह इससे पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। पिछली बार उनकी ऐसी भविष्यवाणी करने के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी उपमुख्यमंत्री अजित पवार के गुट में शामिल हो गए हैं। ये तीनों घटनाएं महाराष्ट्र के लोगों के लिए अप्रत्याशित थीं।

भाजपा नेता गिरीश महाजन ने दावा किया है कि आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और विस्फोट होगा। इससे कई लोगों की भौंहें तन गई हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं। गिरीश महाजन ने कहा, मैंने पिछली बार कहा था कि एक विस्फोट होने वाला है और हुआ था। इससे उनका पारिवारिक रिश्ता है। वे दिवाली, दशहरा त्योहारों के दौरान पारिवारिक समारोहों में एक साथ मिलते हैं, तो यह एक पारिवारिक यात्रा होगी। सुप्रिया सुले और अजित दादा की इस मुलाकात के बारे में अजित दादा ही बता सकते हैं। आठ दिनों में राज्य में एक और विस्फोट की संभावना है।

शरद पवार की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिलने पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की मशाल नहीं जलेगी और पवार साहब की तुरही नहीं बजेगी। एमपी के लिए छह मंत्रियों के नामांकन पर बात करते हुए गिरीश महाजन ने कहा, यह फैसला हमारे वरिष्ठ स्तर के नेता लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक बात सामने नहीं आई है। यह महज एक अफवाह है। लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा केंद्रीय स्तर पर होती है। गिरीश महाजन ने सांसद संजय राउत को लेकर कहा- ऐसा लगता है कि हमारे अध्यक्ष उनसे पूछकर ही काम करते हैं। जहां कुछ भी कहना हो अफवाह फैलाना इनका काम बन गया है। मैं उद्धव ठाकरे और ठाकरे गुट के प्रमुख संजय राउत से कहता हूं कि आप अपनी सीट पर ध्यान दें। हम देखेंगे कि हम कहां लड़ेंगे, कितनी जगह लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। ठाकरे समूह को जितनी सीटें मिली हैं, उनमें से एक सीट चुननी चाहिए। जब मैं भाजपा में था तो 18 सीटों पर चुनाव होते थे। अब उन्हें एमपी के लिए कम से कम एक सीट चुननी चाहिए। उन्होंने कहा, मनोज जरांगे से छह बार मुलाकात हुई। उनसे बातचीत की। पटेलों के आंदोलन के बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाए। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। महाराष्ट्र में पहली बार इतनी तत्परता से काम हुआ। लेकिन फिर से जरांगे की इच्छानुसार काम नहीं कर रहा? कहीं तो संतुष्टि होगी। अब विशेष सत्र बुलाए गए हैं। कानून के अनुकूल आरक्षण दिया गया। हम कह रहे हैं कि जरांगे को अतिवादी रुख अपनाए बिना अपनी जरूरी मांगों को ठीक करना चाहिए, लेकिन भूख हड़ताल पर जाने से कुछ खास हासिल नहीं होगा।

● **बिन्दु माथुर**

सियासत का फेर या आंकड़ों की बाजीगरी

सियासत के फेर में आंकड़ों की बाजीगरी कहें या फिर मानवीय भूल, क्योंकि यह मामला भजनलाल सरकार के मंत्री से जुड़ा था। थानेदार ने मंत्री को खुश करने के लिए या फिर बिना जानकारी के मंत्रीजी के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात कोर्ट में लिख डाली। इधर, खुफिया पड़ताल में सामने आया कि मंत्री के खिलाफ 22 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और जानकारी ठीक करवाकर कोर्ट में भिजवाई गई।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर के खिलाफ वर्ष 2023 में संजय सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। केस विधायक से जुड़ा होने के कारण जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई थी। इधर, इस मामले में अगले महीने मार्च में हाईकोर्ट में मंत्री की पेशी होनी है। मामला संजय सर्किल थाने में दर्ज हुआ था। ऐसे में हाईकोर्ट ने केस की फाइल मंगवाने के निर्देश दिए। फाइल के साथ संजय सर्किल थानाधिकारी ने दिलावर के खिलाफ किसी प्रकार का पुराना मुकदमा दर्ज नहीं होने की जानकारी भेज दी।

दरअसल, जब भी किसी आपराधिक मुकदमें में सेशन और हाईकोर्ट में तारीख पड़ती है तो फाइल कोर्ट में भेजी जाती है। केस की स्थिति के साथ ही **आपराधिक रिकॉर्ड** और तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजना जरूरी होता है। व्यक्ति के खुद के थाने में एफआईआर दर्ज होती है तो पार्ट फर्स्ट में तथा किसी गैर इलाके में मामला दर्ज हो तो जानकारी फार्ट थर्ड में लिखना अनिवार्य है। इधर, संजय सर्किल थाने की फाइल देखते ही कोर्ट कर्मियों ने सीआईडी सीबी थाने और सीआईडी ने मंत्री दिलावर के गृह थाने अटरू से जानकारी मांगी। जिसके बाद पता चला कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ लगभग 22 केस दर्ज हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार, थाने में एफआईआर पार्ट फर्स्ट में दर्ज होती है और गैर इलाके में दर्ज होने वाली एफआईआर पार्ट थर्ड में दर्ज होती है। भले ही आरोपी के खिलाफ कितने ही केस दर्ज हो, जानकारी में नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।

सूत्रों का कहना है कि करीब पांच साल पहले भी दस्तावेज जमा नहीं होने पर आरोपी को जमानत मिल गई थी। गौरतलब है कि राजस्थान में हाल ही गठित भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर काफी सुर्खियों में हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता के तौर पर माने जाने वाले नेता दिलावर अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। 6 जनवरी को उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद उनके कुछ फैसले और बयान लोगों के बीच चर्चा में हैं। ये फैसले इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही जयपुर में भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य की ओर से हिजाब को लेकर कथित रूप से बयान दिया गया। इसको लेकर काफी बवाल मचा। इस मामले में दिलावर ने भी विधायक का पक्ष लेते हुए सभी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा जहां ड्रेस कोड लागू नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिजाब को लेकर दूसरे राज्यों की भी रिपोर्ट मांगने की बात कही। शिक्षा मंत्री दिलावर ने सरकार के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति में पहली से पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। वैसे भी जिन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं हैं तो, उनका कोई उपयोग नहीं है। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हिंदी मातृभाषा है। ऐसे में स्कूलों में संसाधनों को देखते हुए कार्य किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम के रिव्यू कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में देश के आक्रांता अकबर को महान बताया है। जो कैसे महान हो सकता है। जबकि मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने वाले हमारे महाराणा प्रताप थे। यह इतिहास गलत है। यह लोग शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा बोलते थे। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के मौके पर राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सूर्य नमस्कार के माध्यम से रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को अपनी मर्यादा में रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोई शिक्षक अनैतिक आचरण करता हुआ पाया गया तो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ में उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। चाहे फिर मुझे फांसी हो जाए। शिक्षा मंत्री का यह बयान जमकर सुर्खियों में रहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि **उनके विभाग में भ्रष्टाचार** बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वदेशी पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोगों ने हीन भावना पैदा कर दी है कि देश में बनाया हुआ कोई भी सामान विदेशी सामान से हल्का होता है, लेकिन आज की तारीख में वो ये कह सकते हैं कि आज देश में आलपिन से लेकर हवाई जहाज, मिसाइल और लड़ाकू विमान तक सर्वश्रेष्ठ बन रहे हैं, जिनकी मांग विदेशों में भी है और जब यहां स्वदेशी सामान बहुत अच्छे हैं तो विदेशी क्यों खरीदें। यहां पर जो भी सामान बनता है, इसका लाभ यहां के लोगों को मिलता है। उन्हें रोजगार मिलता है, हमारे देश का पैसा देश में ही रहता है। इसलिए लिखित में आदेश दिया है कि आलपिन से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु जो शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग में काम आती है, वो स्वदेशी ही खरीदेंगे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

कभी बरी, कभी वापस और कभी कोर्ट

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ दर्ज मामलों को देखा जाए तो सबसे पहले वर्ष 1979 में अटरू में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। इसी तरह बारां कोतवाली में 1979 दर्ज, वर्ष 1999, वर्ष 2000 में दो, वर्ष 2001 में दर्ज मामले में दिलावर को बरी या केस ड्रोप किया गया। वर्ष 1990 और वर्ष 1992 में दर्ज केसों में एफआर लगी। वर्ष 1989 में विज्ञान नगर कोटा, मकबरा कोटा केस में बरी किए गए। 1995 में बारां सदर में संदेह का लाभ देकर बरी किया गया। 1999 में अटरू में दर्ज केस 399 और 432 को तथा वर्ष 2010 में दर्ज केसों को राज्य सरकार ने वापस लिया। पिछले साल रामगंज मंडी और सुकैत थाने में दर्ज केस 195 पुलिस के पास पेंडिंग हैं। 14 जुलाई 2021 में रामगंज मंडी में दर्ज महामारी अधिनियम का मामला कोर्ट में पैंडिंग है। इस्तगासा से दर्ज दो अन्य केस राज्य सरकार की ओर से वापस लिए गए हैं।

आखिरकार झुके अखिलेश

उप्र में कांग्रेस और सपा की दबाव की रणनीति कामयाब रही। सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग हो गई है। इसकी वजह यह रही कि भाजपा ने जातीय समीकरणों की जोरदार नाकेबंदी की है। भाजपा की नाकेबंदी के कारण सपा और कांग्रेस को मजबूरी में एक-दूसरे की शर्तें माननी पड़ी हैं। उप्र की तरह पंजाब और दिल्ली में भी भाजपा की चुनावी रणनीति को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नए सिरे से बातचीत शुरू हो गई है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव ने दोनों पार्टियों को फिर से बातचीत के लिए मजबूर किया है। उप्र में भाजपा ने पूरब में अनुप्रिया पटेल के अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया है, तो पश्चिम में जयंत चौधरी के रालोद को अपने साथ ले लिया है। विधानसभा चुनावों में ओमप्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और दलित नेता कमलकांत गौतम समाजवादी पार्टी के साथ थे। जातियों के समीकरण के कारण सपा की सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई थीं।

गैर यादव **पिछड़ी जातियों** और दलितों में आधार वाले ये सभी नेता अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। राजभर और जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और कमलकांत गौतम सपा का साथ छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी का एमवाई गठबंधन भी खतरे में है, क्योंकि मुसलमानों का रुख भी कांग्रेस की तरफ है, इसलिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि सपा अकेले चुनाव लड़ती। पिछले कई दिनों से जो खबरें आ रही थीं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत टूट गई है, वह पूरी तरह निराधार थीं। सामने वाले पर दबाव बनाने के लिए राजनीति में कई बार इस तरह की खबरें राजनीतिक दल खुद चलवाते हैं। समाजवादी पार्टी इन खबरों से कांग्रेस पर दबाव बना रही थी। खबरों को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने सपा के उम्मीदवारों का ऐलान भी करना शुरू कर दिया था। 16, 11 और 5 उम्मीदवारों की तीन सूचियों में उन्होंने 32 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। इनमें से कुछ सीटें वे थीं, जिन पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी। कांग्रेस अखिलेश यादव की दबाव की रणनीति के साथ-साथ उनकी मजबूरी को भी समझती थी, इसलिए वह भी टस से मस नहीं हुई। इसी कारण अखिलेश यादव खुद झुकते चले गए। कहां पहले उन्होंने 11 सीटों की पेशकश करते हुए कहा था कि इससे ज्यादा सीटें नहीं दे सकते, फिर 15 सीटों पर आए, और आखिर में संख्या बढ़ाकर 17 कर दी।

अखिलेश यादव के राहुल की यात्रा में शामिल न होने के बयान ने दबाव का जोरदार काम किया। कांग्रेस 21 सीटों की मांग से नीचे आ गई है। 17 या 18 सीटों पर समझौता हो जाएगा। अखिलेश यादव ने खुद ही कह दिया है कि अंत भला तो सब भला। अब राहुल गांधी की उप्र में चल रही यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल होना भी लगभग तय है। इस बीच अंदरखाते बसपा से बातचीत चल रही थी कि वह भी गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन मायावती अड़ी हुई हैं, जिस कारण बसपा के लगभग सारे सांसद इधर-उधर बिखर रहे हैं। कुछ सांसद कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ सपा में जा रहे हैं, तो कुछ भाजपा में जा रहे हैं। विधानसभा में सिर्फ एक सीट जीतने के बाद से बसपा बिखराव के मुहाने पर है। अखिलेश यादव की तरह ही अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ दबाव की राजनीति खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की न तो दिल्ली में बातचीत टूटी है, न पंजाब में। जबकि केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों ही सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक सीट देने की पेशकश की है, जबकि कांग्रेस अभी भी चार पर अड़ी हुई है। अंदरूनी खबर यह है कि एक-दो दिनों में ही केजरीवाल तीन सीटों की पेशकश करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब में भी केजरीवाल के अड़ियल रुख में बदलाव आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया। मेयर पद के चुनाव के लिए समर्थन मांगने केजरीवाल खुद राहुल गांधी के पास गए थे। यह फैसला हो गया था कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा, और डिप्टी मेयर कांग्रेस का होगा। चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में 13 काउंसलर आम आदमी पार्टी के हैं, और 7 कांग्रेस के। दोनों पार्टियों के मिलकर 20 काउंसलर हो गए थे। दूसरी तरफ भाजपा के 14 और अकाली दल का एक काउंसलर है। एक वोट सांसद का होता है, तो भाजपा की सांसद किरन खेर का एक वोट है। लेकिन चुनाव में धांधली करके भाजपा ने मेयर का पद जीत लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने रद्द किए गए 8 वोट बहाल करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया। अब यह अलग विषय है कि चुनाव में हेराफेरी की साजिश की रणनीति किस स्तर पर बनी थी। चंडीगढ़ स्तर पर बनी थी, या राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ भी हो, भाजपा की बदनामी तो हुई ही है। राहुल गांधी ने कहा है कि हेराफेरी करने वाला रिटर्निंग ऑफिसर तो सिर्फ मोहरा था, हेराफेरी के पीछे मोदी का हाथ था। यह अलग विषय है कि आम आदमी पार्टी का मेयर कितने दिन रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तीन काउंसलर दलबदल करके भाजपा में जा चुके है। आम आदमी पार्टी के मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर भाजपा उन्हें कभी भी हटा सकती है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

आप के रुख पर सबकी नजर

पंजाब में कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल में भी बहुत कुछ चल रहा है। अकाली दल और भाजपा की बातचीत इस बात पर टूटी है कि भाजपा 13 में से 7 सीटें मांग रही थी, जबकि अकाली दल पहले की तरह सिर्फ तीन सीटें गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर की ही पेशकश कर रही थी। भाजपा का तर्क है कि विधानसभा चुनावों के बाद उसकी ताकत बढ़ी है। कांग्रेस के दो बड़े नेता अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ भाजपा में आए हैं। अकाली दल के भी कई नेता भाजपा में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और मनीष तिवारी भी भाजपा में आ सकते हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू और मनीष तिवारी भाजपा में आ जाते हैं, तो भाजपा और अकाली दल में भी दोबारा बातचीत शुरू हो जाएगी। उधर, युवराज सिंह के भी भाजपा में शामिल होने और गुरदासपुर से उम्मीदवार बनने की अटकलें हैं। वैसे गुरदासपुर के लिए भाजपा के पास सुनील जाखड़ सशक्त उम्मीदवार हैं, वह पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं। भाजपा अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, आनंदपुर साहिब और पटियाला में चुनाव लड़ने का इरादा रखती है।

बिहार में महिला वोटर किसके साथ

जैसे-जैसे लोकसभा का चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक समीकरणों और एजंडों पर मंथन भी तेजी पकड़ रहा है। बिहार में नीतीश के एनडीए में आने के बाद भाजपा के लिए नफे और नुकसान की भी चर्चा हो रही है। कई लोगों का मानना है कि अब नीतीश बाबू की वह वोट अपील नहीं रही जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान थी। पर बहुत लोगों का यह भी आंकलन है कि नीतीश के पास अपनी जाति के 5 प्रतिशत वोट और महिलाओं के 50 प्रतिशत से अधिक वोट आज भी हैं और किसी भी चुनाव के परिणाम में इतने वोट काफी असर डाल सकते हैं। क्या नीतीश के साथ महिला वोटर सचमुच पहले की तरह बरकरार हैं, या जातिगत सर्वेक्षण और शिक्षक भर्ती का श्रेय तेजस्वी यादव लेकर नीतीश कुमार का पुराना समीकरण बिगाड़ सकते हैं?

2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि महिला मतदाताओं ने एनडीए का भरपूर साथ दिया था। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए के उम्मीदवार जीत गए थे, हालांकि उस जीत में प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता का हाथ था पर बिहार जैसे राज्य में जहां चुनाव मुख्य रूप से जातिगत आधार पर लड़े और जीते जाते हैं, वहां सामाजिक बदलाव का चुनाव पर बड़ा असर पड़े, यह बड़ी बात है। इस नए बदलाव की वाहक बिहार की महिलाएं थी, जिन्होंने नीतीश कुमार की शराबबंदी और लड़कियों की शिक्षा पर रीझ कर एनडीए के पक्ष में जमकर वोट किया था।

2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को भी देखें तो 59.7 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यानि महिलाओं में चुनाव को लेकर उत्साह ज्यादा था। कभी बिहार में महिला मतदान का प्रतिशत 40 और पुरुष मतदान का हिस्सा 60 प्रतिशत होता था। नीतीश को इसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। 2005 से नीतीश कुमार लगातार सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी, तो उसमें उनकी विकासात्मक नीतियों के साथ-साथ महिलाओं के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम के भी परिणाम कारण बने। नीतीश ने गांव और पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और निर्णय में उनकी भूमिका सुनिश्चित की। लगभग दो दशकों के उनके शासनकाल में बिहार में महिलाओं को आजीविका से जोड़ने वाली कई परियोजनाएं चलाई गईं। महिला जीविका कार्यक्रम, साइकिल योजना और महिलाओं के लिए पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण ने नीतीश को एक सुधारवादी नेता के रूप में स्थापित किया। बिहार के लगभग 45,000 गांवों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए महिला-आधारित सामुदायिक संगठनों का एक जाल बन गया है।

मुख्यमंत्री साइकिल योजना से लड़कियों के स्कूल नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कुछ सालों में ही माध्यमिक विद्यालयों में लिंग अनुपात का अंतर कम हो गया। छात्राओं ने सरकार से प्राप्त साइकिल का उपयोग माध्यमिक विद्यालय तक पढ़ाई जारी रखने में किया। लड़कियां चारदीवारी से निकलकर अपने लिए एक मुकाम हासिल करने में सक्षम होने लगीं। उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। वे सामाजिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में भाग लेने लगीं। इसलिए चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी नीतीश कुमार की राजनीतिक और विकासात्मक पहल का ही परिणाम माना जाता है। बिहार में महिलाओं के बीच राजनीतिक आकांक्षा भी बढ़ी है और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने संसदीय और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व भी दिया है। हालांकि जीतकर आने वाली महिला प्रतिनिधियों की संख्या अब भी बहुत कम है। 40 सांसदों में केवल 3 महिला सांसद हैं और उसी तरह 243 विधायकों में से केवल 28 महिला विधायक हैं।

2019 में एक जनमत सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया कि महिलाएं ही थीं जो बिहार में एनडीए को बचाए रखना चाहती थीं, इसलिए नीतीश के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को 41 प्रतिशत महिला वोट पड़े जबकि राजद के नेतृत्व वाले ग्रैंड अलायंस को 31 प्रतिशत महिलाओं के वोट मिले। महिलाओं ने एनडीए को बेहतर कानून और व्यवस्था के साथ-साथ शराबबंदी के प्रति नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता के लिए भी वोट किया। इस बीच बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण और सरकारी नौकरियों का श्रेय लेने की लड़ाई जनता दल यूनाइटेड यानि जेडीयू और राजद के बीच चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं, लेकिन उनका परंपरागत वोटर भी साथ आ गया है, इस पर अलग-अलग आंकलन है। लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी बांटने का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में जरूर उठेगा। तेजस्वी ने ही उपमुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख नौकरियां देने का नारा उछाला था और अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए 1.22 लाख शिक्षकों में से 25,000 को 2 नवंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुलाकर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया था और शेष 97,000 शिक्षकों को उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया गया था। अब इन दोनों मुद्दों के आधार पर राजद नीतीश के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने का दावा कर रहा है। अब यह देखना है कि नीतीश की समर्थक महिलाएं अपना समर्थन बनाए रखती हैं अथवा नहीं।

● **विनोद बक्सरी**

मिशन 40 से 400 प्लस पर निशान

भाजपा का लोकसभा चुनाव 2024 को फतह करने के लिए नारा अगली बार 400 पार है। इसे हर हाल में वह पूरा कर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के अन्य नेता जी-जान से मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 40 से 400 प्लस पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खेमे में नीतीश कुमार को जोड़ लिया है। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो भाजपा को लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से अति पिछड़ा वोटर्स एनडीए के पाले में आ सकते हैं। जो कुछ समय पहले तक भाजपा के लिए एक मुश्किल टास्क दिख रहा था। बिहार में अति पिछड़ा 36 फीसदी हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। पिछड़ा 27, एससी 20 फीसदी, सवर्ण 15 फीसदी और एसटी 2 फीसदी है। ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि नीतीश कुमार को महिलाएं भी बढ़-चढ़कर वोट करती हैं।

पाकिस्तान की राजनीति पर क्यों हावी है सेना?

पाकिस्तान की जनता ने 8 फरवरी को आम चुनाव में मतदान किया। अधिकांश राजनीतिक टिप्पणीकारों का मानना है कि नवाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जीत का यह भरोसा इसलिए नहीं है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को जनता का भारी समर्थन प्राप्त है। बल्कि उनकी जीत की भविष्यवाणी पाकिस्तानी सेना की बदौलत की जा रही है। दूसरी तरफ इस चुनाव में नवाज शरीफ को इसलिए भी फायदा होगा क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान जेल में हैं और वह चुनाव भी नहीं लड़ सकते। बता दें कि इमरान की तरह, नवाज भी जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर चुके हैं। इसके कारण उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में देश भी छोड़ दिया था।

1947 से ही पाकिस्तानी सेना ने अपने देश में सत्ता परिवर्तन को प्रभावित किया है। यह पाकिस्तानी सेना ही थी जिसने यह सुनिश्चित किया कि अब नवाज शरीफ सत्ता में आए और पहले यह तय किया था कि वह सत्ता से बाहर जाएंगे। यह सेना ही है जो इमरान खान के उत्थान और पतन दोनों का सूत्रधार बनी। इस बात का श्रेय भी काफी हद तक पाकिस्तानी सेना को ही जाता है कि अब तक वहां का कोई भी प्रधानमंत्री पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। अब तक तीन तख्तापलट करने वाले पाकिस्तानी जनरल देश में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका की कहानी।

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान: व्हाई कैन्ट वी जस्ट बी फ्रेंड्स?' में सेना के पास शुरू से ही मौजूद संसाधनों के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है, विभाजन में पाकिस्तान के हिस्से में ब्रिटिश भारत की आबादी का 21 प्रतिशत और उसके राजस्व का 17 प्रतिशत शामिल था, विभाजन की शर्तों के तहत, पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की सेना का 30 प्रतिशत, नौसेना का 40 प्रतिशत और वायुसेना का 20 प्रतिशत प्राप्त हुआ। अंग्रेजी शासन ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए कुछ समूहों को मार्शल फोर्स के रूप में पहचाना था। इनमें पश्तून और पंजाबी मुसलमान भी थे, जो अधिकतर उन क्षेत्रों से थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 1948 में पहले बजट का 75 प्रतिशत डिफेंस और जवानों के वेतन व रखरखाव की लागत को कवर करने के लिए आवंटित किया था। हक्कानी लिखते हैं, इस तरह, पाकिस्तान अन्य देशों की तरह नहीं था जो अपने सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए सेना खड़ी करते हैं। इसे एक बड़ी सेना विरासत में मिली थी जिसे बनाए रखने के लिए खतरों की लगातार जरूरत थी।

पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने सेना की सर्वोच्चता की कल्पना नहीं की थी। 1948 में क्वेटा स्थित आर्मी स्टाफ कॉलेज में एक भाषण के दौरान जिन्ना ने कहा था, यह मत भूलो कि सशस्त्र बल लोगों के सेवक हैं। आप राष्ट्रीय नीति नहीं बनाते; यह हम नागरिक हैं, जो इन मुद्दों को तय करते हैं और यह आपका कर्तव्य है कि इन कार्यों को पूरा करें जो आपको सौंपे गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने ठीक इसका उलटा किया है। 2022 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पष्ट कहा था कि सेना ने राजनीति में असंवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया है। सम्मानित पाकिस्तानी अखबार डॉन ने उस समय लिखा था कि, पाकिस्तान की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप व्यापक रहा है। तख्तापलट के माध्यम से जनता की चुनी सरकारों को हटाने से लेकर परोक्ष रूप से कमजोर व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने तक में सेना का हाथ रहा है। राजनीतिक नेताओं ने भी बहुत आसानी से सेना को जगह दे दी है और उनकी कमजोरियों के कारण संस्थागत सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है।

अपनी पुस्तक द आर्मी एंड द डेमोक्रेसी में पाकिस्तानी अकादमिक अकील शाह ने लिखा है कि सेना को राजनेताओं के प्रति अविश्वास ब्रिटिश भारतीय सेना से विरासत में मिला था। शाह ने लिखा, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों (और सिविल सेवकों) ने राष्ट्रवादी राजनेताओं के लिए उसी दृष्टिकोण को आत्मसात कर लिया जो औपनिवेशिक अधिकारियों का था। अंग्रेज अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को निकम्मा आंदोलनकारी मानते थे, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों के जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पाकिस्तानी सेना तीन बार सीधे संभाल चुकी है सत्ता

पहला तख्तापलट (1958)- शाह ने लिखा है, शीत युद्ध के दौरान एशियाई और लैटिन अमेरिकी सेनाओं की तरह, पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व का मानना था कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। सेना लोगों की जातीय भावनाओं का शोषण नहीं करेगी, जैसा कि राजनेता करते हैं। इस प्रकार, 1958 में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सरकार को अलग-थलग कर दिया और राजनीतिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया। लोगों में सेना के प्रति समर्थन की भावना थी, जिसने तख्तापलट को वैध बना दिया।

दूसरा तख्तापलट (1977)- भारत से अपमानजनक हार और 1971 में देश के टुकड़े-टुकड़े होने से एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की मनोदशा खराब हो गई। 1977 के चुनावों के नतीजों पर विपक्षी पाकिस्तान नेशनल अलायंस (पीएनए) ने जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के खिलाफ धांधली के आरोप लगाए। भुट्टो द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद जनरल जिया-उल हक ने 1977 में तख्तापलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई।

तीसरा तख्तापलट (1999)- इस वर्ष प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अधीन सत्ता के मजबूत होने के डर से, सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्तापलट किया। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए मुशर्रफ भारत के साथ युद्ध करना चाहते थे और इसके लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर दबाव बना रहे थे। भारत ने कारगिल में मुशर्रफ के दुस्साहस के लिए पाकिस्तान को दंडित किया। पाक की बुरी हार हुई। इसके बाद जनरल ने देश में तख्तापलट कर दिया।

युद्ध की तैयारी गृहयुद्ध का खतरा

दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश चीन में एक बार फिर से ऐसा कुछ हो रहा है, जो 1970 के दशक के बाद शायद ही देखा गया था। चीन की कंपनियों ने अपनी प्राइवेट आर्मी का निर्माण करना शुरू कर दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की कम से कम 16 बड़ी कंपनियों ने पिछले साल अपनी-अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली हैं। पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेज डिपार्टमेंट के नाम से जानी जाने वाली ये इकाइयां उन लोगों से बनी हैं, जो अपनी नियमित नौकरियां भी करते हैं और इसका भी हिस्सा बने हैं। वे दुनिया की सबसे बड़ी चीन की सेना के लिए रिजर्व फोर्स के तौर पर भी काम करते हैं। और देश में प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ युद्ध की आपात स्थिति में भी किसी भी वक्त जाने के लिए तैयार होते हैं।

चीन की कंपनियों ने जिस सेना का निर्माम किया है, वो फिलहाल चीन के बाहर काम नहीं कर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि चीनी कंपनियों की ये सेना अमेरिका के नेशनल गार्ड से मिलती-जुलती हैं, जो निजी अर्धसैनिक संगठनों को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर दक्षिणपंथी राजनीतिक फोकस रखते हैं। विश्लेषकों का कहना है, कि कॉर्पोरेट ब्रिगेड की स्थापना विदेशों में संभावित संघर्ष के साथ-साथ घरेलू स्तर पर सामाजिक अशांति के बारे में बीजिंग की बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है। यानि, चीनी कंपनियां मानती हैं, कि देश में आंतरिक संघर्ष कभी भी भड़क सकता है। हालांकि, चीनी कंपनियों ने जो सेना का निर्माण किया है, इसका मतलब अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है, बल्कि अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है, कि प्राइवेट आर्मी के निर्माण के पीछे कंपनियों पर शी जिनपिंग का और भी नियंत्रण स्थापित करने का हिस्सा हो सकता है, या फिर चीन को अभी से कोविड जैसी किसी महामारी से निपटने के लिए एक व्यवस्था तैयार करना भी हो सकता है।

एशिया सोसाइटी में चीनी राजनीति के फेलो नील थॉमस ने कहा, कि कॉर्पोरेट मिलिशिया की वापसी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आर्थिक विकास को बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर शी जिनपिंग के बढ़ते फोकस को दर्शाती है, क्योंकि देश को धीमी वृद्धि और बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ और अधिक कठिन भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, सैन्य नेतृत्व में कॉर्पोरेट मिलिशिया कम्युनिस्ट पार्टी को उपभोक्ता विरोध और कर्मचारी हड़ताल जैसी सामाजिक अशांति की घटनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से दबाने में मदद कर सकती है।

चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.2 प्रतिशत बढ़ी थी, जो बीजिंग की तरफ से निर्धारित किए गए आधिकारिक लक्ष्य से थोड़ा बेहतर है। लेकिन देश को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रिकॉर्ड स्तर पर रिएल एस्टेट सेक्टर में गिरावट, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अपस्फीति का दबाव, बढ़ती कॉर्पोरेट चूक और स्थानीय सरकारों पर बढ़ता वित्तीय तनाव शामिल है। जैसे-जैसे चीन में निराशा बढ़ती जा रही है, विरोध-प्रदर्शन फैलता जा रहा है। श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखने वाले हांगकांग स्थित गैर-लाभकारी संगठन, चाइना लेबर बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में श्रमिक हड़तालों और प्रदर्शनों की संख्या बढ़कर 1,794 हो गई, जो 2022 से दोगुनी से भी ज्यादा है। जबकि, ठीक एक साल पहले, दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल फोन बनाने वाली फैक्ट्री चीनी शहर झेंग्झौ में आईफोन फैक्ट्री में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी, क्योंकि महामारी के बाद श्रमिकों को वापस आकर्षित करने के लिए वेतन और लाभ बढ़ाने के वादे से मुकरने के बाद, फॉक्सकॉन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था।

चीन में 1970 के दशक में कंपनियों ने प्राइवेट आर्मी यानि अपनी मिलिशिया रखी थी और ये स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम करती थीं, जिसका मकसद लोगों के किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने से लेकर मजदूरों को नियंत्रित रखना होता था। ये वो दौर था, जब चीन काफी अशांत स्थिति से गुजर रहा था। इनमें से अधिकांश स्थानों पर ये इकाइयां आज भी मौजूद हैं, लेकिन इनका पैमाना काफी कम हो गया था, जबकि एक बार फिर इसमें विस्तार शुरू हो गया है। अब तक जिन कंपनियों ने भी अपनी प्राइवेट आर्मी की घोषणा की है, उनमें से ज्यादातर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (एसओई) हैं, जिनका सीधे स्वामित्व केंद्र या क्षेत्रीय सरकारों के पास है। लेकिन दिसंबर में, दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक, यिली ग्रुप, जो हाल के इतिहास में पहली प्रमुख प्राइवेट चीनी कंपनी बन गई, जिसने अपनी पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेज डिपार्टमेंट यूनिट की स्थापना की है। यिली चीन की सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, लेकिन जिस होहोट में ये कंपनी स्थित है, उस प्रदेश सरकार की इस कंपनी में करीब साढ़े 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हालांकि, अभी तक पता नहीं चल पाया है, कि इस प्राइवेट आर्मी में कितने सैनिक हैं, लेकिन चीन के सैन्य सेवा कानून के अनुसार, पुरुष मिलिशिया सदस्यों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। विशेष कौशल वाले लोगों के लिए कुछ लचीलापन है। महिलाएं भी शामिल होने के लिए पात्र हैं, हालांकि कानून में उम्र की आवश्यकताएं प्रदान नहीं की गई हैं।

● **कुमार विनोद**

चीन में प्राइवेट आर्मी का इतिहास

चीन के पास अपनी कोई सेना नहीं है, बल्कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। चीन की मिलिशिया 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना से पहले की है। उनकी उत्पति 1920 के दशक में हुई थी और उन्होंने कई लड़ाइयों में कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया था। 1949 के बाद, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमि चीन पर कब्जा कर लिया, तो प्राइवेट आर्मी प्रांतीय सरकारों, स्कूलों और कंपनियों में शामिल हो गईं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, 1949 से 1976 तक माओवादी युग के दौरान सेनाएं चीन में काफी प्रचलित थीं और 1950 के दशक के अंत में 22 करोड़ सदस्यों के साथ पीएलए सदस्यों की संख्या अपने चरम पर थीं, जब ताइवान को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य तनाव बहुत ज्यादा था। मिलिशिया चीन की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दो पूर्णकालिक पेशेवर बलों से बना है- पीएलए और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस, जिसे आंतरिक सुरक्षा का काम सौंपा गया है। देश के रक्षा कानून के अनुसार, मिलिशिया पीएलए के लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं। इस ब्रिगेड में बड़ी संख्या में नागरिकों को शामिल करके, चीन के क्रांतिकारी नेता माओ जेडॉन्ग ने कहा था, कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी शाही ताकतों के खतरे के खिलाफ देश की रक्षा को बढ़ा रहे थे।

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

श्री रामचरितमानस में समन्वयवाद

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस केवल भक्तिमार्ग के साधकों का भाव ही पुष्ट नहीं करती, वरन उनका अध्यात्मिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। एक सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के विभिन्न अंगों के लिए आदर्श स्थापित किया है।

एक सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए ग्रंथ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस पर जितनी भी चर्चा, आलोचना-समालोचना और समीक्षा हुई है उतनी शायद ही किसी अन्य लिपिबद्ध ग्रंथ की हुई होगी, और हो भी क्यों न? ऐसा और कौन सा ग्रंथ है, जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न अंगों को इतने मर्मस्पर्शी एवं स्पष्ट ढंग से छुआ हो, चाहे वह परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंधों की गरिमा-मर्यादा हो, समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी संबंधों की मर्यादा हो अथवा राजकीय कामकाज व राजा के कर्तव्यों की।

श्रीरामचरितमानस में निरूपित जीवन-व्यवस्था एक **आदर्श समाज** एवं आदर्श राज्य की कोरी कल्पना मात्र न होकर पूर्णत: अनुभवगम्य और व्यावहारिक है। इस ग्रंथ के माध्यम से गोस्वामी जी ने परस्पर स्नेह-सम्मान के साथ कर्त्तव्य-परायणता के माध्यम से न केवल जीवन को समृद्ध-सुखी बनाने में असंख्य-अप्रतिम योगदान दिया है वरन मानस के पात्रों के माध्यम से ढेरों सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में अभूतपूर्व कार्य किया है।

आज के संदर्भ में हमारे समक्ष विद्यमान विशालतम चुनौतियों में जो अग्रणी हैं उनमें सामाजिक व्यवस्था में समरसता का उत्तरोत्तर ह्रास प्रमुख है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि इक्कीसवीं सदी के उन्नीस वर्ष और भारतीय संविधान लागू होने के उनहत्तर वर्ष बाद भी वर्ण-व्यवस्था और रूढ़ियों के कुचक्र को भेदने में सफल होने की अपेक्षा हम उसमें और उलझते जा रहे हैं और अपने वर्तमान को संभालने के संकट से जूझ रहे हैं।

सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए रामचरित मानस ने जो योगदान कई सौ वर्ष पूर्व किया था वह आज भी उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक प्रासंगिक तथा आवश्यक है। मानस के रचनाकाल को देखें तो पता चलता है कि उस समय वर्ण-व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय समाज मुख्यत: दो सम्प्रदायों वैष्णव और शैव में विभाजित था। तत्कालीन अन्य वैश्विक धर्मों के मतावलम्बियों में विभाजित समूहों-अनुयायियों की भांति, हिंदू धर्म के अनुयायी भी दो वर्गों में विभक्त थे और अपने पंथ (वैष्णव-शैव) तथा आराध्य (भगवान श्रीराम एवं भगवान शंकर) को एक-दूसरे से उच्चतर समझने की वजह से प्राय: एक-दूसरे से विद्वेष-विद्रोह में अपना समय व ऊर्जा व्यर्थ करते थे जिसके फलस्वरूप हानि अंतत: समाज की होती थी।

साहित्यकार समाज का पारखी होता है, समाज की दिशा-दशा पर दृष्टि रखता है तथा अपनी लेखनी के माध्यम से कुरीतियों का शमन करने और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से तत्कालीन समाज को इस सांप्रदायिक विभाजन के फलस्वरूप होने वाली हानि से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान के दोनों स्वरूपों (भगवान शंकर एवं भगवान श्रीराम) को एक-दूसरे का उपासक बताकर, एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाकर उनके अवलम्बियों-उपासकों के परस्पर द्वंद को निर्मूल कर दिया। बालकांड में वर्णित प्रयागराज के मुनि-समागम में ऋषि भारद्वाज अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ अपने संवाद में भगवान शंकर को भगवान श्रीराम का उपासक बताते हुए कहते हैं कि हर कोई अविनाशी भोलेनाथ की उपासना करता है, वहीं स्वयं भगवान शंकर श्री राम की महिमा का बखान करते हैं-

संतत जपत संभु अविनासी,
सिव भगवान ज्ञान गुन रासी।
सोपि राम महिमा मुनिराया,
सिव उपदेश कीन्ह करि दाया।

इसके पश्चात् -

तथा जासु कथा कुम्भज ऋषि गाई सोइ मम इष्ट देव रघुबीरा...के माध्यम से बार-बार शंकर का राम के प्रति सम्मान दिखाना निश्चित ही शैवों के मन से वैष्णवों के प्रति विद्वेष **भाव समाप्त करने** और दोनों सम्प्रदायों के बीच की खाई को भरने और उनमें परस्पर सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया अत्यावश्यक, सार्थक, सफल प्रयास था।

यही नहीं बालकांड में माता पार्वती को श्रीराम जन्म-प्रसंग की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर जन्मोत्सव का आनंद देखने के लिए कागभुशुण्डि के साथ मनुष्य रूप में चोरी से अपने अयोध्या विचरण तथा बाल-लीला देखने की चर्चा करते हैं, जिससे उनके मन में भगवान राम के प्रति आदर परिलक्षित होता है।

यथा -

औरउ एक कहउँ निज चोरी,
सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी।
कागभुशुण्डि संग हम दोऊ,
मनुज रूप जानइ नहि कोऊ।
परमानन्द प्रेम सुख फूले,
वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले।

विचित्रता यह कि ये प्रेम-सम्मान एकांगी नहीं बल्कि विशुद्ध द्विपक्षी है। इसकी एक अति मनोहारी झलक पुष्प वाटिका में मिलती है जब सीताजी शंकर-प्रिया भवानी से अपने लिए एक सुयोग्य वर की प्रार्थना करती हैं-

गयीं भवानी भवन बहोरी,
बंदि चरन बोली कर जोरी।
जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद चकोरी।

और धनुष यज्ञ के समय जब पिनाक-भंजन हेतु श्रीराम की सुकुमार काया और शिव-धनुष की विशालता का अनुमान लगाकर मन में किंचित चिंतित-विचलित होती हैं और मां भवानी और भगवान भोलेनाथ को याद करती हैं-

मन ही मन मनाव अकुलानी,
होहु प्रसन्न महेस भवानी।
करहु सफल आपनि सेवकाई,
करि हितु हरहु चाप गरुआई।

● **ओम**

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

नॉक आउट के दबाव से कब उभरेगा भारत?

भारत की क्रिकेट टीमों का आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबले में हार का सिलसिला जारी है। पिछले साल के अंत में लगातार दस जीत दर्ज करने वाली रोहित शर्मा की कप्तानी वाली सीनियर टीम को ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्डकप के खिताबी मुकाबले में हराया था। अब ऑस्ट्रेलिया ने ही अंडर 19 वर्ल्डकप फाइनल में टीम इंडिया का छठी बार विश्व विजेता बनने का सपना तोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नॉकआउट मुकाबले में ही क्यों हार जाता है भारत? इस हार का जिम्मेदार कौन है? इन खामियों से कब सबक लेंगे कोच और चयनकर्ता? क्या फाइनल के दबाव को झेल नहीं पा रहा भारत? खिताबी मुकाबले के दबाव से कब उभरेगा भारत?

खेल विशेषज्ञों और आलोचकों का कहना है कि नॉकआउट मुकाबले में बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी तीनों में बेहतर प्रदर्शन आवश्यक है जो भारतीय टीम में नहीं दिखा। दूसरा टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना। मुशीर खान, सचिन दास और कप्तान उदय सहारन से फाइनल मुकाबले में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन तीनों ने ही निराश किया। मुशीर 22, उदय 8 और सचिन सिर्फ 9 रन बना सके। हालांकि मुशीर और उदय इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-2 में रहे। उदय ने 56.71 के एवरेज से सर्वाधिक 397 रन बनाए, लेकिन फाइनल मुकाबले में मुशीर को छोड़कर ये धुरंधर दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। तीसरा भारतीय पारी में कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई, जो हार की बड़ी वजहों में से एक रही। सबसे बड़ी साझेदारी 46 रनों की थी, जो नौवें विकेट के लिए मुरुगन अभिषेक और नमन तिवारी के बीच हुई। मगर तब तक भारत के हाथ से मैच लगभग निकल चुका था। यदि भारत की ओर से कोई बड़ी साझेदारी होती तो मैच का निर्णय कुछ और ही होता। चौथा कप्तान उदय सहारन ने स्पिन गेंदबाजों के तौर पर मुरुगन अभिषेक, मुशीर खान, सोमी पांडे और प्रियांशु मोलिया को लगाया था। मगर ये चारों ही गेंदबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। चारों स्पिन गेंदबाजों ने मिलकर 141 रन दिए, लेकिन दो ही विकेट ले सके। यदि ये गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करते तो मैच का नतीजा भारत के पक्ष में आने की उम्मीदें काफी ज्यादा हो सकती थी। फाइनल मुकाबले में ज्यादातर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं। भारतीय कप्तान फाइनल मैच में टॉस नहीं जीत पाए। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीत पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्कोर बनाया, जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही प्रेशर रहा।

अंडर-19 वर्ल्डकप के हर मुकाबले में जब-जब भारतीय टीम मुश्किल में नजर आई कप्तान उदय सहारन ने टीम को संभाला था। फाइनल में उदय को कुछ इसी तरह की परिस्थितियां मिली थी। भारत के पहले दो विकेट महज 40 रन पर गिर चुके थे। यहां से भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी एक बार फिर कप्तान उदय के कंधों पर आ गई। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से भारत को संभालने वाले उदय फाइनल मुकाबले में ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। फाइनल में कप्तान सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने से भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट उदय सहारन का आउट होना रहा। भारतीय टीम फाइनल का दबाव नहीं झेल सकी और एक तरह से उसने सरेंडर कर दिया। पूरे मुकाबले में भारत का कोई भी बल्लेबाज अपना कमाल नहीं दिखा पाया। भारत की गेंदबाजी भी आखिरी कुछ ओवर्स में पटरी से उतरी नजर आई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक समय छह विकेट पर 187 रन था, इसके बावजूद वह 250 से ज्यादा रन बनाने में सफल रही। इससे साफ नजर आया कि वर्ल्डकप फाइनल जैसे बड़े मुकाबले का दबाव भारतीय टीम झेल नहीं पाई।

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक साल के भीतर तीसरी बार टीम इंडिया का चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया है। बीते 11 फरवरी को खेले गए अंडर-19 वर्ल्डकप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को 79 रन के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जीत के लिए 254 रन के लक्ष्य को उदय की कप्तानी वाली भारतीय टीम हासिल नहीं कर सकी। भारतीय टीम महज 43.5 ओवर में 174 रन पर ढेर हो गई। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर-19 विश्वकप का किताब अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्वकप के फाइनल में मात दी थी। ऐसे में भारतीय टीम के विश्व चैंपियन बनने की राह में ऑस्ट्रेलिया रोड़ा बन गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें पिछली बार फाइनल में 6 साल पहले साल 2018 में न्यूजीलैंड में आयोजित विश्वकप के फाइनल में भिड़ी थी जिसमें पृथ्वी शॉ की कप्तानी वाली टीम इंडिया बाजी मारने में सफल हुई थी। भारतीय टीम का अंडर-19 विश्वकप में शानदार प्रदर्शन रहा है। टीम इंडिया रिकॉर्ड नौवीं और लगातार पांचवीं बार फाइनल में पहुंची। पिछले चार में से दो खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं। पिछली बार यश ढुल की कप्तानी में भारतीय टीम पांचवीं बार चैंपियन बनी थी। इस बार 2024 अंडर-19 वर्ल्डकप में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने वर्ल्डकप अभियान का आगाज किया था। भारत ने बांग्लादेश के अलावा आयरलैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल और साउथ अफ्रीका को हराया। इस तरह टीम इंडिया ने लगातार 6 मैच जीते, लेकिन फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।

● **आशीष नेमा**

पाक्षिक पत्रिका अक्स के स्वामित्व एवं अन्य विषयों संबंधित विवरण

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन	:	भोपाल
प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
मुद्रक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रकाशक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
संपादक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा	:	राजेन्द्र आगाल 150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल

जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं राजेन्द्र आगाल एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 01.03.2024 **राजेन्द्र आगाल**

हस्ताक्षर

चिट्ठी आई है गाने के लिए शुरुआत में राजी नहीं थे पंकज उधास, फिर...

जिस फिल्मी गीत चिट्ठी आई है ने रातोंरात गजल गायक पंकज उधास को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया। दरअसल वह शुरू में इस गाने को गाने के लिए तैयार ही नहीं थे और इसके लिए उन्हें राजी करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी।

यह खुलासा मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट ने किया। यह गाना महेश भट्ट की ही फिल्म नाम का है। चिट्ठी आई है गीत से पंकज उधास को प्रसिद्धि मिली और 1986 की फिल्म नाम के इस गीत के जरिए उनकी खास पहचान बनी। पंकज उधास का 72 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 26 फरवरी को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। फिल्ममेकर महेश भट्ट ने कहा कि पंकज उधास का नाम स्क्रीनप्ले राइटर सलीम खान ने सुझाया था। फिल्मकार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे गीत के लिए गजल गायक को मनाने में सफल हुए और आखिरकार यह गीत फिल्म की जान बन गया। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि मैं और सरोज खान, हम लंबे समय तक शूटिंग किया करते थे, तो पंकज उन कलाकारों में शामिल नहीं थे जो टुकड़ों में शूटिंग करते थे।

पंकज उधास को गाने के लिए मनाया... *फिल्म में पंकज उधास खुद एक समारोह में चिट्ठी आई है गीत गाते हुए दिखाई देते हैं। यह गीत आनंद बक्शी ने लिखा था और संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया था। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया, पंकज उधास एक गायक थे और उन्होंने सामने बैठे दर्शकों के लिए गाना गाया था। इसको लेकर वह शुरू में तैयार नहीं थे। वह इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या वह इसे ठीक से कर पाएंगे या नहीं। हम उनकी जगह किसी और को नहीं दिखाना चाहते थे। मैंने उनसे बस इतना कहा (सोचिए) कि आप सिंगापुर या लंदन में अपना कोई शो कर रहे हैं और मंच पर गाना गा रहे हैं। यही एकमात्र तरीका था, जिससे हम गाना शूट कर पाएंगे।*

अंदाज अपना-अपना के सेट पर इसलिए लड़ते थे सलमान खान और आमिर

फिल्म अंदाज अपना-अपना को रिलीज हुए 30 साल हो चुके हैं। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म में सलमान खान और आमिर खान की कॉमेडी ने हंसा-हंसाकर सबके पेट में दर्द कर दिया था। लेकिन फिल्मी पर्दे पर जो कॉमिक टाइमिंग और बॉन्ड नजर आता था, वह पर्दे के पीछे नहीं था। सेट पर सलमान और आमिर का झगड़ा भी होता था।

फिल्म के अहम भूमिका में रहे एक्टर शहजाद खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि आमिर और सलमान का अपने काम के प्रति अलग-अलग नजरिया था और यही उनके बीच तनाव का कारण बना। उन्होंने बताया, आमिर सुबह 7-7.30 बजे मड आइलैंड बंगले पर पहुंचते थे, जबकि कॉल टाइम सुबह 9 बजे होता था। सलमान बेचारे 10-11 बजे तक आ ही जाते थे। शहजाद ने दोस्त सलमान के लेट आने का बचाव करते हुए आगे कहा, हम सभी जानते हैं कि बांद्रा से आना कितना मुश्किल है। कभी गाड़ी खराब, कभी कुछ खराब...। वैसे अंदाज अपना-अपना की शूटिंग के दौरान आमिर भी बांद्रा में ही रहते थे। शहजाद खान ने यह भी बताया कि सलमान और आमिर सेट पर कभी एक-दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते थे।

बड़े मियां छोटे मियां के सेट पर अमिताभ को 7 घंटे इंतजार करवाते थे गोविंदा

गोविंदा के सेट पर लेट-लतीफी के किस्से कई कलाकारों ने सुनाए हैं। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का भी है। एक एक्टर ने खुलासा किया है कि गोविंदा सेट पर अमिताभ को छह घंटे इंतजार करवाते थे। वह सेट पर देरी से पहुंचते थे।

एक इंटरव्यू में उक्त अभिनेता ने बताया कि अमिताभ बच्चन वक्त के पाबंद थे और सेट पर सुबह 9 बजे पहुंच जाते थे। लेकिन गोविंदा शाम के 4 बजे तक सेट पर आते थे। लेकिन डायरेक्टर डेविड धवन स्मार्ट तरीके से अमिताभ को बिजी रखते थे, ताकि वह गोविंदा और उनके लेट आने के बारे में न सोचें। बच्चन साहब सुबह 9 बजे आते थे और गोविंदा साहब दोपहर 3-4 बजे आते थे। यह आईएसटी और जीएसटी के बीच अंतर जैसा था। डेविड जी बहुत होशियार थे। वह जानते थे कि एक्टर (अमिताभ बच्चन) को कैसे बिजी रखना है कि वह (गोविंदा के देर से आने) के बारे में सोच भी न पाएं। वहीं, डायरेक्टर रवि दीवान ने एक बार बताया था कि फिल्म हम की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि रजनीकांत को भी पांच दिन इंतजार करवाया था।

सरकार की सामूहिक विवाह योजना में गजब का फर्जीवाड़ा हो गया था, शासकीय योजना के तहत सामूहिक विवाह में जो प्रोत्साहन राशि का प्रावधान था, उसमें ही गफलत थी जिसकी पड़ताल होनी थी। फर्जीवाड़े को दबाने की कोशिश में देरी हो चुकी थी तब तक पहले से शादीशुदा आठ जोड़ों की सरकारी सामूहिक विवाह योजना में दोबारा शादी भी हो चुकी थी।

लिफाफे वाली शादी...

उस सरकारी अधिकारी समेत 9 लोगों पर भी मुकदमे की तैयारी चल रही थी। मामला गंभीर होने के साथ, सरकारी विभाग का था। इसमें समाज कल्याण विभाग के बड़े अफसर भी लपेटे में आ रहे थे। और तो और सात-आठ लाभार्थियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। जो शादीशुदा होने के बाद भी दूल्हे के गेटअप में सेहरा से चेहरा ढके हुए थे, और पीली धोती पहने चुपचाप सरकारी मंडप में बैठे हुए थे। सभी को विभाग ने ही खोजा था। उनको सरकारी मंडप में ही रंगे हाथो पकड़ लिया गया था। षड्यंत्र तब और पुख्ता हो गया जब पकड़े गए फर्जी दूल्हे के पैर भी रंगे हुए मिले। मतलब वे रंगे हाथों क्या, रंगे पैरों भी पकड़े गए थे। मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को दी जा रही थी।

दूल्हा-दुल्हन के फर्जी शादी में समाज कल्याण विभाग के बड़े अफसर की भूमिका भी संदिग्ध थी। वे अपने केबिन में कभी-कभार ही दिखाई देते थे। बड़े अफसर थे, इसीलिए ज्यादातर दौरे में रहते थे। जब फाइलों का ढेर लग जाता, तब दफ्तर के बड़े बाबू उनको फोन कर इत्तिला कर देते थे तब वे दफ्तर आकर दस्तखत करते और फिर दौरे में चले जाते। धीरे-धीरे विभाग का फर्जी दूल्हा-दुल्हन और सामूहिक विवाह के प्रोत्साहन राशि में घपले से संबंधित धोखाधड़ी का मामला उजागर हो ही गया था। अब तेजी से वायरल भी हो रहा था। विभाग की सामूहिक विवाह योजना की फाइल सामने थी।

दरअसल सरकार की सामूहिक विवाह योजना में गजब का फर्जीवाड़ा हो गया था, शासकीय योजना के तहत सामूहिक विवाह में जो प्रोत्साहन राशि का प्रावधान था, उसमें ही गफलत थी जिसकी पड़ताल होनी थी। फर्जीवाड़े को दबाने की कोशिश में देरी हो चुकी थी तब तक पहले से शादीशुदा आठ जोड़ों का सरकारी सामूहिक विवाह योजना में दोबारा शादी भी हो चुकी थी। सबको यह कहकर लाया गया था कि बस दो घंटे के लिए दूल्हा बनो, दो हजार मिलेंगे। पूछताछ के दौरान बैठा हुआ गिरधारी, बार-बार कह रहा था- हमको पैसे देने में देरी कर रहे हैं। अभी-अभी कल्लू उठकर गया है साब, उसे लिफाफे में दो हजार दिए गए हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित किसी ने शादीशुदा बबलू को पहचान लिया था। यह तो बनवारी का लड़का है, बंशीपुर में इसकी ससुराल है। शादीशुदा है। वह बड़े बाबू के कहने पर आया था, इसके पहले के बड़े बाबू उससे गुपचुप लेनदेन करते देते भेद खुल गया। वह पकड़ा गया। बाकी उन कन्याओं से भी पूछताछ होनी थी जो दुल्हन बनी थी। ग्यारह में से आठ फर्जी दूल्हे पाए गए। पूरा समाज कल्याण विभाग लपेटे में आ रहा था। इनकी प्रोत्साहन राशि कहां गई? सरकार के सामूहिक विवाह योजना संपन्न होने के बाद कुछ फर्जी वधू शादी में पहनी गई अपनी लाल साड़ी और चूड़ियां उतारकर बड़े बाबू को पकड़ा रही थी। दूल्हे का सेहरा और सभी पीली धोतियां, बड़े साहब के केबिन में छुपा दी गई थी। पकड़े गए तथाकथित दूल्हा-दुल्हन से लगातार पूछताछ हो रही थी। फर्जी वधू बनाकर सरकार से अवैध रूप से प्रोत्साहन राशि लेने वालों में रमिता देवी का नाम सामने आ रहा था। उसको अभी पैसे लेने थे इसलिए वह बैठी रह गई।

विभाग के कार्यक्रम प्रभारी ने उसे बुलाया था। कुछ फर्जी दूल्हे फाइल में रखे हुए एक कागज पर हस्ताक्षर कर पहले ही खिसक चुके थे। जिसको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली थी वह बैठे रह गए और पकड़े गए। चेहरे में सेहरा लगाए फर्जी दूल्हे बार-बार बोल रहे थे- हमको कहा गया केवल दूल्हा बनना है, दो घंटे का दो हजार मिलेगा, सो हम आ गए। पकड़ा गया एक फर्जी दूल्हा बार-बार बोल रहा था- साब मैं तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम देखने आया था। वहां उसे बड़े बाबू ने कहा था कि- दूल्हा बनकर बैठ जाओ तुम्हारी फोकट की कमाई हो जाएगी, नाश्ता कराएंगे। इसी कारण वह शादी के पटे में बैठ गया था।

तब तक कुछ जागरूक नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, एवं पत्रकार भी पंडाल में पहुंच चुके थे। उसमें से एक ने पूछा- बड़े बाबू ने क्या बोला यह बताओ?

सच बतलाएं साहब। हमें बड़े बाबू ने कहा था- बस माला पहनाकर कर, सेहरा और टोपी के साथ तुम्हारी फोटो खींचेंगे, चाहे तो काजल भी आंखों में लगा लेना फिर लिफाफा लेकर घर चले जाना।

सरकारी सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े की, ऊपर तक कंप्लेन गई। जांच के लिए समिति बनाने का निर्देश दिया गया। समिति ने जांच में पाया गया कि पास के ही गांव की अर्चना की शादी तो पिछले साल जून में बबलू के साथ हो चुकी है। कलावती और मुनिया देवी की भी शादी मार्च में हो चुकी है। मानमती की शादी पिछले साल, जवाहिर के साथ उसके गांव लालपुर में हो चुकी है। कल्याणी, राधा की शादी भी तो एक वर्ष पहले हो चुकी है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। इस षड्यंत्र में विभाग के बड़े बाबू से ज्यादा दोषी बड़े अफसर निकले। पूरे प्रकरण के साक्ष्य एवं दस्तावेज तैयार हो चुके थे, उच्च कार्यालय में भेजने के लिए नोटशीट लिखा जा चुका था। ठीक उसी दिन समाज कल्याण विभाग के वो बड़े अफसर लंबी छुट्टी में चले गए।

● **सतीश उपाध्याय**

Mahesh Patidar
Builder & Promoter

We Build Your
DREAM HOUSE

पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

इस सँकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है

कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की बृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है